चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

पृष्ठ 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

06 अप्रैल –12 अप्रैल 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

फोटो– सुनील मल्होत्रा

यही न्याय है तो अन्याय क्या है

संतोष भारतीय

22 मई, 1987 की रात भारतीय मानवता के इतिहास की सबसे काली रातों में से एक है. यह रात व्यवस्था के विद्रूप चेहरे को भी दिखाती है, लेकिन व्यवस्था में शामिल कुछ लोगों के प्रति आशा भी पैदा करती है. भारतीय व्यवस्था से जुड़े कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले एक अंग पीएसी ने सोची–समझी योजना के तहत हाशिमपुरा और मलियाना से लोगों को उठाया, उन्हें गाज़ियाबाद के पास गंगनहर के किनारे लेकर आए, लाइन में खड़ा किया, गोली मारी और लाशें बहा दी. मुझे अच्छी तरह याद है, यही हेडिंग चौथी दुनिया के उस अंक की थी, जिसमें हमने सबसे पहले दुनिया के सामने यह कहानी रखी थी. उस समय इस कहानी को कोई भी छापने के लिए तैयार नहीं था और छापता भी कैसे? उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सर्वशक्तिमान माननीय वीर बहादुर सिंह थे और भारत के प्रधानमंत्री सर्वशक्तिमान राजीव गांधी थे. हमने जब इस रिपोर्ट का खुलासा करने का फैसला किया, तब हमें मालूम था कि हम भारत की व्यवस्था के उस हिस्से से टकरा रहे हैं, जिसके मन में लोकतंत्र के प्रति कोई सम्मान नहीं है. तत्कालीन मुख्यमंत्री ने दो बार बाज़ार से चौथी दुनिया के सारे अंक उठवा लिए थे. हमें संदेश भिजवाया, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूंगा कि आज की तरह के निर्मम राजनेता उस समय नहीं थे. जब मैंने वीर बहादुर सिंह जी से कहा कि आप कॉपियां उठवाते रहिए, हम कॉपियां छापते रहेंगे, तो वीर बहादुर सिंह हलके से हंसे और फ़ोन काट दिया.

22 मई 1987 की रात पीएसी की फायरिंग से जिंदा बचे हाशिमपुरा के लोग.

21 मार्च, 2015 को इस केस का फैसला आया. इस केस के फैसले ने हमें बताया कि हमारी न्याय व्यवस्था भी असंवेदनशील है. न्याय व्यवस्था ने उन सारे लोगों को छोड़ दिया, जिन पर इस कत्लेआम को अंजाम देने का आरोप था. न्यायालय ने उन लोगों को संदेह का लाभ (बेनिफिट ऑफ डाउट) दिया, पर यह कमेंट नहीं किया कि आखिर इस हत्याकांड का कोई ज़िम्मेदार है या पीएसी की बंदूकें अपने आप गरजीं, अपने आप लोग मर गए, अपने आप उनकी लाशें बह गईं और जो जिन्दा बच गए, वो जो कह रहे हैं, बकवास है, झूठ है. इस सम्पूर्ण घटनाक्रम का सबसे विद्रूप चेहरा हमारा मीडिया है. जेसिका लाल की हत्या को लेकर अदालत द्वारा उसके ऊपर कोई ध्यान न देने के खिलाफ हजारों हज़ार लोग मोमबत्तियों का जुलूस लेकर निकलते रहे. अख़बारों में लेख छापे जाते रहे और टेलीविज़न के ऊपर बहसें होती रहीं, लेकिन गरीब मुसलमानों के इस कत्लेआम को लेकर न टेलीविज़न पर बहसें हुईं, न अख़बारों में लेख लिखे गए. अब जबकि तीसहजारी की अदालत ने उन लोगों की हत्या के आरोपियों को छोड़ दिया है, तब न एक टेलीविज़न चैनल में बहस हुई, न ही एक मोमबती का जुलूस निकला.

शायद हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी संवेदनाएं बंट गईं हैं. गरीब मरता है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उच्च वर्ग के मनोरंजन के काम में लगे हुए लोगों में से अगर किसी को बाउंसर धक्का दे देते हैं, तो वह टेलीविज़न चैनल और अख़बारों की चिंता का विषय भी बन जाता है और पूरा समाज, तथाकथित समाज उद्वेलित हो जाता है.

अगर ये न्याय है, तो अन्याय क्या है? इसका जवाब न सुप्रीम कोर्ट देगा और न ही माननीय प्रधानमंत्री देंगे. इसका जवाब मीडिया भी नहीं देगा, लेकिन ऐसी घटनाएं एक बड़े वर्ग में ये सन्देश देती हैं कि इस देश में न समाज, न सरकार और न ही न्याय व्यवस्था, उन लोगों के पक्ष में है, जो वंचित हैं और जो इस देश के 85 प्रतिशत लोगों का एक बड़ा हिस्सा है. जब मैं 85 प्रतिशत कहता हूं, तो मैं उन लोगों की बात करता हूं, जो वोट डालते हैं और जो सरकार बनाते हैं. सरकार बन जाने के बाद उन 85 प्रतिशत लोगों का रोल समाप्त हो जाता है. जो उनका वोट लेते हैं, चाहे वो राजनीतिक दलों के लोग हों या राजनीतिक दलों के पक्ष में ले जाने वाले इन वर्गों के नेता हों, वो फिर उन्हें धोखा ही देते हैं.

सवाल मुस्लिम संगठनों का भी है. मुसलमानों के नेता, मुसलमानों के संगठन सामाजिक हों या राजनीतिक हों, इनमें से किसी को इस बात की चिंता नहीं हुई कि हाशिमपुरा हत्याकांड मुस्लिम समाज की चिंता का केंद्रबिन्दु बने. उनके लिए गरीब मुसलमानों की ज़िन्दगी विदेशों में भाषण देने का विषय तो बन जाती है, पर देश में परेशानी का कारण नहीं बनती. न जाने कितने लोगों ने हाशिमपुरा और मलियाना के लोगों की हत्या के बाद विदेशों से सहायताएं जुटाई होंगी, पर वो सहायता हाशिमपुरा और मलियाना के लोगों तक नहीं पहुचीं. वे दिल्ली तीस हजारी कोर्ट तक आते थे, दिन भर बैठते थे और लौट जाते थे. जज साहब कहते थे, एफआईआर की कॉपी लाओ. गरीब मुसलमान, जो थाने से डरता है, वह एफआईआर की कॉपी कहां से लेकर आए, जबकि उसके मुकाबले इस व्यवस्था का सबसे सशक्त क्रूर अंग पीएसी गुस्से से आंखें तरेरती हुई हर जगह खड़ी दिखाई देती थी.

हाशिमपुरा के लोगों का दर्द देश के 16, 18 या 20 प्रतिशत लोगों का दर्द है, लेकिन उस दर्द को पूरा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की सरकार और हिन्दुस्तान की न्याय व्यवस्था अगर नहीं समझेगी, तो हमें यह मान लेना चाहिए कि कल गरीब और वंचितों के दूसरे तबके, जिनमें दलित हैं, पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके ऊपर भी अन्याय होगा, तो कोई उनकी तरफ देखने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की व्यवस्था के सारे अंग उनके पक्ष में खड़े हैं, जिनके पास दौलत भी है और राजनीतिक ताकत भी है.

यह केस अफसोसनाक है और न्याय व्यवस्था के चेहरे के ऊपर एक तमाचा भी है. एक छोटी सी आशा भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है. देखते हैं कि वो अपनी नींद से जागता है या नहीं जागता है और एक सवाल मुस्लिम समाज के रहनुमा बनने वाले लोगों से भी है कि वो अपने इस दर्द की अभिव्यक्ति सशक्त ढंग से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं.

गाज़ियाबाद के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वी.एन. राय मुझे याद आते हैं, जो इस घटना को लेकर चौथी दुनिया के दफ्तर में आए थे और हमारे एक साथी चंचल ने इन सारे किस्से को वी.एन. राय के साथ बैठकर हमें सुनाया था. इस कहानी को छापने का फैसला लेने में हमें क्षण भर भी नहीं लगा. वी.एन. राय जैसे लोग व्यवस्था में आशा की किरण हैं और मेरा मानना है कि उसी लॉ एन्फोर्समेंट के एक अधिकारी वी.एन. राय ने अपनी ही लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसी पीएसी द्वारा की हुई उस बर्बर हत्या की साजिश को या उस साजिश को अंजाम देने वाली घटना के बारे में हमें बताया और उसे दुनिया के सामने लाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा किया. ■

editor@chauthiduniya.com

> सवाल मुस्लिम संगठनों का भी है. मुसलमानों के नेता, मुसलमानों के संगठन सामाजिक हों या राजनीतिक हों, इनमें से किसी को इस बात की चिंता नहीं हुई कि हाशिमपुरा हत्याकांड मुस्लिम समाज की चिंता का केंद्रबिन्दु बने. उनके लिए गरीब मुसलमानों की ज़िन्दगी विदेशों में भाषण देने का विषय तो बन जाती है, पर देश में परेशानी का कारण नहीं बनती. न जाने कितने लोगों ने हाशिमपुरा और मलियाना के लोगों की हत्या के बाद विदेशों से सहायताएं जुटाई होंगी, पर वो सहायता हाशिमपुरा और मलियाना के लोगों तक नहीं पहुचीं.

मुलायम, नीतीश और लालू की नई पार्टी

समाजवादी पार्टी चीफ मुलायम सिंह यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एकजुट होकर एक नई पार्टी का गठन करने का फैसला किया है. नई पार्टी बनाने का निर्णय 26 मार्च को दिल्ली में मुलायम सिंह यादव के निवास पर हुई एक गुप्त बैठक में लिया गया. जिसमें मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार और लालू यादव मौजूद थे. इस बैठक में फैसला हुआ कि मई से पहले जनता परिवार के सारे दलों को विलय हो जाएगा और एक नई पार्टी बनाई जाएगी. इस नवगठित पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव होंगे. वह अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, कमल मोरारका, एच डी देवेगौड़ा, शरद यादव और लालू यादव से बातचीत कर पार्टी के पदाधिकारियों के नामों का फैसला करेंगे. इस बैठक में यह भी तय हुआ कि अप्रैल महीने के पहले पखवाड़े में मुलायम सिंह के घर पर सभी छह दलों की फाइनल मीटिंग होगी. जिसके बाद इन सभी दलों के विलय, नई पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह की घोषणा की जाएगी. जनता पारिवार में विलय होने वाली छह पार्टियां समाजवादी पार्टी, जनता दल(युनाइटेड), राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल(सेकुलर), राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी जनता पार्टी हैं.

फैसले के बाद मातम मना रहा है हाशिमपुरा
पेज-03

दरभंगा के बाबूद्दीन और मुजीबुर्रहमान के हौसले को सलाम
पेज-04

लोहिया जयंती पर मुलायम हुए कठोर
पेज-07

साई की महिमा
पेज-12

हाशिमपुरा हत्याकांड

अदालती फैसला दुर्भाग्यपूर्ण, अप्रत्याशित नहीं

वी एन राय

हाशिमपुरा हत्याकांड के मामले में अदालती फैसला दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है, पर अप्रत्याशित बिल्कुल नहीं. यदि आप ध्यानपूर्वक उत्तर प्रदेश सी.आई.डी. की केस डायरियां पढ़ें, तो आप मेरी बातों से सहमत होंगे कि जो मामला पी.ए.सी. कर्मियों के खिलाफ बनाया गया था, उसमें किसी भी अदालत के लिए उन्हें सज़ा देना आसान नहीं था. मैं इस मामले में शुरू से ही जुड़ा था, इसलिए मैं इतना कह सकता हूं कि तफ़्तीश करने वाले पहले ही दिन से हत्यारों को बचाने में लगे हुए थे. 22 मई 1987 को जब पी.ए.सी. मेरठ के हाशिमपुरा मोहल्ले से 42 मुसलमानों को उठाकर गाज़ियाबाद लाई और वहां की दो नहरों के किनारे खड़ा कर उन्हें गोलियों से भून दिया, तब मैं गाज़ियाबाद का पुलिस अधीक्षक था. घटना रात में लगभग 9 बजे घटी थी और मुझे साढ़े दस बजे के आसपास इसकी जानकारी मिली. जब दूसरे अधिकारियों के साथ मैं एक घटना स्थल पर पहुंचा, तो मकनपुर गांव की गंग नहर पर उस अंधेरी रात मैंने जो दृश्य देखा, उसे जीवन भर नहीं भूल सकता. आधी रात दिल्ली–गाजियाबाद सीमा पर मकनपुर गांव से गुजरने वाली नहर की पटरी और किनारे उगे सरकंडों के बीच टॉर्च की कमजोर रोशनी में खून से लथपथ धरती पर मृतकों के बीच किसी जीवित को तलाशना और हर अगला कदम उठाने के पहले यह सुनिश्चित करना कि वह किसी जीवित या मृत शरीर पर न पड़े–सब कुछ मेरे स्मृति पटल पर किसी हॉरर फिल्म की तरह अंकित है. वहां हमें बाबूदीन नामक एक जीवित व्यक्ति मिला, जो इस घटना स्थल पर उस जघन्य हत्याकांड में बचने वाला अकेला शख्स था और जिससे हमें सबसे पहले हाशिमपुरा कांड का पता चला. थोड़ी देर बाद ही मुरादनगर नहर के दूसरे घटनास्थल की जानकारी हुई, जहां पी.ए.सी. का ट्रक पहले ले जाया गया था और कुछ लोगों को वहां मार कर फेंक दिया गया था.

मैंने दोनों घटनास्थलों के सन्दर्भ में एफ.आई.आर. दर्ज़ करने के आदेश दिए, पर कुछ ही घंटों में तफ़्तीशें मुझसे छीन कर सी.आई.डी. को सौंप दी गई. सामान्य परिस्थितियों में तो यह आदेश उचित ही माना जाता, क्योंकि सी.आई.डी. के पास हमसे ज्यादा संसाधन थे और वे बेहतर तफ्तीश कर सकते थे, पर इस मामले में ऐसा नहीं हुआ. शुरू से ही सी.आई.डी. ने अपराधियों को बचाने के प्रयास शुरू कर दिए. उन्होंने बेमन से तफ्तीश शुरू की. उनकी सारी हरकतें दोषियों को बचाने की थी. मैं इस हत्याकांड पर पिछले कुछ वर्षों से एक किताब पर काम कर रहा हूं और इस सिलसिले में जो तथ्य मेरे हाथ लगे हैं, वे चौंकाने वाले हैं. सी.आई.डी. ने जानबूझकर उनकी उपेक्षा की है. ख़ास तौर से उन्होंने इस घटना में फ़ौज की भूमिका को नजरंदाज़ कर दिया और पूरे मामले की सूत्रधार भाजपा की एक नेत्री से कोई पूछताछ नहीं की. मैं विस्तार से अपनी किताब में उनका जिक्र करूंगा.

हाशिमपुरा आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी कस्टोडियल किलिंग की घटना है. 1984 के सिख दंगे या नेल्ली का नरसंहार भी, जिसमें पुलिस की उपस्थिति में लोग मारे गए थे, इस अर्थ में भिन्न हैं कि हाशिमपुरा में न सिर्फ मरने वाले पुलिस की हिरासत में थे, बल्कि उनके हत्यारे भी पुलिस वाले ही थे. इतनी बड़ी संख्या में पुलिस ने पहले कभी भी लोगों को अपनी हिरासत में लेकर नहीं मारा था. भारतीय राज्यों की साख खतरे में है. यदि इतने बर्बर कांड में भी हत्यारे दंडित नहीं किए जा सके, तो एक धर्मनिरपेक्ष समाज होने के उसके सारे दावे धरे रह जाएंगे. जरूरी है कि हाशिमपुरा कांड की नये सिरे से किसी बेहतर एजेंसी से जांच कराई जाए और इस जांच का पर्यवेक्षण हाईकोर्ट करे या फिर हाईकोर्ट तीन रिटायर्ड आई.पी.एस. अफ़सरों की एक टीम इसके लिए नामित करे. बिना नये सिरे से तफ्तीश किए न तो उन असली दोषियों तक पहुंचा जा सकता है, जिन्हें सी.आई.डी. ने आपराधिक लापरवाही के चलते छोड़ दिया था और न ही वर्तमान अभियुक्तों को दंडित कराया जा सकता है. ■

(लेखक इस घटना के वक्त गाजियाबाद के एसएसपी थे.)

feedback@chauthiduniya.com

'ठीक ढंग से निबटने के लिए'

गिरफ्तार लोगों को भेजा गया फतेहगढ़ सेंट्रल जेल

सुरेश त्रिवेदी

मेरठ के हाशिमपुरा–मलियाना दंगे की ऐसी अनकही दर्दनाक दास्तां और भी है, जो न केवल सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है, बल्कि जो मानवता को भी शर्मसार कर देने वाली है. दरअसल, इन दंगों को कुचलने के नाम पर तमाम ऐसे बेगुनाहों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जो या तो महज तमाशबीन थे या फिर जिनके परिवार दंगों की आंच में बुरी तरह झुलस चुके थे. जाहिर है, पुलिस की उस ज़्यादती का शिकार सारे अल्पसंख्यक समुदाय के ही लोग थे. गिरफ्तारी के बाद ऐसे सौ से अधिक लोगों को फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार भेजा गया. दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किए गए उन लोगों में तमाम ऐसे भी थे, जिनकी उम्र सत्तर पार कर चुकी थी. गिरफ्तारी के बाद उन्हें पुलिस और पी.ए.सी. के जवानों ने बुरी तरह पीटा. फिर घायल अवस्था में ही बिना कोई उपचार कराए उन तथाकथित दंगाइयों को पुलिस के ट्रकों में जानवरों की तरह ठूस कर फतेहगढ़ रवाना कर दिया गया.

फतेहगढ़ सेंट्रल जेल देश के सबसे खूंखार अपराधियों को सुधारने के लिए मशहूर है. चम्बल घाटी के तमाम बागी लम्बे समय तक इस जेल में कैद रहे हैं. कहते हैं कि सरकार ने इस जेल का चुनाव मेरठ के कथित दंगाइयों से ठीक ढंग से निबटने के लिए ही किया था. जाहिर है कि सरकार का इरादा उन बेचारे और बेगुनाह लोगों को सबक सिखाने का था. बरहाल, इसी गहरी और सोची–समझी साजिश के तहत दंगों के आरोपियों के जेल में दाखिल होने के पूर्व कैदियों के बीच हाशिमपुर–मलियाना के दंगो के बारे में तरह–तरह की अफवाहें फैलाई गईं. उन्हें दंगों की बावत झूठी कहानियां गढ़कर सुनाई गईं. उन्हें यह समझाया गया कि मेरठ में हुए दंगों में अल्पसंख्यक समुदाय के बलवाइयों ने हिन्दुओं पर जमकर अत्याचार किए हैं. हिन्दुओं की बहू–बेटियों की इज़्ज़त रौंदी गई है. दर्जनों महिलाओं के स्तन काट दिए गए हैं. इससे जेल में सजा काट रहे अपराधियों के बीच न केवल उत्तेजना फैल गई, बल्कि साम्प्रदायिक हिंसा का जुनून भी उनके सिर चढ़ कर बोलने लगा और फिर वही हुआ, जिसका अंदेशा पहले से था. साफ़ है, इस साजिश में जेल प्रशासन की पूरी मिलीभगत थी.

बहरहाल, मेरठ जेल से रातों–रात रवाना किए गए उन बेगुनाहों के फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार में दाखिल होते ही जेल के पुराने सजायाफ्ता कैदी उन पर टूट पड़े. निहत्थे और बेक़सूर लोगों पर जमकर लाठी–डंडे बरसाए गए. उन्मादियों ने घायलों और बूढ़ों तक को नहीं बख्शा. कोई डेढ़–दो घंटे तक जेल के भीतर खुलेआम हिंसा का यह तांडव जारी रहा. कैदियों ने मेरठ के मजलूमों को मार–पीट कर जेल परिसर के भीतर बिछा दिया. लोहे की पत्तियों को पैना करके बनाए गए चाकुओं से उनके शरीर गोद दिए गए. इस दौरान जेल के तमाम सिपाही और अफसर इस खौफनाक मंजर के मूक दर्शक बने रहे. बताते हैं कि सेंट्रल जेल के तत्कालीन वरिष्ठ अधीक्षक एच.पी. यादव इस दौरान अपने बंगले पर बैठे–बैठे हालत का जायज़ा लेते रहे. इसमें कोई शक नहीं कि यह साजिश पूर्व नियोजित थी. वरना, जेल के सजायाफ्ता कैदियों के पास एकाएक इतनी बड़ी तादात में लाठी–डंडे और धारदार हथियार कहां से आ गए?

कैदियों के इस बर्बर हमले में मेरठ से लाए गए अकलियत के पांच लोगों की जेल के भीतर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 70–80 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए. इस घटना के काफी देर बाद जेल की पगली घंटी बजाई गई. वरिष्ठ अधीक्षक यादव समेत पूरा सरकारी अमला जेल में दाखिल हुआ. फ़ोन की घंटियां घनघनाने लगीं. जिला मजिस्ट्रेट बी.एन. गर्ग की रजामंदी से सारे मामले को रफा–दफा करने की कोशिशें शुरू हो गईं. आनन–फानन में जेल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एस. के. मिश्रा की देखरेख में डॉक्टरों की एक टीम ने घायलों का इलाज शुरू किया. गंभीर रूप से घायलों को फ़ौरन जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. कुछ को लखनऊ रेफर कर दिया गया. मरने वालों का जेल के भीतर ही पोस्टमॉर्टम कराकर उनकी लाशों को गुपचुप तरीके से मेरठ रवाना कर दिया गया. दलील यह दी गई कि ये दंगों में बुरी तरह घायल हो गए थे और इन्हें नाजुक हालत में ही फतेहगढ़ जेल लाया गया था, जहां दाखिल होते ही उन्होंने दम तोड़ दिया. हैरत की बात यह रही कि इतना सब कुछ

होने के बावजूद सरकार का कोई नुमाइंदा जेल में झांकने तक नहीं आया. अलबत्ता जेल के भीतर दम तोड़ने वालों की क्षत–विक्षत लाशों को मेरठ भेजकर पुलिस की देख–रेख में सुपुर्द–ए–ख़ाक कर दिया गया. उस दिन दंगो की दहशत में उनकी मौत पर कोई आंसू बहाने वाला भी नहीं था. फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट वी. एन. गर्ग ने जेल के भीतर सुबह के उजाले में हुई इस घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए, लेकिन कुछ दिनों के भीतर ही इस जांच में लीपापोती कर मामले को रफा–दफा कर दिया गया.

बाद में कई मृतकों के परिजनों व घायलों ने इस सिलसिले में मेरठ की अदालतों में मुक़दमे दर्ज कराए. लगभग दो दशक बाद अदालत ने जेल के तत्कालीन वरिष्ठ अधीक्षक एच. पी. यादव, वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एस. के. मिश्रा और सिपाही बिहारी लाल सहित कई जेलकर्मियों को सम्मन जारी किया, लेकिन तब तक सब कुछ लम्बी और थकाऊ कानूनी प्रक्रिया की भेंट चढ़ चुका था. यानी न मुद्दई बचे और न कसूरवार. बची तो सिर्फ सियासत, जिल्लत और गरीबों को मुंह चिढ़ाती नाइंसाफी. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 07 अंक 05
दिल्ली, 06 अप्रैल–12 अप्रैल 2015
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय
संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार
एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन
सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022–42296060, +91–8451050786, +91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

इंसाफ की जंग जारी रहेगी

नवीन चौहान

फोटो –*सुनील मल्होत्रा*

21 मार्च, 2015 को हाशिमपुरा मामले का दिल्ली की तीस हजारी (विशेष अदालत) ने फैसला सुनाते हुए सभी अभियुक्तों को संदेह का फायदा (बेनिफिट ऑफ डाउट) देते हुए बरी कर दिया. इसके बाद 24 मार्च, 2015 को दिल्ली के लोधी रोड स्थित इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में इस मामले में पांच चश्मदीद गवाह और पीड़ित परिवारों के सदस्यों सहित सिविल सोसायटी के लोगों ने शिरकत की और इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रखने की घोषणा की. अदालत ने पुख्ता सबूतों के आभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया. इससे यह सवाल उठता है कि क्या सरकार के सभी अंग लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं या फिर वे सभी इसकी विपरीत दिशा में काम करते हैं. साल 1987 में घटित इस घटना की जांच कर रही सीबीसीआईडी ने 9 साल बाद चार्जशीट दाखिल की. इसके बाद भी जब उत्तर प्रदेश में इस मामले की न्यायिक प्रक्रिया एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी, तब एक याचिका की सुनवाई करते हुए साल 2002 में उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया. केस के दिल्ली आने के बाद जस्टिस सच्चर के कहने पर पीड़ित पक्ष की वर्तमान वकील वृंदा ग्रोवर ने इस केस की पैरवी करनी शुरू की.

फैसला आने के बाद वृंदा ग्रोवर का कहना है कि यदि कोई पूछे कि इस तरह का एक फैसला अचानक से कैसे आ जाता है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए. इसके लिए पूरी तैयारी होती है और केस को उसी पूर्व निर्धारित दिशा में आगे खींचा जाता है. दुर्घटनावश या संयोगवश इस तरह का फैसला नहीं आया है. इसके सिस्टमैटिक कारण हैं. आज जरूरत है उन सिस्टमैटिक कारणों को जानने की और उन्हें दूर करने की. इस केस में पीड़ितों ने लीगल सिस्टम में जो आस्था दिखाई है, उसे पहले समझें. यदि हम इस निर्णय का एनालिसिस नहीं करेंगे तो ऐसा बार–बार होगा. ये निर्णय डिसअपॉइंटिंग इसलिए नहीं है, क्योंकि आरोपियों को बेनिफिट ऑफ डाउट देकर बरी कर दिया गया है. डिसअपॉइंटिंग इसलिए है, क्योंकि अदालत ने कहीं भी यह समझने की कोशिश नहीं की कि जब स्टेट इस तरह बायस्ड होकर कस्टोडियल किलिंग करता है, तो इसके क्या कारण हैं. यहां सबूत नहीं होने और लोगों के प्रति दु:ख और संवेदना व्यक्त करके ज्यूडीशियरी अपनी जिम्मेदारी टाल रही है और जिनकी तरफ उंगली उठ रही है, ज्यूडीशियरी उस पर तीखी नज़र नहीं डाल रही है.

जांच में सिस्टमैटिक तरीके से सबूतों को छिपाने की कोशिश की गई. जांच ऐजेंसियों ने सबूत जुटाने की कोशिश ही नहीं की. यदि वे कोशिश करते तो सबूत मिल सकते थे. जिस यासीन को ट्रक से उतारकर सबसे पहले गोली मारी गई थी, चश्मदीद नासिर ने यासीन को उन्हीं फोटोग्राफ्स के जरिये पहचाना कि ये नासिर है. प्रवीण जैन, जो इंडियन एक्सप्रेस के फोटोग्राफर हैं और उनके फोटोग्राफ्स इस केस के महत्वपूर्ण सबूत हैं. उन फोटोग्राफ्स में दिख रहा है कि यासीन को पीएसी वाले मोहल्ले से ले जा रहे हैं. उसके बाद उन्हें पीएसी वाले ट्रक में ले जाते हैं, जिसके बाद यासीन कभी घर नहीं लौटे. सभी जानते हैं कि यदि आपको किसी फोटोग्राफ को सबूत बनाना हो तो उसका निगेटिव कोर्ट में जमा करना जरूरी है. जांच एजेंसी ने वे निगेटिव्स कभी प्रवीण जैन से नहीं लिए. वृंदा ग्रोवर कहती हैं कि उन्होंने प्रवीण जैन से अपने दोस्तों के माध्यम से संपर्क किया. वह कहती हैं कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि प्रवीण जैन के यहां घर में उसके निगेटिव्स मिल गए. उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि आप कौन सी तस्वीरों की बात कर रही हैं. वह खुद उन निगेटिव्स को कोर्ट में लेकर आए और गवाही दी. जो काम सीबीसीआईडी 9 साल में नहीं कर सकी, उस काम को प्रवीण जैन ने किया. वृंदा ग्रोवर ने कहा कि इसीलिए वह जांच में लापरवाही का आरोप लगाती हैं.

> हम अपील करेंगे. हमारे पास पर्याप्त सबूत थे. यदि आप हमारी आखिरी बहस पर नज़र डालें तो हमारा केस बेदह मजबूत था. यह पर्याप्त था या नहीं, यह अपील कोर्ट को निर्धारित करना है. हमने अपना पक्ष रखा है. कुछ मटेरियल हमारे पास हैं, जिसके बारे में अभी बात करना ठीक नहीं होगा. अगले 60 से 90 दिनों में हम मामले की अपील दायर कर देंगे. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपील दायर का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार को लेना है.
>
> *–रेबेका जॉन, पीड़ित पक्ष की वकील*
>
> हमारी मेहनत खराब नहीं हुई है. सिस्टम एक्सपोज हुआ है. पुलिस वाले वर्दीधारी कत्लेआम करते हैं, तो स्टेट के हर इंस्टीट्यूशन, पूरा ज्यूडीशियल सिस्टम, पूरा लीगल सिस्टम उनकी प्रोटेक्शन करता है, न कि उनको सजा देता है. हमारे पास सबूत हैं. अभी हमारे पास अपील के लिए वक्त है. हमें आज ही जजमेंट मिला है. अभी पढ़ा भी नहीं है. कानून के हिसाब से जितना वक्त है, उस वक्त में अपील दायर करेंगे. अब हाई कोर्ट में कितना वक्त लगेगा, इसका मैं कोई अंदाजा नहीं लगा सकती.
>
> *–वृंदा ग्रोवर, पीड़ित पक्ष की वकील*

ट्रक को जब 10–15 साल बाद मैकेनिकल इंस्पेक्शन के लिए भेजा गया, तो उसमें गोलियों के छेद थे, जो तीन लोगों को मारने के बाद गाड़ी में बचे लोगों के शोर मचाने पर चलाई गईं थीं. एक जगह जहां गोली लगी थी, वहीं तीन इंच की आयरन की पट्टी लगी है. वहां गोली टीन की बॉडी के रास्ते गई थी, लेकिन जज साहब ने कहा कि यह पर्याप्त नहीं है. उस ट्रक को इतने दिनों बाद इंस्पेक्शन के लिए क्यों भेजा गया. वह ट्रक पीएसी का था. वह पीड़ितों के कंट्रोल में नहीं था. कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि पीएसी इसमें शामिल थी. घटना के कुछ देर बाद ही यह मालूम चल गया था कि पीएसी ने कुछ लोगों को गिरफ्त में लिया है और उन्हें गोली मारी है. ऐसा नहीं है कि लंबे समय बाद यह मालूम हुआ हो और सबूत नष्ट कर दिए गए हों. कोर्ट ने पांचों बचे लोगों की गवाही को सच पाया है और कहा कि उन पर शक करने का कोई कारण नहीं है. इन सभी के बयानों में कोई विरोधाभास नहीं है. पुलिस द्वारा उनपर पीएसी द्वारा हमला करने की बात न कहने के लिए दबाव डालना और उनका उस समय ऐसा बयान देना सामान्य है. ऐसी मनोदशा में कोई भी व्यक्ति ऐसा ही करता. पीएसी के जवानों ने चश्मदीद गवाहों को मरा हुआ समझकर पानी में फेंक दिया था. भगवान की मर्जी थी कि वे बच गए. उनकी गवाही से यह साबित होता है कि घटना घटी थी. आरोपियों की पहचान सुनिश्चित नहीं हो सकी, इसलिए उन्हें संदेह का फायदा (बेनिफिट ऑफ डाउट) दिया. पीएसी के जवानों ने तो यहां तक कोशिश की थी कि कोई भी इस घटना का चश्मदीद ही न बचे.

क्या हमारे देश में जांच एजेंसियां नहीं हैं या यदि कोई घटना के बारे में बताने के लिए नहीं होता है, तो क्या हम केस बंद कर देते हैं. ■

हत्या के आरोपी पीएसी जवान बरी

फैसले के बाद मातम मना रहा है हाशिमपुरा

डॉ. क़मर तबरेज़

हाशिमपुरा दंगा मामले में 28 वर्षों की लंबी अदालती कार्यवाही के बाद फैसला आ चुका है. यह फैसला दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट ने 21 मार्च को सुनाया. फैसले में अदालत ने पीएसी के उन सभी 16 आरोपियों को बरी कर दिया, जिन पर 22 मई, 1987 को हाशिमपुरा के 42 मुस्लिम नौजवानों को गोली मारकर नृशंस हत्या करने और उनकी लाशें गंग नहर और हिंडन नदी में फेंकने का आरोप है. इस फैसले के बाद हाशिमपुरा के लोग भारतीय न्यायपालिका और इसके न्याय करने के तरीक़ों पर मातम मना रहे हैं. 'चौथी दुनिया' की टीम ने इस जघन्य हत्याकांड पर फैसला आने के अगले ही दिन हाशिमपुरा का दौरा करके वहां के लोगों की प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया.

न्याय मिलने की उम्मीद जब ख़त्म हो जाती है, तो लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है, यह आजकल मेरठ शहर के हाशिमपुरा मोहल्ले का दौरा करने पर आसानी से देखा और सुना जा सकता है. गुस्से में लोग व्यवस्था को गालियां दे रहे हैं. मीडिया वालों को देखते ही आक्रोश से कहते हैं, लो आ गए हमारे ज़ख़्मों को कुरेदने. हमसे कितनी बार पूछोगे कि कितने लोग मारे गए, कैसे मारे गए. भईया! हमें चैन से जीने दो. कुछ लोग गुस्से से कहते हैं कि हमारे 42 लोग मारे गए. अदालत भी इस बात को मानती है कि इस दिन यानी 22 मई, 1987 को हाशिमपुरा के 42 लोग पीएसी की गोलियों से मारे गए. वे कहते हैं कि गोली मारने वाले कौन लोग थे, यह हमसे क्यों पूछते हो, यह पता लगाना तो तुम्हारा काम है. सरकार और न्यायालय को तो हमने नहीं, बल्कि सीआइडी के लोगों ने यह बात बताई थी कि हाशिमपुरा नरसंहार में पीएसी की 41वीं बटालियन के जवान शामिल थे. फिर हमसे यह क्यों कहा गया कि तुम कैसे कह सकते हो कि गोली चलाने वाले यही लोग थे. जज ने हमसे कहा कि जब लोगों को गोली मारी गई, तब रात का समय था और पीएसी वाले अपने सरों पर हेलमेट पहने हुए थे, फिर तुमने रात के अंधेरे में उनके चेहरों को कैसे पहचान लिया? और इसी सवाल को आधार बनाकर जज ने अपना फैसला सुना दिया कि जिन लोगों को अरोपी बनाया गया है, उनकी सही पहचान नहीं की जा सकती कि गोली मारने वाले यही लोग थे. लिहाज़ा, उन्हें बरी किया जाता है.

हालांकि यह बात सभी जानते हैं कि 22 मई, 1987 को जब पीएसी वाले हाशिमपुरा के पुरुषों को उनके घरों से निकाल कर एक मैदान में जमा कर रहे थे, उस समय दिन का उजाला था. उनकी वह तस्वीरें तब भी अख़बारों में छपी थीं और आज भी छपी हैं. क्या तब लोगों ने उन पुलिस जवानों या पीएसी जवानों के चेहरे नहीं देखे थे? दूसरी बात यह कि जब भी पुलिस, पीएसी या आर्मी की किसी टुकड़ी को किसी जगह पर तैनात किया जाता है तो पुलिस चौकी या पीएसी और आर्मी के कंट्रोल रूम में वह सभी रिकॉर्ड मौजूद होते हैं कि किस काम के लिए, किस स्थान पर और किस गाड़ी से उन्हें वहां भेजा जा रहा है. क्या अदालत के माननीय न्यायाधीश इन सभी अभिलेखों को मंगवाकर यह नहीं पता कर सकते थे कि जिस समय लोगों को ट्रकों में भरकर ले जाया जा रहा था, उस समय उस ट्रक पर पीएसी के कौन-कौन जवान तैनात थे, ट्रक का नंबर क्या था? हाशिमपुरा के लोग आज भी पत्रकारों से यही सब सवाल करते हुए दिखाई देते हैं. उनके इसी आक्रोश का सामना 'चौथी दुनिया' की टीम को भी वहां पहुंचने पर करना पड़ा.

हाशिमपुरा केस के चश्मदीद गवाह ज़ुल्फिक़ार नासिर, बाबुद्दीन अंसारी, मुजीबुर्रहमान और मोहम्मद उस्मान ने 'चौथी दुनिया' को अपना दर्द सुनाते हुए अपने शरीर पर गोलियों के निशान दिखाते हुए कहा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है. हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं. अगर अदालत यह मानती है कि हमारे साथ यह घटना हुई है, तो घटना को अंजाम देने वाला भी तो कोई होगा. अब यह काम तो सरकार और अदालत का है कि वह दोषियों का पता लगाए और फिर उन्हें सज़ा दे. हमने 28 वर्षों तक कोर्ट के चक्कर लगाए, लेकिन हमें क्या मिला? यह चारों चश्मदीद गवाह, जो पीएसी की गोली लगने के बावजूद ख़ुशकिस्मती से अपनी जान बचाने में सफल रहे, तीस हज़ारी कोर्ट के इस फैसले से मायूस अवश्य हैं, लेकिन अभी उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है. वह न्याय प्राप्त करने की इस लड़ाई को आगे लेकर जाना चाहते हैं. उन्हें इस बात की उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय से उन्हें अवश्य न्याय मिलेगा.

दूसरी ओर हाशिमपुरा के आम लोग हैं, जो पूरी तरह निराश हो चुके हैं. उन्हें लगता है कि उन्हें कोई न्याय नहीं मिल पाएगा. गलियों और चौराहों पर खड़े युवा बार-बार यही कहते हैं कि सरकार और अदालत उन लोगों के साथ खड़ी है, जिन्होंने हमारे परिजनों को गोलियां मारीं. अब सरकार और न्यायालय से तो लड़ा नहीं जा सकता. 21 मार्च, 2015 को दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट ने पीएसी के सभी 16 आरोपियों को 'बेनिफिट ऑफ डाउट' के आधार पर जब बरी किया तो हाशिमपुरा के लोगों को लगा कि उन्होंने 28 वर्षों तक जिस न्याय की आस में अदालतों के चक्कर लगाए, वह सारी मेहनत बेकार गई.

हाशिमपुरा की गली नंबर 2 के मकान नंबर 8 में रहने वाले लगभग 80 वर्षीय अब्दुल हमीद ने 'चौथी दुनिया' के संवाददाता को अपने सिर का घाव दिखाते हुए बताया कि इस दिन पुलिस हमें घर से उठाकर पुलिस लाइन ले गई और हमें जेल में बंद कर दिया. पुलिस वाले हर दिन वहां हमारे ऊपर लाठियां बरसाते और कहते 'बाबरी मस्जिद लोगे, यह लो बाबरी मस्जिद. और फिर हमारे ऊपर ताबड़तोड़ इनकी लाठियां बरसने लगतीं. अब्दुल हमीद की पत्नी हाजिरा बताती हैं कि उनके पति के सिर पर गहरा घाव आया था और इस घाव में कीड़े भी पड़ गये थे, बड़ी मुश्किल से इनकी जान बची। दूसरी ओर इन दोनों के 17 वर्षीय बेटे मोहम्मद नईम को पीएसी वालों ने गोली मारकर उसकी लाश गंग नहर में फेंक दी थी. बाद में ईद के दिन बेटे की लाश मेरठ पुलिस ने यह कहकर वापस दी कि ''यह लो तुम्हारे लिए ईद का तोहफ़ा.'' यह बात बताते हुए हाजिरा की आंखों में आंसु आ जाते हैं. इसी घर में हाजिरा के साथ इनकी बहुरानी ज़रीना भी रहती हैं, जो इस दिन 7 दिन के बच्चे के साथ ज़चगी की हालत में थीं, जब इनके पति ज़हीर अहमद और बेटे जावेद को पीएसी वालों ने गोली मारकर जान लेली थी. रो-रो कर इनकी आंखें सूज गई हैं और मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती. यह सारा मंज़र दिल दहलाने वाला था. अब उन लोगों को लगता है कि इंसाफ़ के सारे दरवाज़े बंद हो चुके हैं, इसीलिए यह लोग तीस हज़ारी कोर्ट के निर्णय पर मातम मना रहे हैं. यहां एक बात को स्पष्ट करना ज़रूरी है. हाशिमपुरा के अधिकतर लोग अशिक्षित हैं, मज़दूरी करके पेट पालते हैं. उन्हें क़ानून की बारीकियों का ज्ञान नहीं है. शायद यही कारण है कि हाशिमपुरा के अधिकतर लोगों को लगता है कि तीस हज़ारी कोर्ट का निर्णय अंतिम है और इस निर्णय को अब चैलेंज नहीं किया जा सकता. दूसरा कंफ्यूज़न स्वयं पत्रकारों में है. अधिकतर पत्रकार, जो हाशिमपुरा पर रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें यह लगता है कि हाशिमपुरा नरसंहार केस की एफआईआर यूपी सरकार की ओर से की गई थी और सरकार नहीं चाहती कि पीएसी वालों को सज़ा हो, इसलिए वह जानबूझ कर इस केस को कमज़ोर करना चाहती है, केस को तूल देना चाहती है, ताकि हाशिमपुर के लोग थक-हारकर इस घटना को भूल जाएं. दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी यह कह चुके हैं कि हाशिमपुरा के सभी पीड़ितों को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवज़ा दिया जा चुका है. इसका दूसरा मतलब यह हुआ कि पीएसी के हत्यारों को सज़ा दिलाने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है. लेकिन, जब हमने हाशिमपुरा केस में पीड़ितों के एक वकील जुनैद अहमद से बात की, तो पता चला कि एफआईआर बाबुद्दीन अंसारी और मुजीबुर्रहमान की ओर से दर्ज कराई गई थी. अब अगर दोनों ही या इनमें से कोई एक भी तीस हज़ारी कोर्ट के इस निर्णय को उच्च अदालत में चैलेंज करना चाहे तो वह कर सकता है. हालांकि उन्होंने यह बात ज़रूर कही कि तीस हज़ारी कोर्ट के वर्तमान निर्णय से हाशिमपुरा के लोगों में अभी भी काफ़ी आक्रोश है, इसलिए आगे वह क्या रणनीति अपनाएंगे, इस पर फिलहाल कोई बात करने को तैयार नहीं है. हमें आशा करनी चाहिए कि हाशिमपुरा के लोगों को न्याय मिलेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

जिन्हें अब भी मुआवज़े का इंतज़ार है

1-	अख़लाक पुत्र अहमद यार ख़ां	दरभंगा, बिहार
2-	कौसर अली पुत्र मोहम्मद अब्बास अंसारी	दरभंगा बिहार
3-	मोहम्मद अज़ीम पुत्र बकरीद अंसारी	दरभंगा, बिहार
4-	मोहम्मद यूसुफ़ पुत्र शरफ़ुद्दीन	पिलखुआ, उत्तर प्रदेश
5-	शाकिर पुत्र ख़लील अहमद	बिजनौर, उत्तर प्रदेश
6-	मुईनुद्दीन पुत्र करीमुद्दीन	हाशिमपुरा, मेरठ, उत्तर प्रदेश
7-	इस्लामुद्दीन पुत्र बन्दो	

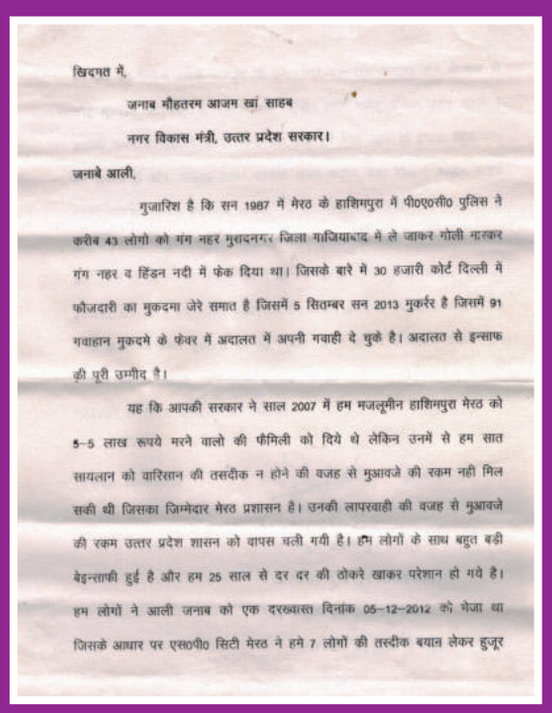

खिदमत में,

जनाब मौहतरम आजम खां साहब

नगर विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार।

जनाबे आली,

गुजारिश है कि सन 1987 में मेरठ के हाशिमपुरा में पी0ए0सी0 पुलिस ने करीब 43 लोगो को गंग नहर मुरादनगर जिला गाजियाबाद में ले जाकर गोली मारकर गंग नहर व हिंडन नदी में फेंक दिया था। जिसके बारे में 30 हजारी कोर्ट दिल्ली में फौजदारी का मुकदमा जेरे समात है जिसमें 5 सितम्बर सन 2013 मुकर्रर है जिसमें 91 गवाहान मुकदमे के फेवर में अदालत में अपनी गवाही दे चुके है। अदालत से इन्साफ की पूरी उम्मीद है।

यह कि आपकी सरकार ने साल 2007 में हम मजलूमीन हाशिमपुरा मेरठ को 5-5 लाख रूपये मरने वालो की फैमिली को दिये थे लेकिन उनमें से हम सात सायलान को वारिसान की तसदीक न होने की वजह से मुआवजे की रकम नही मिल सकी थी जिसका जिम्मेदार मेरठ प्रशासन है। उनकी लापरवाही की वजह से मुआवजे की रकम उत्तर प्रदेश शासन को वापस चली गयी है। हम लोगों के साथ बहुत बड़ी बेइन्साफी हुई है और हम 25 साल से दर दर की ठोकरे खाकर परेशान हो गये है। हम लोगों ने आली जनाब को एक दरख्वास्त दिनांक 05-12-2012 को भेजा था जिसके आधार पर एस0पी0 सिटी मेरठ ने हमे 7 लोगों की तस्दीक बयान लेकर हुजूर

आमतौर पर लोगों को यही मालूम है कि हाशिमपुरा में 22 मई, 1987 को जो लोग पीएसी की गोलियों का शिकार हुए, उनकी संख्या 42 है और यूपी सरकार ने उनमें सभी के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये मुआवज़े के तौर पर दे दिए, लेकिन चौथी दुनिया के हाथ लगे एक दस्तावेज़ के अनुसार, इन 42 में से 7 मृतक ऐसे भी हैं, जिनके परिजनों को अभी तक सरकार की ओर से कोई मुआवज़ा नहीं मिला है. उन 7 मृतकों के परिजनों को यूपी सरकार की ओर से मुआवज़ा न मिलने का एक कारण यह भी हो सकता है कि उनमें से एक को छोड़कर शेष 6 लोग चूंकि हाशिमपुरा के नहीं थे, इसलिए सरकार ने उनको मुआवज़ा देना आवश्यक न समझा हो. जैसा कि सूची को देखने से पता चलता है, पहले तीन बिहार के दरभंगा ज़िले के रहने वाले थे और हाशिमपुरा में बतौर मज़दूर काम करते थे. उन तीनों के पिता अब भी बिहार के दरभंगा ज़िले में ही रहते हैं. 22 मई, 1987 की रात को पीएसी की गोली लगने के बावजूद बाबुद्दीन अंसारी अपनी जान बचाने में सफल रहे, लेकिन उनके तीन अन्य साथी अख़लाक, कौसर और मोहम्मद अज़ीम अपनी जान नहीं बचा पाए. अब उनके पिता चाहते हैं कि जिस प्रकार हाशिमपुरा के 35 मृतकों के परिजनों को यूपी सरकार ने पांच-पांच लाख रुपये का मुआवज़ा दिया है. इसी प्रकार उन्हें मुआवज़े की यह राशि दी जाए, ताकि वह अपनी शेष जिन्दगी इस पैसे की मदद से आसानी से गुज़ार सकें. इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर के रहने वाले ख़लील अहमद, मुज़फ्फरनगर के अहमद यार ख़ां और पिलखुआ के शरफुद्दीन अभी तक सरकारी मुआवज़े का इंतज़ार कर रहे हैं. इन तीनों के बेटे भी हाशिमपुरा नरसंहार में मारे गए थे.

सरकार का यह कहना है कि इन मृतकों के परिजनों की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, जबकि 'चौथी दुनिया' के हाथ लगे दस्तावेज़ के अनुसार, इन सातों मृतकों के परिजनों ने मुआवज़े के सिलसिले में 5 दिसंबर, 2012 और फिर 22 अगस्त, 2013 को आज़म ख़ां को पत्र लिखकर उनसे मदद की अपील की थी. दस्तावेज़ से यह भी पता चलता है कि आज़म ख़ां ने मेरठ प्रशासन को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया था, इसके बावजूद उन लोगों को अब तक मुआवज़े की राशि नहीं मिल सकी है. दस्तावेज़ में एक जगह लिखा हुआ है कि '...हम लोगों ने आदरणीय (आज़म ख़ां) को एक आवेदन 05-12-2012 को भेजा था, जिसकी बुनियाद पर एसपी सिटी, मेरठ ने हम 7 लोगों के पुष्ट बयान लेकर आदरणीय की सेवा में भेज दिया, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों तक इस पुष्टि होने के बाद भी कोई मुआवज़े की राशि और सूचना नहीं पहुंची'. इसी दस्तावेज़ में एक जगह यह भी लिखा हुआ है कि '...आप की सरकार ने वर्ष 2007 में हम पीड़ितों हाशिमपुरा, मेरठ को 5-5 लाख रुपये मृतकों के परिजनों को दिए थे, लेकिन उनमें से 7 लोगों के परिजनों की पुष्टि न होने के कारण उन्हें मुआवज़े की राशि नहीं मिल सकी थी, जिसका जिम्मेदार मेरठ प्रशासन है. उनकी लापरवाही के कारण मुआवज़े की राशि उत्तर प्रदेश सरकार को वापस चली गई है'. ■

28 साल बाद हाशिमपुरा

दरभंगा के बाबूद्दीन और मुजीबुर्रहमान के हौसले को सलाम

शशि शेखर

साल 1982 की बात है. बिहार के दरभंगा से रोजी–रोटी की तलाश में 16 साल का बाबूद्दीन हजार किलोमीटर दूर मेरठ आ गया था. मेरठ के हाशिमपुरा मोहल्ले में हथकरघा का काम होता है. बाबूद्दीन को अपने साथी मुजीबुर्रहमान के साथ हथकरघा चलाने का काम मिल गया. मुजीबुर्रहमान भी तब 15 साल का था और दरभंगा से ही काम की तलाश में यहां पहुंचा था. मजे से दोनों अपना काम कर रहे थे, लेकिन, 22 मई 1987 का दिन इन दोनों प्रवासी मजदूरों के जीवन में काला दिन बन कर आया था. 2 बजे दिन में बाबूद्दीन अपने घर में बैठे थे. अचानक पुलिस पहुंची. तलाशी के नाम पर सबको बाहर लाया गया. उसके बाद मुख्य सड़क पर, जहां पहले से ही करीब 300 लोग जमा किए गए थे, इन्हें लाया गया. रात 8 बजे करीब 50 लोगों के साथ बाबूद्दीन को एक पीली ट्रक पर बिठा कर पीएसी वाले मुरादनगर ले गए. वहां गंगनहर के पास ट्रक रोक दी गई. एक–एक आदमी को ट्रक से उतार कर पीएसी के जवानों ने गोली मारी और लाश को गंगनहर में फेंक दिया. उसके बाद वो ट्रक गाजियाबाद की ओर चल दी और हिंडन के किनारे रूकी. बाबूद्दीन को भी दो गोली लगी थी. उसे दो जवानों ने पकड़ कर और आश्वस्त होकर कि वह मर चुका है, हिंडन नदी में फेंक दिया. और भी कई लोगों को हिंडन नदी में फेंका गया. इस संवाददाता से बात करते हुए बाबूद्दीन बताते हैं कि पानी में कई घंटे रहने के बाद मुझे होश आया, जहां गाजियाबाद पुलिस का कोई अधिकारी पहुंचा और मुझे अपने साथ लेकर लिंक रोड थाने गया, एफआईआर दर्ज करवाई और फिर नरेंद्र मोहन अस्पताल में मुझे भर्ती करवाया. (वह अधिकारी तत्कालीन गाजियाबाद पुलिस कप्तान वी एन राय थे). इस तरह, हाशिमपुरा हत्याकांड में सबसे पहली एफआईआर बाबूद्दीन अंसारी के नाम से ही दर्ज हुई थी.

अब कल्पना कीजिए कि एक गरीब नौजवान, जो बिहार के दरभंगा से मजदूरी करने मेरठ आया हो और उसके साथ ऐसा हादसा हो जाए, तो वह क्या करेगा. जाहिर है, इतना कुछ होने के बाद भी वो कम से कम ऐसी जगह पर रहने की हिम्मत तो नहीं ही जुटा पाएगा, लेकिन उस हौसले को सलाम, जिसकी वजह से बाबूद्दीन न सिर्फ 28 साल से हाशिमपुरा में रह रहे हैं, बल्कि अपने लिए और हाशिमपुरा के अन्य पीड़ितों के लिए न्याय की लड़ाई भी लड़ रहे हैं. हर एक सुनवाई पर वह गवाही देने के लिए दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट जरूर पहुंचते थे. एक गरीब प्रवासी मजदूर निचली अदालत के इस फैसले के बाद भी (जिसमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है) अपना हौसला बनाए रखे हुए है और आगे लड़ाई लड़ते रहने की बात करता है. गौरतलब है कि बाबूद्दीन को आज तक सरकार से मुआवजा के तौर पर एक भी पैसा नहीं मिला है, क्योंकि दो गोली खाने के बाद भी वो जिंदा बच गया था, लेकिन बाबूद्दीन अन्य पीडितों को मुआवजा मिले, इसके लिए जी–तोड़ मेहनत कर रहा है.

इसी तरह की कहानी बाबूद्दीन के साथी मुजीबुर्रहमान की भी है. रहमान भी दरभंगा से हाशिमपुरा पावरलूम का काम करने आया था. तब उसकी उम्र 16 साल थी. उस हत्यारे पीले ट्रक में वह भी था. गंग नहर के पास लाइन में खडा कर पीएसी ने इसे भी दो गोली मारी थी और

नहर में फेंक दिया था. इस गोलीकांड में इसके चाचा मो. अजीम की मौत तत्काल हो गई थी, लेकिन सौभाग्य से रहमान जिंदा बच गया. यहां से पुलिस वाले उसे मुरादनगर थाने ले गए और एफ आई आर दर्ज हुई. इस तरह हाशिमपुरा हत्याकांड में दूसरी एफआईआर मुजीबुर्रहमान के नाम से दर्ज हुई. संवाददाता ने बातचीत के दौरान बाबूद्दीन अंसारी और मुजीबुर्रहमान का जो आत्मविश्वास देखा, वह किसी भी तथाकथित पढ़े–लिखे, समझदार इंसान से अधिक था. शायद यह मौत की मुंह से निकलने के बाद का आत्मविश्वास और हौसला है, जिसके बाद आपको न कोई डरा सकता है, न झुका सकता है. तभी तो, मुफलिसी की जिंदगी जीने के बाद भी इन दोनों ने मानो ये ठान लिया है कि ***हार नहीं मानूंगा, रार नई ठानूंगा.*** ■

shashishekhar@chauthiduniya.com

दर्द, जो आंखों से झलकता है

गली नंबर 4 का मकान नंबर 2. इसके पहली मंजिल पर रहती है अंजुम, 70 वर्षीय उनकी सास नसीबन, उनकी पांच बेटियां और दो बेटे. अंजुम के दोनों बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं है. नसीबन का एक बेटा और अंजुम के पति सलीम 2013 में आत्महत्या कर चुके हैं. नसीबन के पति जमील अहमद और छोटा बेटा मो. नसीम 22 मई की उस काली रात पीएसी की गोली के शिकार हो चुके हैं. यानी, इस परिवार में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है, जो अपने परिवार के लिए दो जून की रोटी कमा सके. इसलिए अंजुम खुद स्वर्गीय पति की हार्डवेयर की दुकान को संभालती हैं.

अंजुम की शादी सलीम से 1989 में, यानी उस गोलीकांड के ठीक दो साल बाद हुई थी, जिसमें उसके ससुर और देवर को अपनी जान गंवानी पड़ी थी. अंजुम बताती हैं कि मेरे पति

सत्तर साल की एक बूढ़ी औरत से आखिर ये तो नहीं ही पूछा जा सकता कि अदालत के इस फैसले के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा हैं?

को भी पीएसी वाले पकड़ कर ले गए थे, लेकिन उन्हें बाद में छोड़ दिया गया था, लेकिन उस गोलीकांड में अपने पिता और भाई को खोने के गम ने सलीम को बुरी तरह झझकोर दिया था. उन्हें शराब की लत पड गई और काफी तनाव में जीने लेगे. अदालती कार्यवाही और प्रक्रिया से उब कर सलीम ने 2013 में आत्महत्या कर ली, लेकिन अंजुम के हौसले की दाद देनी चाहिए कि इतना सब कुछ होने और सहने के बाद भी वह बहुत ही हिम्मत दिखाते हुए कहती हैं कि हम इस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं, बल्कि आगे भी लड़ेंगे. अंजुम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इस केस को लड़ने में भी खर्च करती हैं. वह कहती हैं कि मुझे नहीं मालूम कि सरकार की तरफ से क्या किया गया, लेकिन इतना मालूम है कि फैसला गलत आया है, लेकिन उम्मीद भी है कि न्याय मिलेगा, जरूरत सिर्फ लड़ाई लड़ते रहने की है.

सत्तर साल की नसीबन जो भी बोलती हैं, वो समझ में नहीं आता, लेकिन उनका दुख उनके शब्दों से नहीं, उनकी आंखों और उनके चेहरे से साफ झलकता है. टूटे–फूटे शब्दों में नसीबन बताती हैं कि जब पुलिस मेरे पति की लाश लेकर आई, तो मुझे सिर्फ उनके पैर देखने को मिले. अपने शौहर और बेटे की फोटो हाथ में लेकर जब वह फोटो खिंचवाने के लिए खाट पर बैठती हैं, तो लगता है कि शायद अब भी इस बूढ़ी औरत को यकीन है कि उसे इंसाफ मिलेगा. एक पत्रकार होने के नाते मैं और मेरे साथी कमर तबरेज बड़ी मुश्किल से उनसे सवाल पूछने की हिम्मत जुटा पाते हैं. इसलिए, क्योंकि किसी के 28 साल पुराने जख्मों को कुरेदने पर जो दर्द रिसता है, उसे देखने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए. सत्तर साल की एक बूढ़ी औरत से आखिर यह तो नहीं ही पूछा जा सकता कि अदालत के इस फैसले के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? ■

शशि शेखर

shashishekhar@chauthiduniya.com

हाशिमपुरा

अदालती फैसले पर उर्दू अख़बारों का रुख

21 मार्च को जिस दिन यह फैसला आने वाला था, दैनिक इंक़लाब को छोड़ कर दिल्ली के किसी भी बड़े उर्दू अख़बार ने अपने पाठकों को यह बताने की ज़हमत नहीं की कि एक लम्बे इंतज़ार के बाद मुसलमानों से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकदमे का फैसला आने वाला है. इंक़लाब ने इस खबर को हाशिमपुरा नरसंहार पर ऐतिहासिक फैसला आज के शीर्षक के साथ यह खबर छापी थी, लेकिन यह अख़बार भी इस मामले को कितनी अहमियत दे रहा था, इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि इस खबर को अख़बार के दूसरे पन्ने पर जगह मिली.

शफीक आलम

साल 1987 में मेरठ के हाशिमपुरा मोहल्ले के 42 लोगों की पीएसी द्वारा गोली मार कर हत्या या नरसंहार पर दिल्ली की तीस हजारी सत्र न्यायालय में चल रहे मुक़दमे का फैसला आ गया है. जानना जरूरी है कि मुसलमानों की आवाज़ होने का दावा करने वाले उर्दू अख़बारों ने फैसले को कैसे देखा? उर्दू अखबारों ने अपने पाठकों को इस मुद्दे पर कितनी जानकारी दी? फैसला आने से पहले दिन या फैसले के दिन क्या उर्दू अख़बारों ने इस मुकदमे पर कोई रिपोर्ट प्रकाशित की? यदि प्रकाशित की तो अख़बार में कहां और कितनी जगह मिली?

अदालत का फैसला आने के बाद रोजनाम राष्ट्रीय सहारा, इंक़लाब, सहाफत, हिंदुस्तान एक्सप्रेस, हैदराबाद से छपने वाले अख़बार मुसिफ और सियासत समेत देश के तकरीबन सभी छोटे–बड़े उर्दू अख़बारों ने सम्पादकीय और रिपोर्टें प्रकाशित की हैं. रोजनाम राष्ट्रीय सहारा अपने सम्पादकीय में लिखता है कि जिस तरह इस मामले में आदालत ने कसूरवारों को बरी किया, उससे अफ़सोस तो ज़रूर है, लेकिन इस फैसले से बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं है. अख़बार यह कहता है कि पिछले दंगों में हजारों लोग मरे गए हैं, लेकिन शायद ही किसी दोषी को सजा मिली है. आखिर में मुस्लिम नेतृत्व और संगठनों पर सवाल उठाए गए हैं. इंक़लाब ने भी अपने सम्पादकीय में फैसले पर अफ़सोस जताया है और सरकारी जांच

एजेंसियों की सख्त आलोचना की गई है. सम्पादकीय में यह भी कहा गया है कि कानून के रखवालों ने कानून की आंख में धुल झोंकने के लिए जानबुझ कर साक्ष्य नहीं पेश किए. रोजनामा सहाफत ने भी लगभग वही बातें कहीं हैं, जो दूसरी अख़बारों में कही गईं हैं. कुल मिलाकर देखा जाए तो देश सभी अख़बारों ने लगभग इसी तरह के विचार व्यक्त किए हैं.

21 मार्च को जिस दिन यह फैसला आने वाला था, दैनिक इंक़लाब को छोड़ कर दिल्ली के किसी भी बड़े उर्दू अख़बार ने अपने पाठकों को यह बताने की ज़हमत नहीं की कि एक लम्बे इंतज़ार के बाद मुसलमानों से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकदमे का फैसला आने वाला है. इंक़लाब ने इस खबर को हाशिमपुरा नरसंहार पर ऐतिहासिक फैसला आज के शीर्षक के साथ यह खबर छापी थी, लेकिन यह अख़बार भी इस मामले को कितनी अहमियत दे रहा था, इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि इस खबर को अख़बार के दूसरे पन्ने पर जगह मिली. बहरहाल, फैसला आने के बाद देश के तकरीबन हर छोटे–बड़े उर्दू अख़बार ने अदालत के फैसले पर रिपोर्टें प्रकाशित कीं. इन रिपोर्टों में अदालत के फैसले के साथ–साथ इस वारदात, पुलिस जांच, मुक़दमे की कार्रवाई और फैसला आने के बाद की रणनीति पर रिपोर्टें शामिल थीं, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि कुछ ऐसे भी अख़बार थे, जिन्होंने अदालत का फैसला आने के दूसरे दिन भी कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की. उनकी नींद उस समय खुली, जब कई टीवी न्यूज़ चैनलों ने इस फैसले पर परिचर्चा प्रसारित की. मिसाल के तौर पर लखनऊ, दिल्ली और मुंबई से प्रकाशित होने वाला अख़बार सहाफत दैनिक है, जिसकी नींद फैसला आने के तीसरे दिन खुली. अब सवाल यह उठता है कि इसे क्या माना जाए? क्या ये अखबार किसी के दबाव में काम करते हैं या उन्हें इतनी बड़ी खबर की जानकारी ही नहीं थी? कुल मिलाकर देखा जाए तो उर्दू अख़बारों ने आदालत के फैसले के बाद ही इसकी रिपोर्टिंग की, वो भी आधे–अधूरे मन से. ■

feedback@chauthiduniya.com

भूमिका की तलाश में पूर्व नायक

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

जबीर हुसैन | नागमणि | पी.के. सिंहा | प्रेम कुमार मणि | रंजन यादव | शकुनी | शिवानंद तिवारी

बिहार में विधानसभा चुनावों की दुंदुभी बज गई है और सेनाएं रणभूमि में उतरने को बेताब हैं. हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि आसन्न चुनावी संघर्ष का स्वरूप क्या होगा– राष्टीय जनतांत्रिक गठबंधन के सामने एकीकृत जनता परिवार या बिहार में उनके घटक जद (यू) और राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन का उम्मीदवार होगा अथवा हर क्षेत्र में कम से कम तीन प्रत्याशी होंगे, पर अभी से इतना तो तय लगता है कि हाल–फिलहाल तक गैर भाजपा चुनावी रणनीति को आकार देनेवाले कुछ राजनीतिक चेहरे के जिम्मे कोई काम नहीं होगा. ये दशकों से बिहार की राजनीति में अपनी बौद्धिक छटा बिखेरनेवाले ऐसे नेताओं की भूमिका बनाने के जरिये राजनीति को सलाह–मशविरा देने तक सिमट कर रह जाएगी. इतना ही नहीं, सत्ता राजनीति की रणनीति को धार देने में अपनी भूमिका दिखानेवाले कुछ राजनीतिक परिंदों की भूमिका भी बदली रहेगी.

प्रखर सामजवादी और अपनी गैर भाजपाई राजनीति के लिए विख्यात शिवानंद तिवारी की आसन्न विधानसभा चुनावों में कोई विशिष्ट दलीय भूमिका नहीं रहेगी, ऐसा लगभग तय है. यह विडम्बना ही है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को उनके आरंभिक दौर में राजनीति का गुर देनेवाले शिवानंद तिवारी को अब इन दोनों में कोई अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं. राज्यसभा की दूसरी बार (2014) उम्मीदवारी न मिलने से नाराज तिवारी जी की पिछले संसदीय चुनाव में भी कोई खास भूमिका नहीं रह गई थी. अपनी भाजपा विरोधी राजनीति के अनुसार काम करने का उस चुनाव में भी उन्होंने काफी प्रयास किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली. जद (यू) के अघोषित सुप्रीमो नीतीश कुमार ने चुनाव से काफी पहले ही उन्हें अपने से अलग मान लिया और फिर साथ लाने की जरूरत नहीं समझी. बार–बार इधर–उधर के कारण राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का उन पर भरोसा नहीं रहा. हालांकि तिवारी जी ने अपने तरफ से काफी कोशिश की थी, पर नतीज़ा वही ढाक के तीन पात रहा. फिर भी वह कुछ न कुछ करते ही रहे. सत्तर साल से अधिक उम्र के तिवारी जी अब किस राजनीतिक ध्रुव की तलाश करें– कहां जाएं. हालांकि मांझी–नीतीश विवाद में वह खुल कर जीतनराम मांझी के पक्ष में रहे. उनके पक्ष में विधायकों के नाम खुली चिट्ठी भी लिखी. इतना ही नहीं, मांझी के कुछ कार्यक्रमों में भाग भी लिया, लेकिन यह सिलसिला लंबा नहीं चला. अब वह मांझी के हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के आयोजनों में शामिल नहीं होते हैं. एक बौद्धिक हैं प्रेम कुमार मणि. कभी नीतीश कुमार के अति प्रिय लोंगों की सूची में उनका नाम था. श्री शिवानंद तिवारी के जद (यू) में शामिल होने पर उन्होंने लेख लिख कर नीतीश कुमार को शिवानंद तिवारी से सावधान रहने की सलाह भी दी थी. यह वाकया आठ– नौ साल पुराना है, लेकिन उनसे जद (यू) सुप्रीमो ने उससे पहले ही दूरी बना ली थी और अंत में दल विरोधी गतिविधियों के कारण उनकी विधान परिषद की सदस्याता भी समाप्त हो गई. वह राजद से तत्कालीन समता पार्टी में गए थे, लालू प्रसाद को खूब भला–बुरा कहा था. अब एक बार फिर लालू प्रसाद ने अपने दल में तो उन्हें शामिल कर लिया है, पर उनकी कोई राजनीतिक भूमिका तय नहीं की है.

ऐसे ही नामचीन लोगों में रंजन प्रसाद यादव भी हैं. वर्षों तक लालू प्रसाद के सबसे करीबी थिंक टैंक रंजन प्रसाद यादव के सितारे भी गर्दिश में हैं. लालू प्रसाद और बाद में राबड़ी देवी के राज के आरंभिक वर्षों में बिहार के विश्वविद्यालयी और स्कूली शिक्षा के भाग्यविधाता के तौर पर चर्चित रंजन प्रसाद यादव भी खुद को लालू–नीतीश का राजनीतिक गुरु मानते रहे हैं, पर अपनी शरद–भक्ति के कारण बिहार की राजनीति में उन्हें याद करनेवाले कुछ ही लोग बचे हैं. इस शताब्दी के शुरुआती वर्षों में ही लालू प्रसाद के कूचे में ही अपनी हैसियत से बेदखल कर दिए जाने के बाद रामविलास पासवान के साथ हो गए. फिर जद (यू) में आ गए और लोकसभा के सदस्य बने. पिछला चुनाव हारने के बाद उन्हें याद करने के लिए लोगों को जोर डालना पड़ता है. यह सही है कि बिहार में 1991 से लेकर बाद के कई चुनावों में उनका पौ बारह रहा, पर अब लोग उनकी दर की ओर रुख करने भी कतराने लगे हैं. राजनेता के बाद प्रखर साहित्यकार की खुद की पहचान बनानेवाले जाबिर हुसैन तो अब भी राजद के साथ मानते हैं, पर सवाल है कि राजद सुप्रीमो ऐसा मानते हैं या नहीं. राजद सुप्रीमो बहुतों की नोटिस नहीं लेते, शायद जाबिर साहब भी उन्हीं लोगों में हैं. जाबिर साहब विधान परिषद के अध्यक्ष रहे, राजद के नेता रहे, सांसद रहे, पर हाल के वर्षों में उनकी दलीय निष्ठा के बारे राजद के लोग भी भरोसे के साथ कुछ नहीं कह सकते. श्री हुसैन मधुरभाषी और मितभाषी हैं, लेकिन हाल के वर्षों में अखबारनवीसों से दूर रहने लगे हैं. इसलिए राज–पाट और राजनीति से जुड़ी खबरों में बहुधा दिखते नहीं हैं. बिहार के राजनीतिक हलके में एक और नाम है पीके सिन्हा का. पीके सिन्हा गत कुछ वर्षों से भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चला रहे हैं. उनका यह अभियान मुख्यतः राजनीति में ढोंग और पाखंड के खिलाफ है और इसीलिए उन राजनेताओं को उन्होंने अपना निशाना बनाया है, जो खुद को राजनीतिक शुचिता और ईमानदारी के प्रतीक के तौर पर पेश कर रहे हैं. सिन्हा के निशाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे ऊपर हैं. हालांकि समता पार्टी के उस दौर को भी बिहार ने देखा, जब नीतीश कुमार के सबसे प्रिय लोगों के तौर पर पीके सिन्हा को माना जाता था और फिर लोगों ने उस दौर को भी देखा, जब पीके सिन्हा के खिलाफ नीतीश भक्त नित नई रणनीति तैयार करते रहे थे. प्रशासनिक अधिकारी से सोशल एक्टीविस्ट, पत्रकार और राजनेता बने सिन्हा की बिहार के चुनावों में कभी बड़ी भूमिका रही थी, पर अब कोई भूमिका नहीं बची है. हालांकि अभियानों की मदद से चुनाव में अपनी भूमिका वह साबित करना चाहते हैं, पर अपनी इस भूमिका को वह किस हद तक जमीन पर उतार पाते हैं, यह देखना अभी बाकी है.

ये कुछ नाम हैं, जिनकी हाल–फिलहाल तक चुनावों में भूमिका रही. ऐसे लोगों की फेहरिस्त काफी लंबी है, जो अब चुनावी राजनीति में अपनी भूमिका तो चाहते हैं, पर जमीन नहीं मिल रही है. इनमें से अधिकांश राजनेता बिहार की राजनीति में दशकों से सक्रिय रहे हैं–पांच दशक से. उन्होंने सक्रियता से अपनी पहचान बनाई है, पर अब राजनीति के रंग–ढंग बदल गए हैं. कुछ लोगों को छोड़ दें तो अधिकांश लोग उस दौर की राजनीति की उपज हैं, जब राजनीति में धन की वक़त उतनी ही थी, जितनी इसकी जरूरत समझी जाती थी. उन दिनों राजनीति में संघर्ष और कार्यक्रम का जोर हुआ करता था. जन संघर्ष और कार्यक्रम जन–गोलबंदी के आधार होते थे, धन नहीं. उस दौर में राजनीति सामुहिकता की उपज हुआ करती थी, सुप्रीमो का उदय नहीं हुआ था. मौजूदा दौर में हालात पूरे बदल गए हैं. राजनीति धन केन्द्रित हो गई है और सुप्रीमो–संस्कृति से यह ओत–प्रोत है. अब नेतृत्व के विचार से असहमति का अर्थ दल का विरोध है. ऐसे में दलों में नेता एक ही होता है और नेता (सुप्रीमो) कहे दिन तो दिन, नेता कहे रात तो रात. इसलिए हर पार्टी में सुप्रीमो के बाद की कुर्सी बड़ी महत्वूर्ण हो गई है और नेता जी को छोड़ कर बाकी लड़ाई इसी दो नम्बर की कुर्सी की हो गई है. ऐसे में किसी गैर सुप्रीमो की राजनीतिक भूमिका इस पर निर्भर है कि उसकी कुर्सी किस नम्बर पर है. कुर्सी का स्थान परिवर्त्तन किसी नेता की राजनीतिक वक़त का पैमाना हो गया है और इसी से किसी की भूमिका भी तय होती–वह चुनाव ही क्यों न हो. इसलिए जब स्थान ही नहीं रहा, तो भूमिका क्या रहेगी. पहले नगरी मिले, फिर तो कोई राजा बनेगा. राजनीति में अब दास–भाव का बोलबाला बढ़ता जा रहा है. राजनीति में इस बढ़ते दास–भाव को एक घटना बेहतर तरीके से अभिव्यक्त करती है. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पूर्वी चम्पारण जिले के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव (जसोली जमुनिया) में एक पूर्व विधायक की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे. अनावृत प्रतिमा पर माल्यार्पण और सभा मंच से उतरने के बाद जूते पहनने के लिए उन्हें कसरत करनी पड़ती. यह उनके लिए परेशानी का सबब था. परेशानी की बात उनके मुंह से निकलते ही एक पूर्व विधान पार्षद समेत कई नेता उनके पांव पर झुक गए–जूते पहनाने में बाज़ी मार लेने की होड़ मच गई. यह जानना जरूरी नहीं है कि जूते पहनाने का सौभाग्य अंततः किसे मिला. यह जानकारी देना मेरा अभिष्ट भी नहीं है. मैं तो केवल यह इंगित करना चाहता हूं कि गरीबों–पिछड़ों की राजनीति के नायक किस हद तक सामंत हो गए हैं और इस सामंती आचरण के सार्वजनिक प्रदर्शन में उन्हें कोई संकोच भी नहीं होता. ऐसे में सुप्रीमो से अलग राजनीति और समाजिक मुद्दों पर अपनी निजी राय रखनेवालों की क्या वक़त होगी, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है.■

सरकारी निष्क्रियता का परिणाम

महंगाई बेलगाम

पिछले कुछ वर्षों से महंगाई ने जैसे देश में अपना आशियाना सा बना रखा है. सरकार का न तो बाजार पर कोई नियंत्रण है और न ही जमाखोरों पर. सरकार की निष्क्रियता का ही परिणाम है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें नई ऊंचाइयों पर पहुंच गईं हैं. सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए, जिससे बाजार और खाद्य वस्तुओं की कीमतें नियंत्रण में रहें, ताकि आम आदमी को महंगाई से राहत मिल सके. सही मायने में देखा जाए तो खाद्य वस्तुओं की कीमतों में इस तरह की तेजी देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है. इससे अर्थव्यवस्था में असंतुलन की स्थिति पैदा हो सकती है.

राजीव रंजन

नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन हैरानी इस बात की है कि सरकार बनने के बाद जब पहला बजट पेश किया गया, तो बजट में महंगाई से निपटने का कोई जिक्र तक नहीं था. सत्य तो यह है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, उसके लिए महंगाई कोई मुद्दा है ही नहीं, जबकि सत्ता में आने से पहले कोई भी पार्टी महंगाई पर नियंत्रण अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करती नजर आती है. मोदी ने भी सरकार बनने के बाद संसद के पहले सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिये कहा था कि महंगाई पर काबू पाना उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी, लेकिन मोदी सरकार वास्तविकता से कोसों दूर चली गई. सही मायने में देखा जाए तो इस सरकार ने रेल किराये, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने के साथ ही महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. सवाल यह उठता है कि अगर मोदी सरकार महंगाई पर नियंत्रण को लेकर गंभीर है, तो वह यह बताए कि उसने महंगाई को बढ़ाने वाले कितने जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ कार्रवाई की या उन्हें गिरफ्तार किया? सच तो यह है कि मोदी सरकार के ही केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बयान देते हैं कि पश्चिमी भारत में सूखे के हालात बन रहे हैं और मध्य भारत में भी बारिश 50 फीसदी से ज्यादा कम हो जाएगी. अब जब भारत सरकार के मंत्री ही पश्चिमी भारत में सूखे की एडवांस घोषणाएं करेंगे, तो पश्चिम भारत के राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात आदि में जमाखोरी बढ़ने का खतरा तो पैदा होगा ही. मंत्री जी की घोषणा के बाद यह तय है कि उन इलाकों से आने वाली पैदावार की कीमतों में इजाफा होगा और देश में अधिक महंगाई बढ़ेगी. लोगों का मानना है कि

सब्जियों की कीमतें आसमान पर

कुछ राज्यों में सब्जियों की कीमतों पर हम नजर डालें तो पाएंगे कि पिछले कुछ दिनों में सब्जियों की कीमतों में 70 से 72 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. देश की राजधानी दिल्ली-एनसीआर में भिंडी, करेला और तोरी 100 रुपये किलो की दर से बिक रही है, जबकि लौकी 60 रुपये किलो बिकने लगी है. प्याज 30 रुपये प्रति किलो से उछाल मारकर 40 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है. मटर और टमाटर भी 40 रुपये किलो बिक रहा है. अहमदाबाद में भिंडी की कीमत 100 रुपये किलो पर पहुंच गई है. जम्मू में भिंडी 80 रुपये किलो बिक रही है, जबकि टमाटर 40 रुपये, मटर 25 रुपये, करेला 85 रुपये, बैंगन 35 रुपये किलो बिक रहा है. जयपुर में अरबी की कीमत 40-60 रुपये पर पहुंच गई है. करेला भी 60 रुपये किलो मिल रहा है, जबकि भिंडी एक हफ्ते में 40 से 70 रुपये प्रति किलो की कीमत पर पहुंच गई है. एशिया की सबसे बडी सब्जी मंडी आजादपुर में इन दिनों आलू का थोक रेट 5 रुपये प्रति किलोग्राम है और खुदरा में यह रेट 10 से 12 रुपये प्रति किलोग्राम है, लेकिन आनेवाले 15 से 20 दिनों में मंडी में आलू की फसल का अंतिम हिस्सा समाप्त हो जाएगा. व्यापारियों के अनुसार, आलू के दाम थोक में 20 रुपये प्रति किलाग्राम और खुदरा में 35 पर रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकते हैं.

जमाखोरों पर लगाम जरूरी

सरकार को पहले जमाखोरी की मंशा और मतलब समझना होगा. सच पूछा जाए तो सरकार चाहती ही नहीं है कि जमाखोरी पर नियंत्रण हो. यही कारण है कि सरकार के हाथ बड़े जमाखोरों या बड़े स्टॉक रखने वाली कंपनियों के गिरेबान तक नहीं पहुंच पाते. सरकार कार्रवाई करती भी है, तो छोटे दुकानदारों या जमाखोरों पर, जबकि सरकार की सख्ती बड़े और छोटे जमाखोरों पर समान रूप से होनी चाहिए. दूसरी बात कि सरकार को यह नीति भी साफ करनी होगी कि जमा किस हद तक होनी चाहिए. यानी उसकी लिमिट तय कर दे सरकार.

जमाखोरों की पनाहगार बनीं मंडियां

आखिर मंडी व्यवस्था को सरकार निरस्त क्यों नहीं कर देती. बड़े जमाखोरों के लिए ये मंडियां पनाहगार बन चुकी हैं. मंडी समिति क़ानून असल में जमाखोरी से बचाने के लिए बना था, लेकिन इसके तहत जिसे लाइसेंस मिला, वे जमाखोरी कर रहे हैं. किसान मंडी के अलावा बाहर बाज़ार में किसी को बेच नहीं पाता. असल में व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि किसान अपना सामान सीधे बाज़ार में बेच दे, लेकिन होता इसके उलट है. यही कारण है किसी भी क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित सोची-समझी नीति के तहत की जाती है, क्योंकि इससे उस क्षेत्र के किसानों को अतिरिक्त पैकेज मिलने की संभावना प्रबल हो जाती है.

केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान कहते हैं कि आलू और प्याज के जो दाम बढ़ रहे हैं, वो जमाखोरी की वजह से बढ़ रहे हैं. मंत्री जी को बेतुके बयान देने की बजाय जमाखोरों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.

पहले यह कहा जाता था कि दिल्ली में सब्जियां इसलिए महंगी हैं, क्योंकि कोलकाता, सिलीगुड़ी और राजस्थान के कुछ स्थानों से यहां सब्जियां आती हैं, लेकिन आज दिल्ली और आस-पास खूब सब्जियों की पैदावार हो रही है. फिर भी सब्जियों के दाम कम नहीं हो रहे हैं. इसके पीछे प्रमुख कारण है कि जमाखोरों ने कृत्रिम अभाव पैदा किया है. बड़े-बड़े पूंजीपति किसानों से सब्जी खरीदकर कोल्ड स्टोरेज में रख लेते हैं और जब दाम बढ़ता है, तब निकालते हैं. महंगाई के कारणों पर डालते हैं एक नज़र.

बेमौसम बारिश का कहर देश के कई राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र के रबी फसलों पर पड़ा है. उत्तर प्रदेश में आलू की 70 फीसदी और गेहूं की 50 फीसदी फसल बर्बाद हो गई है. मध्यप्रदेश में 15 जिलों की 1400 गांवों की पूरी फसल तबाह हो गई है. राजस्थान के 26 जिलों में फसल को भारी नुकसान पहुंचा है. महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में भी नुकसान हुआ है और 8000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है. एक अनुमान के अनुसार 50 लाख एकड़ भूमि में रबी की फसल बर्बाद हो गई है. उत्तर प्रदेश में करीब 2 लाख एकड़, महाराष्ट्र में 7.5 लाख एकड़, राजस्थान में 14.5 लाख एकड़, पश्चिम बंगाल में 50,000 एकड़ और पंजाब में 6000 एकड़ में फसल बर्बाद हो गई है. फसलों की बर्बादी भी महंगाई के लिए जिम्मेदार है.

कि जो सामान मंडी में 5 रुपये किलो मिलती है, वही मंडियों के बाहर 15 रुपये किलो. सरकार की यह नीति गलत तरीके से बाजारवाद को बढ़ावा देती है. जमाखोरों का हौंसला इतना अधिक बढ़ गया है कि मंडियों में आए सामान का भाव वे गुप-चुप तरीके से तय करते हैं. सामान का भाव तय करने की कोई नीति ही नहीं है.

स्टोरेज की समस्या

सरकार के पास न तो गोदाम पर्याप्त हैं और न ही कोल्ड स्टोरेज. जो गोदाम हैं, वो चावल और गेहूं से भरे पड़े हैं. इसलिए सब्जियों या अन्य खाद्यानों के स्टोरेज की समस्या बनी रहती है. सरकार की इन नीतियों का फायदा यहां जमाखोर उठाते हैं और प्राइवेट गोदामों या कोल्ड स्टोरेज का प्रयोग कर जान-बूझकर उपभोक्ता से अधिक कीमत लेने के लिए सामान को दबा देते हैं, ताकि बाजार में वे सामानों का कृत्रिम अभाव पैदा कर सकें. महंगाई बढ़ने का दूसरा कारण यह है कि खाद्यानों का संतुलित उत्पादन नहीं हो रहा है. चावल-गेहूं अधिक हैं, तो दलहन-तिलहन खपत से कम. इसलिए आयात करना पड़ता है, जो देशी बाजारों में आते-आते काफी महंगे हो जाते हैं.

महंगाई के आंकड़े

आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2015 में साल दर साल आधार पर प्याज की कीमत 26.58 प्रतिशत, फलों की कीमत 16.84 प्रतिशत, सब्जियों के दाम 15.54 प्रतिशत तथा दालों के दाम 14.59 प्रतिशत बढ़ गए. इनके अलावा दूध के दाम में 7.33 प्रतिशत तथा चावल के दाम में 3.82 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई. खाद्य पदार्थों में सिर्फ आलू और गेहूं के दाम क्रमश: 3.56 फीसदी और 2.40 फीसदी घटे हैं. इस दौरान पेट्रोल के दाम 21.35 प्रतिशत, डीजल के 16.62 प्रतिशत तथा रसोई गैस के दाम 8.86 प्रतिशत कम हुए. वहीं खनिजों के दाम भी 25.57 प्रतिशत कम हुए. दिसंबर के थोक महंगाई सूचकांक में संशोधन करते हुए इसे 0.11 प्रतिशत से घटाकर 0.50 प्रतिशत ऋणात्मक कर दिया गया है.

सप्लाई नीति में सुधार जरूरी

खाद्य पदार्थों की सप्लाई की समस्या महंगाई बढ़ने के प्रमुख कारण हैं. ज़्यादातर गोदाम शहरों में हैं, जबकि आलू-प्याज़ के गोदाम खेतों के पास होने चाहिए. दिल्ली में पॉश इलाकों में गोदाम बनाना बेमतलब है. आलू-प्याज़ के गोदाम ग्रामीण एरिया या उसके आसपास होने चाहिए. ऐसी व्यवस्था हो कि गोदामों में रखे गए सामानों के बारे में ऑनलाइन जानकारी हासिल हो सके. इससे एकाधिकार या वर्चस्व पर लगाम लगेगा, जिसका फ़ायदा किसान और उपभोक्ता दोनों को होगा.

सरकारें निष्क्रिय

मीडिया में अक्सर यह देखने-सुनने को मिलता है कि केंद्र सरकार जमाखोरी के लिए राज्य सरकारों को दोषी ठहराती हैं और राज्य सरकारें केंद्र को. असल में सरकारों का प्रमुख उद्देश्य जनता को बरगलाना है. सरकारें जमाखोरी को लेकर तनीक भी गंभीर नहीं हैं और उनकी नीयत ठीक नहीं है. ■

feedback@chauthiduniya.com

पार्टी मुख्यालय में डॉ. राम मनोहर लोहिया के नाम पर बने सम्मेलन कक्ष का उद्घाटन करने के बाद मुलायम कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि लोकसभा चुनाव में आपने कहीं का नहीं छोड़ा. अगर हम 40-45 सीटें जीत जाते तो केंद्र में सपा की सरकार होती. कांग्रेस भी समर्थन करती, लेकिन आपलोगों ने सारा सत्यानाश कर दिया. मुलायम ने लोहिया के विचार का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि जिंदा कौमें पांच साल इंतजार नहीं करतीं. आज लोहिया के विचारों को समझने की जरूरत है.

लोहिया जयंती पर मुलायम हुए कठोर

लोहिया जयंती पर कार्यकर्ताओं पर हमला बोलने वाले मुलायम ने लोहिया की पुण्यतिथि पर पिछले साल जनता और कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा था कि सरकार के मंत्रियों की गलती की सजा उन्हें न दी जाए. मुलायम ने डॉ. राममनोहर लोहिया के जीवन की कई मिसाल देते हुए कहा था कि जिस जनता ने आपको बहुमत की सरकार दी है, वह मूर्ख नहीं है. वोटर गरीब या अनपढ़ हो सकता है, लेकिन सत्ता में बैठे नेताओं के आचरण में आने वाले बदलाव को वह समझता है और नाराज होने पर सबक सिखा देता है.

प्रभात रंजन दीन

राजनीति और उम्र की इस दहलीज पर आकर मुलायम सिंह यादव के स्वभाव में लोहिया उतर रहे हैं. अब तक मुलायम की राजनीति पर लोहिया प्रभावी रहे हैं. लोहिया को स्वभाव में उतारना मुलायम की विवशता भी हो सकती है. लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद मुलायम के व्यक्तित्व पर लोहिया के नाम पर सियासत कम, लोहिया का आक्रामक व्यक्तित्व अधिक प्रभावी दिखने लगा है. अखिलेश सरकार के मंत्रियों की जन विरोधी गतिविधियों और उनके भ्रष्टाचार पर लगातार तीखा प्रहार कर रहे मुलायम ने 23 मार्च को लोहिया जयंती के मौके पर यह कह कर लोगों को आश्चर्य में डाल दिया कि पार्टी के नेता उनकी जासूसी कर रहे हैं, उन पर नजर रख रहे हैं. कुछ नेता सीआइडी का काम कर रहे हैं. उनका केवल इतना ही काम रह गया है कि वे इस बात पर नजर रखें कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक उनसे कौन-कौन मिलता है. मुलायम ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी अपना खूब गुस्सा उतारा. मुलायम ने कहा कि सपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी का सत्यानाश कर दिया. 2014 के लोकसभा चुनाव में मिली शर्मनाक हार का गुस्सा समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के चेहरे पर स्पष्ट दिख रहा था. उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र में सरकार बनाने के उनके सपनों पर पानी फेर दिया. पार्टी के सारे नेता और कार्यकर्ता हक्के-बक्के होकर मुलायम का अर्धसत्य सुन रहे थे और बाहर निकल कर कोस रहे थे कि पार्टी को नेताओं ने मिल कर डुबोया और बदनाम कार्यकर्ता हो रहे हैं.

पार्टी मुख्यालय में डॉ. राम मनोहर लोहिया के नाम पर बने सम्मेलन कक्ष का उद्घाटन करने के बाद मुलायम कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि लोकसभा चुनाव में आपने कहीं का नहीं छोड़ा. अगर हम 40-45 सीटें जीत जाते तो केंद्र में सपा की सरकार होती. कांग्रेस भी समर्थन करती, लेकिन आपलोगों ने सारा सत्यानाश कर दिया. मुलायम ने लोहिया के विचार का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि जिंदा कौमें पांच साल इंतजार नहीं करतीं. आज लोहिया के विचारों को समझने की जरूरत है. कार्यक्रम के बाद बाहर निकलते कुछ कार्यकर्ताओं ने मुलायम के वक्तव्य पर चुटकी भी ली, जिंदा कौमों ने पांच साल कहां इंतजार किया, यूपी में सरकार बनने के दो साल बाद ही लोकसभा चुनाव में पार्टी को जमीन का अहसास करा दिया. लोकसभा चुनाव में सपा उत्तर प्रदेश में 80 में से केवल पांच सीटें ही जीत पाई, वह भी मुलायम परिवार के ही पांच लोग जीत कर संसद पहुंचे. आजमगढ़ सीट से मुलायम खुद जीते, जबकि उनकी बहू डिंपल यादव, भतीजे धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव व पोते तेज प्रताप सिंह यादव क्रमशः कन्नौज, बदायूं, फिरोजाबाद और मैनपुरी सीटों से चुनाव जीते. पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए मुलायम ने कहा कि पार्टी में चापलूसों की भरमार है. उन्होंने चुनौती देने के अंदाज में कहा कि इस बार यूपी में सरकार नहीं बनी तो अच्छा नहीं होगा. उन्होंने उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार फिर से बनाने के लिए उन्हीं कार्यकर्ताओं से आह्वान भी किया, जिन्हें कुछ ही मिनट पहले सत्यानाशी बताया था. लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार की वजह बताते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि बाबर की 13 हजार की फौज थी, जिसने भारत पर कब्जा कर लिया, क्योंकि उसकी सेना अनुशासित थी, हमारी सेना बंटी हुई थी. अनुशासन में रहेंगे तभी हम चुनाव जीत पाएंगे.

दागदार नेताओं की मौजूदगी में मुलायम ने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी कि अगर वे बेदाग रहेंगे तो लंबी राजनीति कर सकते हैं, वर्ना अब लंबी राजनीति नहीं की जा सकती. मुलायम ने पार्टी कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि वे विपक्षी दलों के दुष्प्रचार से सतर्क रहें. मुलायम ने कार्यकर्ताओं को कुछ लिखने-पढ़ने की भी सलाह दी. मुलायम बोले कि सम्मेलनों-बैठकों में कार्यकर्ता न तो कुछ लिखते हैं और न ही उन्हें पार्टी संविधान और घोषणापत्र की कोई जानकारी है. सबको पार्टी संविधान और 2012 के विधानसभा चुनावों के लिए तैयार पार्टी का घोषणापत्र पढ़ना चाहिए. जनता को बताना चाहिए कि सपा सरकार ने क्या किया है और किस तरह उसने अपने सभी चुनावी वायदे पूरे किए हैं. मंत्रियों को अपने स्वार्थ और अपनी प्रशंसा से ही फुर्सत नहीं रहती. वे सरकार के काम के बारे में लोगों को क्या बताएंगे. मुलायम ने कहा कि मंत्रियों को तो पार्टी के संविधान तक की जानकारी नहीं है. उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पुत्र अखिलेश यादव पर भी कड़ा प्रहार किया. यह भी कहा कि वे जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब मुंबई में चार-चार विधायक हुआ करते थे. कर्नाटक में भी दो विधायक होते थे, लेकिन अब तो पार्टी यूपी के अंदर ही सिमट कर रह गई है.

पिछले साल अक्टूबर महीने में हुए पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में मुलायम ने कहा था कि अखिलेश सरकार के कुछ मंत्री जनहित में काम नहीं कर रहे हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं. मंत्रियों ने जनता का काम नहीं किया और केवल व्यक्तिगत लाभ उठाया. उन मंत्रियों और कुछ विधायकों का कच्चा-चिट्ठा उनके पास है. मुलायम ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सतर्क करते हुए कहा था कि जनता से दूरी बनाओगे तो खुद खत्म हो जाओगे. जनता की उपेक्षा न करें. जनता अपनी उपेक्षा कभी नहीं भूलती. उपेक्षा करने वाले मंत्रियों को जनता सबसे पहले हराती है. पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल ने भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से कहा था कि मंत्री कोई काम नहीं कर रहे हैं, उनके काम-काज का हिसाब लिया जाना चाहिए, लेकिन इन नसीहतों का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर कोई असर नहीं पड़ा. मंत्रियों की भ्रष्ट गतिविधियां उसी तरह जारी हैं. मुलायम ने हर मौके पर अखिलेश सरकार को आगाह किया और सार्वजनिक प्रहार करने से कभी नहीं चूके. उन्होंने यहां तक कहा कि सरकार में चापलूस राज कर रहे हैं. मंत्री और अफसर सब इन्हीं से घिरे हैं. कुछ मंत्री तो पूरी सरकार को बहका रहे हैं. मुलायम ने अखिलेश को चाटुकारों से दूर रहने की सलाह भी दी थी, लेकिन चाटुकारों का मोह कौन नेता त्याग पाता है.

लोहिया जयंती पर कार्यकर्ताओं पर हमला बोलने वाले मुलायम ने लोहिया की पुण्यतिथि पर पिछले साल जनता और कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा था कि सरकार के मंत्रियों की गलती की सजा उन्हें न दी जाए. मुलायम ने डॉ. राममनोहर लोहिया के जीवन की कई मिसाल देते हुए कहा था कि जिस जनता ने आपको बहुमत की सरकार दी है, वह मूर्ख नहीं है. वोटर गरीब या अनपढ़ हो सकता है, लेकिन सत्ता में बैठे नेताओं के आचरण में आने वाले बदलाव को वह समझता है और नाराज होने पर सबक सिखा देता है.

मुलायम के आक्रामक तेवर के कारण लोहिया की 105वीं जयंती याद रखी जाएगी. समाजवादी पार्टी ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर लोहिया जयंती समारोहों का आयोजन किया था. मुख्य समारोह लखनऊ में गोमती नगर स्थित डॉ. लोहिया पार्क में हुआ, जहां डॉ. लोहिया की मूर्ति पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव, मंत्री शिवपाल सिंह यादव समेत अन्य नेताओं ने माल्यार्पण किया. इस अवसर पर प्रो. राम गोपाल यादव की किताब डॉ. लोहिया और उनका समाजवाद, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की पुस्तिका- पूरे हुए वादे, अब हैं नए इरादे और दीपक मिश्र की किताब-लोहिया, मुलायम व समाजवाद का विमोचन भी हुआ.

इस मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के विकास का उल्लेख किया. समारोह में विधानसभाध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय, वरिष्ठ मंत्री शिवपाल सिंह यादव, पूर्व वरिष्ठ नेता भगवती सिंह, राष्ट्रीय महासचिव किरनमय नन्दा, राज्यसभा सांसद जया बच्चन, रंजना बाजपेयी शादाब फातिमा, अहमद हसन, बलराम यादव, राजेन्द्र चौधरी, डॉ. अशोक बाजपेयी, अवधेश प्रसाद, अरविन्द सिंह गोप, डिम्पल यादव, नरेश उत्तम, राम आसरे विश्वकर्मा, डॉ. मधु गुप्ता, सरोजनी अग्रवाल, राज किशोर मिश्र, रामवृक्ष यादव, जयप्रकाश अंचल, डॉ. हीरा ठाकुर, आशु मलिक, विजय यादव, गीता सिंह, गायत्री प्रसाद प्रजापति, एसआरएस यादव, मनोज पांडेय, सुनील यादव, डॉ. राजपाल कश्यप, राम सागर यादव, आनन्द भदौरिया, बृजेश यादव, मो. एबाद, सोनम सिंह यादव और खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की उल्लेखनीय उपस्थिति रही.■

नेताजी को याद आए अमर

लोहिया जयंती के मौके पर अखिलेश सरकार के मंत्रियों और कार्यकर्ताओं को आड़े हाथों लेते वक्त सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को अमर सिंह खूब याद आए. मुलायम ने अमर सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा कि अमर सिंह हमेशा सही बोलते थे. अमर सिंह पूरी तैयारी के बाद ही बोलते थे. उन्हें चीजों की सही-सही जानकारी रहती थी. वे पढ़ते थे और पूरी जानकारी लेने के बाद ही उसे सामने रखते थे. मुलायम ने कहा कि पार्टी में अब ऐसे नेता नहीं हैं.

अब व्हाट्स-ऐप से समाजवाद सिखाएंगे अखिलेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व्हाट्स-ऐप की तर्ज पर समाजवाद-ऐप लाएंगे. अखिलेश प्रदेश के युवाओं को व्हाट्स-ऐप के जरिए समाजवाद सिखाएंगे. लोहिया के शिष्य मुलायम सिंह यादव से समाजवाद की सीख प्राप्त करने में चूके अखिलेश लोहियावाद की गंभीरता को मोबाइल फोन के माध्यम से सरलीकृत करेंगे. लोहिया जयंती पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को नारेबाजी से ज्यादा लोहिया के विचारों पर ध्यान देने की नसीहत दी और बोले कि जल्दी ही समाजवादी पार्टी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए युवाओं तक समाजवादी पार्टी की नीतियों और योजनाओं को पहुंचाएगी. युवाओं को व्हाट्स-ऐप के जरिए समाजवादी सिद्धांतों के बारे में बताया जाएगा. अखिलेश ने कहा कि डॉक्टर लोहिया के विचार समाजवादी थे. उन्होंने अपने समाजवादी विचारों से देश की सेवा की. सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने लोहिया के समाजवादी विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया. अखिलेश ने कहा कि समाजवादी विचारधारा के लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि कैसे लोहिया के विचारों से देश और पार्टी आगे बढ़े. ■

समाजवादियों को शहीदों की याद नहीं आई

23 मार्च, बलिदान व समाजवाद की एक यादगार प्रेरक तारीख है. 1910 में 23 मार्च के ही दिन समाजवाद को नई परिभाषा देने वाले डॉ. राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ था. डॉ. लोहिया के जन्म के मात्र पांच वर्ष बाद 23 मार्च, 1915 को भारत की आज़ादी के लिए छेड़े गये फरवरी विप्लव के कथित अपराधी रहमत अली, दुढू खान, गनी खान, सूबेदार चिश्ती खान और हाकिम अली को मलय-सिंगापुर में वतन परस्ती के जुर्म में गोली से उड़ा दिया गया. 23 मार्च, 1931 को ही बलिवेदी पर भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव फांसी पर चढ़ा दिये गये थे. वर्ष 1988 में 23 मार्च के ही दिन क्रांति के गीत लिखने वाले अवतार सिंह पाश को आतंकवादियों ने गोलियों से भून दिया. इन ऐतिहासिक घटनाओं ने 23 मार्च को प्रेरणाश्रोत तारीख बना दिया, लेकिन डॉ. लोहिया की लखनऊ में भव्य जयंती मनाने वाले समाजवादियों को 23 मार्च के उन शहीदों की याद नहीं आई, जो जंग ए आज़ादी की बलिवेदी पर हंसते-हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर इस दुनिया से विदा हो गए. ■

- अरविन्द विद्रोही

लोहियावादियों और अंबेडकरवादियों की ढुलमुल राजनीति

उत्तर प्रदेश की लोहियावादी पार्टी सपा और अंबेडकरवादी पार्टी बसपा, दोनों ही ढुलमुल राजनीति पर चल रही है, इसीलिए जनता के बीच पकड़ खोती जा रही है. यूपीए के कार्यकाल में दोनों पार्टियां कांग्रेस का साथ देती रहीं और प्रदेश में कांग्रेस विरोध की सियासी नौटंकी मंचित करती रहीं. अब केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद सपा और बसपा ने अपना पैंतरा फिर बदल दिया है. प्रदेश में भाजपा की खूब लानत-मलामत होती है, लेकिन केंद्र में ये दोनों पार्टियां भाजपा सरकार का साथ दे रही हैं. मोदी सरकार ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सहयोग से अपने दोनों महत्वपूर्ण बिल कोयला और खनन बिल पास करा लिए. राजग के पास राज्यसभा में इन बिलों को पास कराने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं था, लेकिन सपा और बसपा के चलते उनका काम बन गया. इससे यह साफ हो गया है कि ये दोनों पार्टियां भले ही विपक्ष में हों, लेकिन ठीक उसी तरह भाजपा सरकार की संकटमोचक बनी हैं, जैसे कांग्रेस सरकार के लिए थीं. सपा और बसपा ने कई महत्वपूर्ण मौकों पर कांग्रेस का साथ देने के अलावा अहम बिलों को पास कराने में भी यूपीए सरकार का साथ दिया था. 2008 में अमरीका के साथ परमाणु संधि के दौरान सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह ने ऐन मौके पर कांग्रेस का समर्थन किया था. उस समय कांग्रेस नाजुक स्थिति में थी. अब भाजपा को समर्थन देने के बाद यह स्थापित हो गया कि दोनों पार्टियां केंद्रीय सत्ता से अलग रह ही नहीं सकतीं. इन बिलों पर भाजपा को बिजू जनता दल, तृणमूल कांग्रेस और अनाद्रमुक का भी समर्थन मिला, लेकिन भाजपा सरकार को समर्थन देने की सपा और बसपा की राजनीति का अवसरवादी पक्ष उत्तर प्रदेश के लोगों को हैरान भी करता है और नाराज भी. उत्तर प्रदेश में ये दोनों दल भाजपा को ही अपना मजबूत प्रतिद्वंद्वी दिखाते हैं. पिछले साल लोकसभा चुनावों में भाजपा ने यूपी की 80 में 73 सीटों पर जीत हासिल की थी. सपा पांच सीटें लाई, जबकि बसपा का तो सफाया हो गया था. जानकार यह भी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार को केंद्र से मदद दिलाने और बेटे का सियासी रास्ता साफ रखने के लिए सपा ऐसा कर रही है. बिजली के लिए खनन और कोयला जैसे मसले असलियत में कुछ भी नहीं हैं. ■

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

अब बिहार चुनाव की बात. हमें कहा गया कि अमित शाह इसका प्रभार एक बार फिर से खुद ही ले रहे हैं. जाहिर है, वे पार्टी अध्यक्ष हैं, ऐसा करना सही भी है, लेकिन भाजपा के लिए बिहार बहुत आसान नहीं होने जा रहा है. जाहिर है, यहां पर जनता परिवार का अभी भी एक साथ आना बाकी है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, वो भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव से अलग है. लोकसभा के दौरान जनता के सामने प्रधानमंत्री का चयन था. राष्ट्रीय स्तर पर जनता को भाजपा या कांग्रेस का प्रधानमंत्री चुनना था. जाहिर है, जनता कांग्रेस को नहीं चुनती, इसलिए भाजपा को भारी जीत मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव का मसला अलग है.

देश को किस रास्ते पर जाना चाहिए

केंद्रीय बजट को पास करने के क्रम में संसद में बहस जारी है. इस दौरान बजट पर वास्तविक विश्लेषण शुरू हो गया है कि बजट से क्या मिला? विश्लेषक दो नतीजों पर पहुंचे हैं. पहला यह कि राज्यों के लिए बहुप्रचारित फंड के हिस्से को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया है. 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय कर में राज्यों की हिस्सेदारी को बढ़ाने की सिफारिश की थी. जो अच्छी बात है, लेकिन जिस मुद्दे ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया, वह था फंड ट्रांसफर के साथ-साथ बहुत सारी योजनाओं का राज्यों को हस्तांतरित किया जाना. जिसके लिए पहले केंद्र सरकार राज्यों को वित्त मुहैया कराता था. हालांकि ऐसा नहीं है कि राज्यों को खर्च के लिए एक बड़ी राशि नहीं मिलेगी, लेकिन इस राशि के साथ जिन योजनाओं की जिम्मेदारी राज्यों के हिस्से में आयेगी, उसके हिसाब से जो रकम मिलेगी वह कम होगी. बहरहाल, यह एक सही दिशा में उठाया गया क़दम है, क्योंकि इससे जहां राज्य फंड के इस्तेमाल के लिए स्वतंत्र होंगे, वहीं उनके बीच प्रतिस्पर्धा का माहौल भी बनेगा. जिन राज्यों में शासन व्यवस्था अच्छी होगी, वे राज्य अच्छा प्रदर्शन करेंगे और जिन राज्यों में शासन व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, उन्हें नुकसान होगा.

अगर नीतियों का दिल्ली से नियंत्रण करने के बजाए केंद्र सरकार राज्यों को थोड़े और अधिकार दे देती है तो यह सैद्धांतिक तौर पर अच्छी बात है, लेकिन निराश करने वाली बात यह है कि कृषि के लिए अपर्याप्त फंड का प्रावधान किया गया है, इस वजह से हालत कितने विस्फोटक हो सकते हैं, फिलहाल हम समझ नहीं पा रहे हैं. कृषि उपज में वृद्धि जनसंख्या में वृद्धि के अनुसार होनी चाहिए. इसका असर हमें 10 साल बाद दिखेगा, जब हम एक बार फिर खाद्यान्न की कमी महसूस करने लगेंगे, और यही भारत के एक शक्तिशाली अर्थव्यवथा बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा साबित होगा. अभी भी समय है कि वित्त मंत्री इस पर पुनर्विचार करें और कृषि के लिए अतिरिक्त फंड मुहैया करवाएं और इस क्षेत्र में दीर्घकालिक पूंजी निवेश की व्यवस्था करें. खाद्यान्न की कमी का एहसास इस साल या आने वाले एक-दो सालों में नहीं होगा. क्योंकि फिलहाल हमारे पास खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है. चीनी उद्योग पूरी तरह कृषि पर आश्रित है और सरकार के लिए यह एक गंभीर समस्या बनने जा रहा है. यदि किसानों को उनका पैसा नहीं मिला तो चीनी मिलों के पास इतना भी पैसा नहीं होगा कि वे गन्ने से चीनी बना सकें. इसलिए किसानों का बकाया लगातार बढ़ता जाएगा. इस मुद्दे पर रंगराजन कमेटी का गठन किया गया था. कमेटी ने गन्ने की कीमत को चीनी के बाजार भाव के आधार पर निर्धारित करने का सुझाव दिया था. राज्यों के बजाए कृषि मंत्री, खाद्य मंत्री और वित्त मंत्री को एक कमेटी का गठन करना चाहिए, जो एक ऐसा फार्मूला बनाए, जिससे कीमतों का निर्धारण हो, ताकि यह उद्योग बन्द न हो.

अब बजट के आगे की बात. एक अफवाह फैलाई जा रही है कि यह सरकार पिछली सभी सरकारों से अधिक पैसा खर्च करने जा रही है. इसमें ऐसी कौन सी अनोखी बात है. हर साल ये आंकड़े बढ़ जाते हैं. हर साल का बजट पिछले साल के बजट की तुलना में अधिक पैसे का प्रावधान करता है. सरकार ने इंफ्रास्ट्रकचर के बारे में जितनी बातें की इसके लिए उतना

सामाजिक मोर्चे पर कुछ चिंताजनक बातें हैं. चर्च जलाए जा रहे हैं. पत्थरबाजी हो रही है. लोग डर के साये में जी रहे हैं. खास तौर से क्रिश्चियन समाज के लोग. इन सब को कैसे जायज ठहरा सकते हैं? हालांकि, प्रधानमंत्री ने कहा कि हर कोई अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन संघ परिवार समूह यह सब नहीं समझता और वे भय का वातावरण बनाना चाहते हैं, बिना यह समझे कि इससे केन्द्र सरकार को ही नुकसान पहुंचेगा.

प्रावधान बजट में नहीं किया. अब एफडीआई और विदेशी कंपनियों के आने की बात कर रही है लेकिन पब्लिक सेक्टर में विवेश की बैत हो सकती थी लेकिन सरकार ने बजट में इस संदर्भ में कोई बात नहीं की. बजट में रेल अथवा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश की कोई ठोस बात बजट में नहीं है जैसा कि सरकार अब तक कहती आई है. सरकार की नीति क्या है, इसे बताया जाना चाहिए, ताकि लोगों को यह महसूस हो कि कुछ होने वाला है या होने जा रहा है.

सामाजिक मोर्चे पर कुछ चिंताजनक बातें हैं. चर्च जलाए जा रहे हैं. पत्थरबाजी हो रही है. लोग डर के साये में जी रहे हैं. खास तौर से क्रिश्चियन समाज के लोग. इन सब को कैसे जायज ठहरा सकते हैं? हालांकि, प्रधानमंत्री ने कहा कि हर कोई अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन संघ परिवार समूह यह सब नहीं समझता और वे भय का वातावरण बनाना चाहते हैं, बिना यह समझे कि इससे केन्द्र सरकार को ही नुकसान पहुंचेगा.

कैग ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाने को लेकर एक रिपोर्ट दिया है. कांग्रेस ने हमेशा की तरह कहा है कि इसमें वाड्रा का नाम नहीं लिया गया है. इससे क्या फर्क पड़ता है? स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी का नाम रिपोर्ट में आया है. यह किसकी कंपनी है? कांग्रेसी शायद कभी नहीं सीखेंगे. अब हरियाणा सरकार वाड्रा के साथ क्या करेगी, हमें नहीं मालूम.

अगर वाड्रा की गिरफ्तारी के मामले में कोई आपसी सहमति बन गई हो, तो कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन यदि कानून अपना काम करता है, तो वाड्रा को बहुत सारी बातों का जवाब देना होगा, क्योंकि ये सामान्य प्रक्रिया है. भूमि का अधिग्रहण किस उद्देश्य के लिए किया गया, यह साफ नहीं है. जमीन पहले वाड्रा को मिली, फिर इसे डीएलएफ को दे दिया गया. यह सब कॉरपोरेट वर्ल्ड की सन्देहास्पद बातें हैं और वाड्रा को अपने संपर्कों के साथ यह बताना होगा कि कैसे वह इतने पैसे वाले बन गए. वाड्रा के अलावा सिर्फ वाईएस जगन रेड्डी ही ऐसे है, जो इतने कम समय में इतना अधिक पैसा कमा सके. यह उनके पिता वाईएसआर की वजह से हुआ और वाड्रा इसलिए, क्योंकि उनकी सास सोनिया गांधी हैं. यह एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है. छोटी-मोटी हेराफेरी तो ठीक है, लेकिन एक सीमा के बाद यह सब सहनीय नहीं है. इन सब की विशेष जांच होनी चाहिए.

अब बिहार चुनाव की बात. हमें कहा गया कि अमित शाह इसका प्रभार एक बार फिर से खुद ही ले रहे हैं. जाहिर है, वे पार्टी अध्यक्ष हैं, ऐसा करना सही भी है, लेकिन भाजपा के लिए बिहार बहुत आसान नहीं होने जा रहा है. जाहिर है, यहां पर जनता परिवार का अभी भी एक साथ आना बाकी है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, वो भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव से अलग है. लोकसभा चुनाव के दौरान लोगों के सामने प्रधानमंत्री का चयन था. राष्ट्रीय स्तर पर जनता को भाजपा या कांग्रेस का प्रधानमंत्री चुनना था. जाहिर है, जनता कांग्रेस को नहीं चुनती, इसलिए भाजपा को भारी जीत मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव का मसला अलग है. बिहार में भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है. बिहार के निर्विवादित नेता नीतीश कुमार ही हैं. अब भाजपा के पास क्या रास्ता है? क्या वह किरण बेदी की तरह किसी को सीएम उम्मीदवार बनाएगी या किसी पुराने नेता को सामने लेकर आएगी? कहा नहीं जा सकता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अमित शाह अपना बेहतर देंगे. जाहिर तौर पर धर्मनिरपेक्ष ताकतों को अब कमर कस लेना चाहिए और अपना बेहतर देने के लिए तैयार रहना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि यह देश आगे किस दिशा में जाए और कैसे जाए? क्या हमें डर, खौफ फैलाने वाले संघ परिवार के रास्ते पर चलना है या संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक वास्तविक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी रास्ते पर जाना है. ■

feedback@chauthiduniya.com

विक्रम मल्लाह और फूलन देवी-5

औरत फिर बनी मौत की वजह

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं. नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

छोटेलाल मिश्रा के जेल जाने के बाद उसके छोटे भाई सियाराम ने बदले की भावना से उन व्यक्तियों के विरोध में गुस्सा प्रगट करना प्रारंभ कर दिया. कुछ लोगों ने सियाराम से कहा कि एक आपसी व्यक्ति ही तुम्हारे भाई के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है. अत: सियाराम का सारा ध्यान अब इसी आदमी पर केंद्रित हो गया. लेकिन, इस तथाकथित व्यक्ति के भाइयों ने एक दुश्चक्र रचकर, उसके दो बच्चों और सियाराम को मौत के घाट उतार दिया. छोटेलाल को जेल में जब यह ख़बर लगी, तो वह बेचैन हो गया. फिर भी वह शांति से जीना चाहता था. पर इसके लिए कोई दिशा नहीं बन पा रही थी. उसके रिश्तेदार ही प्रयत्न कर रहे थे कि उसकी जमानत न हो. अंत में छोटेलाल की जमानत हो गई. वह सामान्य तरीके से रहने लगा. गांव के आदमियों को यह भी मंजूर नहीं हुआ. छोटेलाल के विरोधियों ने पुलिस व बदमाशों से साठगांठ कर उसे मरवाने के षड्यंत्र किए. बाध्य होकर छोटेलाल बीहड़ों में भाग गया तथा वहां जाकर गब्बर सिंह व माया से मिल गया.

गब्बर विशुद्ध अपराधी वृत्ति का युवक था व माया भी उसी स्वभाव की थी. फलस्वरूप गिरोह में विकृतियां पैदा होने लगीं. एक वक्त ऐसा आया, जब छोटेलाल मिश्रा, माया व गब्बर के अतिरिक्त सभी लोग घनश्याम के गिरोह में जा मिले. किंतु गब्बर शेष लोगों से अलग था, बहुत दुष्ट, खूंखार, दूसरों की पीड़ा में आनंद लेने वाला तथा अबोध बालिकाओं से बलात्कार का शौकीन. इसी वजह से वह एक दिन छोटेलाल मिश्रा द्वारा मार दिया गया. गब्बर के मरने के बाद छोटेलाल मिश्रा उसकी राइफल लेकर समर्पण का प्रयास करने लगा. इसी सिलसिले में वह जमुना के किनारे दो महीने तक रहा. फिर वह हाज़िर होने के लिए उरई की तरफ़ अपने संबंधियों सहित बढ़ने लगा. पर पुलिस के इरादे कुछ और थे. वह उसकी हत्या करने की कोशिश में थी. फलस्वरूप समर्पण की बात भूल छोटेलाल मिश्रा विक्रम से जा मिला. इसी बीच विक्रम के गिरोह में भी फूलन को लेकर तनाव बढ़ चुका था तथा विक्रम के साथी भारत सिंह ने अलग गिरोह बना लिया था. विक्रम छिपता फिर रहा था, किंतु उसके भाग्य व पुलिस की बेवकूफी से छोटेलाल मिश्रा जैसा दुस्साहसी आदमी विक्रम को मिल गया. फूलन व विक्रम अब अपने को सबल समझने लगे. दो-चार डकैतियों में तो विक्रम ने खुली घोषणा की, याद रखो पुलिस वालों, मुझे कमजोर न समझो, अब छोटेलाल मिश्रा मेरे साथ है.

विक्रम, फूलन व छोटेलाल ने दो बार समर्पण करने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. निराशा के अतिरेक में आकर इन तीनों का

गब्बर विशुद्ध अपराधी वृत्ति का युवक था व माया भी उसी स्वभाव की थी. फलस्वरूप गिरोह में विकृतियां पैदा होने लगीं. एक वक्त ऐसा आया, जब छोटेलाल मिश्रा, माया व गब्बर के अतिरिक्त सभी लोग घनश्याम के गिरोह में जा मिले. किंतु गब्बर शेष लोगों से अलग था, बहुत दुष्ट, खूंखार, दूसरों की पीड़ा में आनंद लेने वाला तथा अबोध बालिकाओं से बलात्कार का शौकीन. इसी वजह से वह एक दिन छोटेलाल मिश्रा द्वारा मार दिया गया. गब्बर के मरने के बाद छोटेलाल मिश्रा उसकी राइफल लेकर समर्पण का प्रयास करने लगा. इसी सिलसिले में वह जमुना के किनारे दो महीने तक रहा.

गिरोह जमकर डकैतियां डालने और दुश्मनों की हत्याएं करने लगा. सामान्यत: डाकू की मौत या तो पुलिस की गोली से होती है या अपने ही गिरोह के किसी सदस्य के हाथ. विक्रम मल्लाह को दूसरी मौत मिली. वह अपने ही सहयोगी छोटेलाल मिश्रा की गोली का शिकार हो गया. विडंबना यह कि उसकी मौत का बायस बनी

फूलन. वही फूलन देवी, जिसकी खातिर विक्रम ने खुद अपने साथी बाबू गूजर को मौत के घाट उतार दिया था.

दरअसल, छोटेलाल मिश्रा के विक्रम मल्लाह के गिरोह में आ मिलने के बाद गिरोह का समीकरण धीरे-धीरे बदलने लगा. इसका असर फूलन देवी पर भी पड़ा, जो अब काफी महत्वाकांक्षी हो चली थी. छोटेलाल के प्रति उसका रुझान स्पष्ट होने लगा. विक्रम को यह बात कैसे बर्दाश्त हो सकती थी. ताकत के जोर पर सब कुछ हासिल करने की तबीयत स्त्री को भी उसी आधार पर प्राप्त करना चाहती थी. फलत: विक्रम और छोटेलाल के बीच तनाव उभरने लगा. विक्रम अक्सर उसे गालियां देता. कभी-कभी तो फूलन के सामने ही. छोटेलाल के सामने अपनी रणनीति स्पष्ट होने लगी. 27 अप्रैल, 1980 की रात को जब यह गिरोह हमीरपुर की सीमा पर टिका हुआ था, छोटेलाल ने अचानक पाया कि विक्रम अकेला है. फ़ैसले की घड़ी आ गई. छोटेलाल ने गोली दाग दी. फिर छोटे और फूलन वहां से चल दिए. गिरोह के दूसरे सदस्य घायल विक्रम को झांसी ले गए, चिकित्सा के लिए, फिर उन्नाव. लेकिन, विक्रम की हालत बिगड़ती गई. अंतत: 13 मई को विक्रम ने दम तोड़ दिया. उस पर दस हज़ार रुपये का इनाम था. विक्रम की मौत से डाकू आतंक का एक अध्याय समाप्त हो गयाङ्क. *क्रमश:*

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

राजनीतिक तंत्र को ज़िम्मेदार बनाने की ज़रूरत है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, न ही वे आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं और शायद नरेंद्र मोदी इस बात को जानते हैं कि उन्हें अपने को देश के प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करना है. वो इस खतरे से भी वाकिफ हैं कि उनके विरोधी उन्हें हमेशा संघ और भाजपा का प्रधानमंत्री साबित करने में लगे रहेंगे और उनके हर एक क्रियाकलाप को संघ और भारतीय जनता पार्टी के किसी न किसी नीति सिद्धांत से जुड़ा हुआ दिखाते रहेंगे. मेरा ये मानना है कि ये चुनौती भारत में हुए अब तक के किसी प्रधानमंत्री से ज्यादा श्री नरेंद्र मोदी के सामने विकराल रूप में खड़ी है. नरेंद्र मोदी के पास सबसे बड़ी ताकत ये है कि उनके साथ उनके पारिवारिक और परिवार से जुड़े सासाजिक दायित्वों में वक्त जाया करने का खतरा नहीं है.

हाशिमपुरा हत्याकांड के फैसले ने जांच एजेंसियों और न्याय व्यवस्था के साथ-साथ प्रशासनिक संरचना के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. यूं तो ये सवाल सालों पुराने हैं और लोग इनके बारे में बातचीत करते भी रहते हैं, पर ये बातें अनसुनी हो जाती हैं, पर हाशिमपुरा हत्याकांड ऐसा मसला है, जो ये बताता है कि अगर आप सरकार के अंग हैं और आपने अत्याचार किए हैं या हत्याएं की हैं, तो जांच एजेंसियां भी आपकी मदद करेंगी. आप सस्पेंड भी नहीं होंगे. आप गिरफ्तार भी नहीं होंगे. आपके ऊपर जब मुकदमा चलेगा, तो 28 साल के बाद जज साहब यह कह देंगे कि चेहरा तो ढका हुआ था, तुमने चेहरे को कैसे पहचाना, तुमने कैसे कह दिया कि ये वही लोग हैं और केस को खारिज कर देंगे. ये सवाल नहीं उठाएंगे कि पुलिस नये सिरे से इस केस की छानबीन करे और अभी जो जिंदा बचे हुए लोग हैं, उस हत्याकांड के बाद उनसे दोबारा बातचीत कर उस समय के सबूतों को रिक्रिएट कर फिर से जांच हो. न्याय 90 प्रतिशत गरीबों को नहीं मिलता. वो न्याय की अंतिम सीढ़ी तक जा ही नहीं पाते. जहां एक वकील एक पेशी का 4 लाख से 5 लाख रुपये लेता है. चाहे केस की सुनवाई हो या न हो. केस की तारीख पड़ जाए, किसी भी परिस्थिति में उसे चार से पांच लाख रुपये चाहिए. एक केस अगर पांच साल में निपटना है और एक साल में उसकी पांच या दस पेशी होनी है, तो हिसाब लगाया जा सकता है कि इतना पैसा, जिसे न्याय चाहिए, उसे खर्च करना पड़ेगा. क्या इतना पैसा इस देश के 90 प्रतिशत लोगों के पास है? इसका सीधा जवाब है-नहीं. अगर ये पैसा 90 प्रतिशत लोगों के पास नहीं है, तो इसका मतलब उन्हें अंतिम न्याय नहीं मिल सकता. फिर वो न्याय के मकड़जाल में फंस जाते हैं और उन्हें पुलिस, दलाल और अदालत की सेटिंग करने वालों के भरोसे रहना पड़ता है. जाहिर है, इस स्थिति में उन्हें न्याय की जगह अन्याय मिलता है और जो अन्याय करता है, वो ही उपने पक्ष में न्याय का तराजू झुका लेता है.

क्या संसद में बैठे लोगों के लिए वक्त नहीं है? क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों को अब भी नहीं सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था कैसे सक्षम हो? हर एक को न्याय दे और वो सस्ती भी हो. गांव की पंचायत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक न्याय व्यवस्था के संपूर्ण तंत्र को नये तरीके से गठित करने की आवश्यकता है.

हमारी विधायिका और कार्यपालिका में एक रोग लग गया है. उनकी कोई भी योजना दो साल, तीन साल या पांच साल की बनती है और उस दो, तीन और पांच साल में ही वो उस बजट को खर्च करने की कोशिश करती हैं. ऐसी बहुत कम योजनाएं देश में होंगी, जिसे कार्यपालिका ने अगले पचास साल और सौ साल को ध्यान में रखकर बनाया हो. हम देखते हैं कि एक पुल बनता है और दो साल के भीतर ही देखते-देखते वह पुल अपने ऊपर से गुजरने वाली सवारियों के लिए अपर्याप्त हो जाता है. तब पड़ोस में दूसरा पुल बनता है. हम अक्सर देखते हैं कि सड़कें बनीं, साल भर होते ही वो सड़कें टूट जाती हैं. फिर उनकी मरम्मत शुरू हो जाती है और इससे भी मजेदार कि जब सड़कों के किनारे के फुटपाथ छह महीने में ही एक इंच छोटा करने के नाम पर तोड़ दिए जाते हैं.

आजादी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री हुए, सबके सामने ये चुनौतियां रहीं कि कैसे वो तंत्र को संवेदनशील बना सकें और उसे जिम्मेदार भी बनाएं, पर आजादी के इतने साल बाद कोई भी प्रधानमंत्री इसमें सफल नहीं हुआ. तंत्र को संवेदनशील और जिम्मेदार बनाना तो दूर, वो तंत्र को चुस्त भी नहीं कर पाए और इसीलिए हर साल हर अंग पहले से ज्यादा सड़ा दिखाई पड़ता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, न ही वे आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं और शायद नरेंद्र मोदी इस बात को जानते हैं कि उन्हें अपने को देश के प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करना है. वो इस खतरे से भी वाकिफ हैं कि उनके विरोधी उन्हें हमेशा संघ और भाजपा का प्रधानमंत्री साबित करने में लगे रहेंगे और उनके हर एक क्रियाकलाप को संघ और भारतीय जनता पार्टी के किसी न किसी नीति सिद्धांत से जुड़ा हुआ दिखाते रहेंगे. मेरा ये मानना है कि ये चुनौती भारत में हुए अब तक के किसी प्रधानमंत्री से ज्यादा श्री नरेंद्र मोदी के सामने विकराल रूप में खड़ी है. नरेंद्र मोदी के पास सबसे बड़ी ताकत ये है कि उनके साथ उनके पारिवारिक और परिवार से जुड़े सासाजिक दायित्वों में वक्त जाया करने का खतरा नहीं है. वह चौबीसों घंटे देश के भले और भरोसे के लिए सोच सकते हैं. नरेंद्र मोदी ने राजनीतिज्ञों की जगह प्रशासनिक तंत्र को चुस्त बनाने का जिम्मा अपने कंधों पर लिया है. इसलिए अब वो केंद्र सरकार के सचिवों के साथ-साथ प्रदेश के मुख्य सचिवों के साथ सीधा संबंध बैठाना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब तक वो राजनीतिक तंत्र को जिम्मेदार बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये प्रशासनिक तंत्र मजबूत बनाने से उन्हें हासिल कितना होगा, संदेह का विषय है. राजनीतिक तंत्र एक सबसे बड़ा काम ये करता है कि वो नीति बनाने वालों को और नीतियों पर अमल करने वालों को ये बताता है कि आवश्यकता किस बात की है और कैसी योजनाएं बननी चाहिए और दूसरा, उन योजनाओं के ऊपर कुछ अमल हो भी रहा है या नहीं हो रहा है.

अगर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पास यह जानकारी नहीं पहुंचेगी कि देश में करना क्या है और देश में वो जो कर रहे हैं, उसका असर क्या हो रहा है, तो फिर कहीं पर भ्रम पैदा हो जाएगा और भ्रष्टाचार बढ़ने की गुंजाइश ज्यादा हो जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश की समस्याओं को हल करने की मंशा और प्रखरता में कोई संदेह नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संपूर्ण राजनीतिक तंत्र इस सवाल के ऊपर वैसे नहीं सोचता, जैसे खुद प्रधानमंत्री सोचते हैं. प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के सदस्य प्रधानमंत्री के विचारों के साथ अपने को जोड़ नहीं पा रहे. उनके सचिव उन्हें सिर्फ एक शब्द कहते हैं कि पीएमओ की तरफ से यह कहा गया है. नरेन्द्र मोदी जी का आतंक इतना है कि उन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता पीएमओ से यह सवाल नहीं पूछ पाते कि क्या आपने यह हमारे सचिव से कहा है. यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी एक दायरे में घिर गए हैं. उनकी जानकारी का सिर्फ और सिर्फ एक स्रोत टेलीविजन और अखबार हैं, पर उनके पास टेलीविजन देखने और अखबार पढ़ने का वक्त है कहां. उनके सूचना सलाहकार उन्हें कटिंग काटकर देते हैं और वह कटिंग वही होती है, जिसे वो सूचना सलाहकार पढ़वाना चाहता है. उसे पढ़कर नरेन्द्र मोदी देश के बारे में जानकारियां संग्रहित कर रहे हैं.

मैं मानता हूं कि हो सकता है यह स्थिति गलत हो, हो सकता है मुझे गलत जानकारी मिली हो, पर जिस तरह के क्रियाकलाप चल रहे हैं, उनसे तो ऐसा ही लगता है कि मैं सही हूं और मैं जो आपसे कह रहा हूं, उसमें कुछ भी अतिश्योक्ति नहीं है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं की विशाल ताकत को देश के निर्माण में और जनता को देश के निर्माण में शामिल करने के लिए प्रेरित करने में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं. नतीजे के तौर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वो अंग, जो देश में दूरियां बढ़ाने का काम करते हैं, उन लोगों को इनसे ताकत मिल जाती है. इसलिए जिस तरह से देश में बाकी अंगों को सक्रिय करने में प्रधानमंत्री लगे हैं, उसी तरह से उन्हें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं की विशाल ताकत को आम जनता के विकास के कामों में शामिल करने के लिए प्रेरित करने में लगाना चाहिए. इसका एक उदाहरण उनका स्वच्छता अभियान है. इतना अच्छा अभियान, लेकिन उसका देश में कहीं पर भी असर अब नहीं दिखाई देता. अगर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का विशाल कार्यकर्ता वर्ग इस स्वच्छता अभियान में जनता को शामिल कर आगे बढ़ता, तो नरेन्द्र मोदी का आह्वान किसी एक मंजिल तक पहुंच सकता था, पर न नरेन्द्र मोदी जी ने उन संगठनों को मजबूत किया, जो आधिकारिक रूप से सफाई के लिए जिम्मेदार है और न राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं के सहारे जनता को इसके लिए प्रतिबद्ध और प्रेरित किया. मुझे लगता है कि नरेन्द्र मोदी जी को इन सारे सवालों के ऊपर फिर से सोचना चाहिए, उनका उत्तर कैसे मिले, इसकी नई योजना बनानी चाहिए. ■

editor@chauthiduniya.com

राहुल गांधी का अप्रासंगिक होना

मेघनाद देसाई

अपनी पीढ़ी के किसी भी नौजवान की तरह राहुल छुट्टी लेकर आराम करना चाहते हैं. वह अपने लिए एक काम चुनते हैं. उस काम की उन में समझ भी होती है, लेकिन अगर काम में समय लगने वाला हो तो वह जुट कर काम नहीं करना चाहते. राहुल यह स्वीकार करने के मामले में भी अजीब हैं कि उनसे भूल हो गई थी और सोचने के लिए उन्हें समय चाहिए. यह किसी को मालूम नहीं है कि वह कहां गए हैं (शायद अपने विशाल सैनिक फॉर्म के बोल्ट-होल में छुपे हों). वह कब आएंगे और पार्टी को कैसे चलाना चाहेंगे, यह भी किसी को नहीं पता.

कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होना एक अस्थाई मामला हुआ करता था. पार्टी हर साल अपना अध्यक्ष का चयन करती थी. कभी-कभी ही ऐसा होता था कि कोई अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित होता था. सुभाष चन्द्र बोस दो टर्म (अवधि) और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब वार्षिक अधिवेशन बुलाना संभव नहीं था, तो मौलाना आजाद 6 साल तक अध्यक्ष के पद पर बने रहे. आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री पार्टी का वास्तविक नेता होता था और अध्यक्ष की हैसियत नाम मात्र रह गई थी. इंदिरा गांधी और नेहरू के बीच के समय में यह पद एक बार फिर अहम हो गया था. लेकिन इंदिरा गांधी ने कमज़ोर अध्यक्ष की पुरानी परम्परा को फिर से स्थापित किया. तब जा कर इस पद की अहमियत को लेकर नीलम संजीव रेड्डी का भ्रम टूट गया.

दरअसल, यह सोनिया गांधी थीं, जिन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद को एक गंभीर राजनीतिक पद बना दिया. उन्हें ऐसा करना ही था, क्योंकि सीताराम केसरी के कार्यकाल में पार्टी कमज़ोर होती जा रही थी (हालांकि उस समय पार्टी की हालत इतनी बुरी नहीं थी, जितनी आज है). बहरहाल, सोनिया का अध्यक्ष पद पर बने रहने की अवधि सबसे लंबी है. उन्होंने अपने कार्यकाल में इस पुरानी पार्टी में कार्यकारी गुणवत्ता को बहाल किया. उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नहीं बनने का फैसला किया, लेकिन किसी के मन में शक की गुंजाइश नहीं थी कि अन्य गांधियों की तरह असल बॉस कौन है.

इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी न केवल मई 2014 के आम चुनाव में हारी, बल्कि उसके बाद होने वाले राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी पार्टी ने अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया है. इसकी एक वजह यह है कि पार्टी देश के शहरी नौजवानों से कट गई है और दूसरी वजह यह है कि लगभग पांच साल

से सोनिया गांधी की सेहत अच्छी नहीं रही है. हम यह तो नहीं कह सकते कि उन्हें क्या हुआ है, लेकिन पिछले दो चुनावों की तरह वह 2014 में चुनाव प्रचार नहीं कर सकीं.

सोनिया गांधी के संबंध में एक असाधारण तथ्य यह है कि वह राजनीति को नापसंद करतीं थी और उन्होंने राजीव गांधी को राजनीति में शामिल होने से रोका था, लेकिन राजीव गांधी गद्दी के उतराधिकारी थे और तोहफे में उन्हें लोक सभा में सबसे बड़ा बहुमत मिला था, जिसे बाद में उन्होंने गवां दिया. अपने आकर्षक व्यक्तित्व के बावजूद उनमें राजनीतिक कौशल नहीं था. संजय गांधी में यह कौशल मौजूद था, लेकिन यह किसी को पता नहीं कि जब सत्ता उनके हाथ में आती तो वह उसका किस तरह से इस्तेमाल करते.

राहुल गांधी की बहुत समस्याएं हैं. अब उन्हें इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि उन्हें अब पसंद नहीं किया जाता और उनमें न तो राजनीतिक कौशल है और न ही प्रतिभा. राजनीतिक दांव-पेंच सीखने के लिए उनके सामने उनकी मां का उदाहरण था. राजनीति को नापसंद करने वाली सोनिया गांधी ने राजनीति के दांव-पेंच अनोखे ढंग से सीखे. इसके लिए उन्होंने कोई औपचारिक या अनौपचारिक ट्रेनिंग नहीं ली. राहुल पतंग तो उड़ाते हैं, लेकिन वह उन्हें छोड़ देते हैं. मिसाल के तौर पर पार्टी प्राइमरी का चुनाव या भट्टा परसौल आन्दोलन के नाम लिए जा सकते हैं. राजनीति 24 घंटे चलने वाला काम है.

अपनी पीढ़ी के किसी भी नौजवान की तरह राहुल छुट्टी लेकर आराम करना चाहते हैं. वह अपने लिए एक काम चुनते हैं. उस काम की उन में समझ भी होती है, लेकिन अगर काम में समय लगने वाला हो तो वह जुट कर काम नहीं करना चाहते. राहुल यह स्वीकार करने के मामले में भी अजीब हैं कि उनसे भूल हो गई थी और सोचने के लिए उन्हें समय चाहिए. वह भी अपनी मां से दूर.

यह किसी को मालूम नहीं है कि वह कहां गए हैं (शायद अपने विशाल सैनिक फॉर्म के बोल्ट-होल में छुपे हों). वह कब आएंगे और पार्टी को कैसे चलाना चाहेंगे, यह भी किसी को नहीं पता. दुखद सच तो यह है कि इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता. वह अब अप्रासंगिक हो गए हैं. इस बीच सोनिया गांधी ने फिर से सक्रिय नेतृत्व संभाल लिया है. वह सरकार विरोधी प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहीं हैं और लोकसभा में भाषण दे रही हैं. इसका बहुत कम लोगों को अंदाज़ा है कि प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति बनने के बाद सोनिया कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ सांसद हैं. वह केवल वंशवाद की वजह से यहां नहीं हैं. राहुल गांधी को पार्टी का कमान सौंपने में असफल होने के बाद सोनिया गांधी को फिर से पार्टी का कार्यभार संभालना होगा.

फ़िलहाल कांग्रेस को 2014 में असफलता के कारणों पर गंभीरता से और खुले रूप से विचार करने की आवश्यकता है. उसे अपनी कार्यकारणी में अनुभवी लोगों को लाकर संगठन में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा. उसे गंभीरता से पुनर्विचार करना होगा कि मोदी विरोध के नारे के अतिरिक्त और कौन से मुद्दे हैं, जिन पर पार्टी विश्वास करती है. उसे अपने सदस्यों को अगले चुनाव में केवल पार्टी टिकट के लिए इंतज़ार करवाने के बजाय ज़मीनी स्तर पर पार्टी को पुनर्गठित करके काम करना होगा.

जहां तक राहुल का सवाल है, तो उन्हें छुट्टी पर ही रहने दिया जाए. यह कांग्रेस को बचाने का एक तरीका हो सकता है. नहीं तो अलविदा कांग्रेस. ■

feedback@chauthiduniya.com

गैस्ट्रोएन्टराइटिस

गर्मी के मौसम में होने वाली बीमारियां

गैस्ट्रोएन्ट्राइटिस से प्रभावित व्यक्ति को डायरिया हो सकता है जिसे आम भाषा में गैस्ट्रिक या इसके अलावा इसे स्टमक फ्लू भी कहते हैं. यह बीमारी नोरोवायरस, रोटावायरस और एस्ट्रोवायरस जैसे बैक्टीरिया पैदा होने पर फैलती है. यह वायरस ज्यादातर दूषित पानी और खाने से फैलता है और चार से 48 घंटे में अपना संक्रमण फैलाते हैं.

मोनिशा भटनागर

आम तौर पर गर्मियों में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बीमारी है गैस्ट्रोएन्टराइटिस. गर्मी का मौसम इस बीमारी के जीवाणुओं को पनपने के लिए उपयुक्त माहौल देता है, जिस वजह से इस मौसम में गैस्ट्रोएन्टराइटिस के रोगी सबसे अधिक पाए जाते हैं. इस मौसम में अक्सर देखा गया है हर दूसरा व्यक्ति पेट की तकलीफ से परेशान होता है. गैस्ट्रोएन्टराइटिस से प्रभावित व्यक्ति को डायरिया हो सकता है जिसे आम भाषा में गैस्ट्रिक या स्टमक फ्लू भी कहते हैं. यह बीमारी नोरोवायरस, रोटावायरस और एस्ट्रोवायरस जैसे बैक्टीरिया पैदा होने पर फैलती है. यह वायरस ज्यादातर दूषित पानी और खाने से फैलता है और चार से 48 घंटे में अपना संक्रमण फैलाते हैं. बच्चों में अब रोटावायरस के संक्रमण से बचाव के लिए टीके भी लगाए जाते हैं. एक्यूट गैस्ट्रोएन्टराइटिस जानलेवा भी हो सकता है.

लक्षण

इसके मुख्य लक्षण हैं पेट खराब होना,पेट में गुड़गुड़ाहट, दर्द और उल्टियां होना. इसमें बेचैनी या घबराहट भी होती है साथ ही बार–बार गला सूखता है. हल्का बुखार, कमज़ोरी, मांसपेशियों में खिंचाव और भूख में कमी भी इस बीमारी के लक्षण हैं. कुछ लोगों में जी मिचलाना, तेज ठंड लगना, त्वचा में हल्की जलन होना और बहुत पसीना आना जैसे लक्षण भी होते हैं.

सावधानी

इस बीमारी से बचने के लिए बाहर की खासकर खुली जगहों जैसे ठेलों, रेहड़ी–पटरी आदि से लेकर खाने की चीजें न खाएं. गर्मियों में खाना अक्सर जल्दी दूषित हो जाता है और ऐसा खाना खाने से गैस्ट्रोएन्टराइटिस हो जाता है. इसलिये इस मौसम में बासी खाना खाने से खासकर परहेज करें. साथ ही फल–सब्जियां भी सभी अच्छे से धोकर प्रयोग में लानी चाहिए. धूप में ज्यादा देर पानी पिए बिना न रहे और पानी के साथ साथ और तरह के तरल पदार्थों का भी सेवन बढ़ाएं. बिना ढका या फ़िल्टर किया गया पानी न पियें. सबसे ज़रूरी है साफ़ सफाई का ध्यान रखना. गर्मियों के मौसम में कई बीमारियों से केवल हाइजीन का ख्याल रख के बचा जा सकता है. जैसे खाना बनाने और खाने दोनों से पहले अच्छी तरह साबुन से हाथ धोएं, कहीं भी बाहर से आने पर हाथ पैर अच्छी तरह साफ़ करें, शौच के बाद भी हाथ साबुन से धोने चाहिये. अपने घर और अपने आस–पास भी साफ़–सफाई का खास ख्याल रखें.

गर्मी से मुकाबला

गर्मियों के इस मौसम से मुकाबला करने में यह कुछ खास बातें करेंगी आपकी मदद. इस मौसम में कोशिश कीजिए कि एक दिन में कम से कम 12 गिलास पानी अवश्य पिएं. इसके साथ ही ताजे फलों का रस, नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ आदि समय–समय पर पीने से शरीर को स्फूर्ति के साथ–साथ गर्मी के मौसम में ठंडक भी मिलती है. इसके अलावा खुले में बिक रही खाने की चीजों से दूर रहें क्योकि देर तक खुले रखे सामान में बैक्टीरिया पनप जाते हैं, जो पेट में जाकर संक्रमण फैलाते हैं. पाचन तंत्र का ख्याल करते हुए इस मौसम में ज्यादा तीखा या मसाले वाला खाना न खाएं. विशेषज्ञ कहते हैं की गर्मी के मौसम में जितनी भूख हो, उससे थोड़ा कम खाना खाना चाहिए और जल्दी पचने वाला हल्का खाना चाहिए. लेकिन ध्यान रहे गर्मी में घर से बाहर निकलते हुए पेट भरा होना चाहिए यानि बिल्कुल खली पेट धूप में न निकलें. खाने पीने के अलावा कपड़े पहनने में भी कुछ चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जैसे सूती और हल्के रंग के कपड़े पहनें. गहरे रंग के कपड़ों में गर्मी ज्यादा लगती है इसलिए उन्हें न पहनें. जिन जगहों पर मक्खी–मच्छर होने की आशंकाएं ज्यादा हों वहां पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें. गर्मियों में धूप में अगर ज्यादा समय बिताना पड़े तो समय–समय पर चेहरे को ठंडे कपड़े या गीले टिश्यू पेपर से चेहरा पोंछते रहें. इसके अलावा सूरज की यू.वी किरणों से बचने के लिए सन्स्क्रीन के इस्तेमाल के साथ–साथ टोपी, छाता और गॉगल्स का भी प्रयोग करें. ■

feedback@chauthiduniya.com

> स्टमक फ्लू से बचने का सबसे कारगर तरीका का है हाइजीन का ख्याल रखना. खाना बनाते समय, खाने की कोई भी चीज़ खाने से पहले, या चेहरे पर हाथ लगाने से पहले अगर हाथ को अच्छी तरह साबुन से धो लिया जाये तो स्टमक फ्लू ही नहीं कई बीमारियों से बचा जा सकता है. गर्मियों के मौसम में मच्छर–मक्खियों का प्रकोप बढ़ जाता है, ऐसे में गन्दगी में यह और पनपतें हैं और आखिरकार बीमारियों की वजह बनते हैं. आस–पास की साफ़–सफाई और पर्सनल हाइजीन बीमारियों से बचने का अचूक उपाय है. इसके अलावा अक्सर गर्मी के मौसम में लोग बाहर से गन्ने का जूस पी लेते है. यह गैस्ट्रोएन्टराइटिस की एक बड़ी वजह है. जूस के अलावा खुले में रखा खाना जिस पर मक्खी–मच्छर बैठते हों, उसे खाने से भी यह बीमारी होती है. गर्मी के इस मौसम में स्ट्रीट वेंडर्स से लेकर खाना तो नहीं ही खाना चहिये साथ ही नॉन–वेज भी अवॉयड करना चाहिए. हाइजीन और खाने–पीने में सावधानी बरतने से गैस्ट्रोएन्टराइटिस जैसी बीमारी से बचा जा सकता है.
>
> **आर.पी सैनी**
> *वरिष्ठ चिकित्सक, सफदरजंग हॉस्पिटल*

जासूसी की मिसाल लीजे

बोरेल और लीजे को एसओई की तरफ से यह निर्देश दिए गए थे कि उन्हें जर्मनी अधिकृत फ्रांस में एक ऐसे सुरक्षित घर की व्यवस्था करनी है जिसमें आगे आने वाले जासूसों को आसानी के साथ रखा जा सके. उन पर दूसरी जिम्मेदारी यह थी कि लीजे को फ्रांस में काम कर रहे डॉक्टरों के जरिये एक ऐसा नेटवर्क तैयार करना था जिससे ब्रिटिश जासूसों को देश में अलग अलग जगहों पर ठहराया जा सके.

अरुण तिवारी

लीजे मैरी जीनेट डे बेसियाक का जन्म फ्रांस अधिकृत मॉरिशस में सन 1905 में हुआ था. उन्हें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेनाओं के स्पेशल ऑपरेशन की नायिका कहा जाता है. वे एक ऐसी साहसी जासूस थीं जिन्होंने हिटलर के हिटलर के ख़िलाफ़ लड़ाई में ब्रिटिश सेनाओं की गुप्त सूचनाओं के जरिये काफी मदद की और उनके कई ऑपरेशन चलाये. युद्ध समाप्त होने के बाद उन्हें ब्रिटिश सरकार की तरफ से कई वीरता पुरस्कार दिये गए थे.

लीजे अपने माता–पिता की तीसरी संतान थीं. उनके माता–पिता फ्रांसीसी थे. 1919 में उनका पूरा परिवार पेरिस में आकर बस गया. साल 1940 में पेरिस पर जर्मनी का अधिकार हो गया था. ऐसी स्थिति में लीजे के बड़े भाई जीन डे बेसियाक ने ब्रिटिश सेना ज्वाइन कर ली. इसी दौरान उनके एक और भाई क्लाउडे और लीजे ने दक्षिणी फ्रांस के रास्ते ब्रिटेन पहुंचने की कोशिश की. इन दोनों ने ब्रिटेन के रास्तों के जानकार से मदद ली और पहले स्पेन के रास्ते पुर्तगाल पहुंचे. यहां उन्हें लगभग पांच महीने तक इंतजार करना पड़ा क्योंकि ब्रिटेन के भीतर जाने की अनुमति उन्हें नहीं मिल पा रही थी. लंदन पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात लेडी केमस्ले से हुई. केमस्ले ने नौकरी दिलवाने में लीजे की मदद की. वहीं उनके भाई को सेना के स्पेशल ऑपरेशन के लिए भर्ती कर लिया गया. जल्दी ही स्पेशल ऑपरेशन के लिए महिलाओं की भर्ती भी शुरू की गई. लीजे ने इसके लिए आवेदन किया. उनका साक्षात्कार अंग्रेज अधिकारी सेलविन जिप्सन ने किया. सेलविन ने पाया कि लीजे के भीतर एक जासूस बनने से ज्यादा गुण हैं. उन्हें लगा कि लगा कि लीजे के जरिये एक पूरा जासूसों का सर्किट ही चलाया जा सकता है. उन्हें चयनित कर लिया गया और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा ट्रेनिंग दी जाने लगी. उनकी ट्रेनिंग हैंपशायर में हुई. जुलाई 1942 में उन्हें फर्स्ट एड नर्सिंग में कमीशन दिया गया. जब उन्हें कमीशन दिया गया था तब उनके ट्रेनर ने उनके बारे में कहा था कि लीजे में दूसरे प्रशिक्षुओं से ज्यादा गुण थे और वे अपने साथियों से जासूसी के मामले में कई गुना आगे थीं.

पहला मिशन : 24 सितंबर 1942 को लीजे और एंड्री बोरेल (एंड्री बोरेल के बारे में हम पूर्व में चौथी दुनिया की अपनी इसी श्रृंखला में प्रकाशित कर चुके हैं) ऐसी पहली महिला जासूस बनीं जिन्हें जर्मनी अधिकृत फ्रांस में पैराशूट के जरिये उतारा गया. बोरेल और लीजे को एसओई की तरफ से यह निर्देश दिए गए थे कि उन्हें जर्मनी अधिकृत फ्रांस में एक ऐसे सुरक्षित घर की व्यवस्था करनी है जिसमें आगे आने वाले जासूसों को आसानी के साथ रखा जा सके. लीजे को इसके अलावा भी एक और जिम्मेदारी दी गई थी. वह जिम्मेदारी यह थी कि लीजे को फ्रांस में काम कर रहे डॉक्टरों के जरिये एक ऐसा नेटवर्क तैयार करना था जिसके जरिये आसानी के साथ ब्रिटिश जासूसों को देश में अलग अलग जगहों पर ठहराया जा सके. दरअसल उस समय जर्मन सैनिकों की निगाह हर तरफ हुआ करती थी जिसकी वजह से जासूसों को अस्पताल में रखना भी ज्यादा आसान काम हुआ करता था. मरीज का रूप लिये हुए जासूसों पर किसी को जल्दी शक भी नहीं होता था. सिर्फ इतना ही नहीं लीजे ने इस बात की जिम्मेदारी भी संभाल रखी थी कि जर्मनी अधिकृत फ्रांस में जब भी ब्रिटेन से हथियार आने वाले होते थे तो उन्हें सुरक्षित जगह पर कैसे पहुंचाया जाये? ये हथियार जर्मनी से लड़ाई लड़ रही फ्रेंच रेजिस्टेंस आर्मी इस्तेमाल किया करती थी. लीजे इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही थीं. यह जिम्मेदारी ज्यादा महत्वपूर्ण इस वजह से थी क्योंकि जर्मनी से लड़ाई लड़ रहे सैनिकों के पास हथियार अगर सही समय से न पहुंचते तो उन्हें लड़ाई जारी रख पाने में काफी मुश्किल होती. इसी दौरान उनकी एक दुर्घटना में उनकी टांग टूट गई और उन्हें ब्रिटेन वापस लौट कर आना पड़ा. लीजे को ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगा. दो महीने बाद ही उन्होंने सेना से इच्छा जाहिर की कि उन्हें फ्रांस जाकर ब्रिटेन के लिए काम करना है. एक बार फिर वहां जाकर उन्होंने ब्रिटेन को सूचनाएं पहुंचाना शुरू कर दिया. जब युद्ध की समाप्ति हुई तो वे वापस लौटकर ब्रिटेन आ गईं. लीजे अपनी दूसरी कई साथियों से सौभाग्यशाली थीं क्योंकि उन्हें जर्मनी की सेनाओं के हाथों से भी जान बचाकर निकलने का मौका मिला.

युद्ध की समाप्ति के बाद उन्होंने शादी की. लेकिन दंपति को संतान नहीं पैदा हुई. लीजे की मौत 98 साल की उम्र में साल 2004 में हुई. 2008 में उनपर फ्रांस में एक फिल्म भी बनाई गई. ■

feedback@chauthiduniya.com

देश की राजधानी समेत लगभग सभी महत्वपूर्ण शहरों में सालेह के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए. सालेह अपना पद छोड़ना नहीं चाहते थे. वह पूरे विरोध को बहुत बेदर्दी के साथ मसलने के मूड में थे, लेकिन ऐसा नहीं कर सके. सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस दौरान भी खाड़ी के लगभग सभी देश सालेह के साथ थे. सालेह ने विरोध को दबाने की काफी कोशिशें की, लेकिन नाकाम रहे. इस दौरान जब उनपर एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के दौरान हमला हुआ, जिसमें वे बुरी तरह घायल हो गए थे, तो उसके बाद उन्होंने सरकार छोड़ दी.

सत्ता संघर्ष में यमन ने खोया अमन

अरुण तिवारी

यमन संकट की शुरुआत साल 2011-12 में उस समय हुई, जब लगभग दो दशक से ज्यादा समय तक देश पर राज कर चुके राष्ट्रपति अली अब्दुल्लाह सालेह के शासन के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन शुरू हुए थे. सालेह ने 2012 की शुरुआत में यमन सरकार और विपक्ष के बीच समझौते के बाद अपना पद छोड़ दिया था. उनके बाद देश के राष्ट्रपति मूंसर हादी बने, जिन्होंने देश के बिगड़े हुए राजनीतिक परिदृश्य को संभालने की कोशिश की. उन्हें लगातार अल कायदा और हौती आतंकियों की तरफ से धमकियां मिल रही थीं. 2014 में हौती आतंकियों ने देश की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और हादी सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि देश की दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर एक साझा सरकार बनाई जाए. हादी पर दबाव बनाए रखने के दौरान एक दिन वह भी आया, जब आतंकियों ने उनके राष्ट्रपति महल पर हमला कर दिया. हादी ने अपने मंत्रियों सहित जनवरी 2015 में पद त्याग दिया. फरवरी में हौती समूह ने खुद को आधिकारिक तौर पर वहां का नुमाइंदा घोषित कर दिया और हौती नेता अब्दुल मलिक हौती के रिश्तेदार मुहम्मद अली हौती के नेतृत्व में एक रिवोल्यूशनरी कमेटी का गठन किया, जो देश की सत्ता संभालने के लिए बनाई गई थी. इन सारे घटनाक्रमों के बीच हादी देश के समुद्री किनारे पर बसे शहर अदन भाग गए. उन्होंने वहां इस बात की घोषणा की कि देश के वास्तविक राष्ट्रपति वही हैं और अदन को ही उन्होंने देश की तात्कालिक राजधानी घोषित कर दिया. उन्होंने अपने नजदीकियों और मिलिट्री के विश्वासपात्र अधिकारियों से इस बात की अपील भी की कि वे उनका साथ दें.

अरब क्रांति के शुरू होने के बाद ज्यादा दिन नहीं लगे थे, जब यमन में भी सरकार विरोधी बयारें बहनी शुरू हो गई थीं. यमन पश्चिम एशिया का एक गरीब देश है. उस समय लोगों के बीच वहां की अली अब्दुल्लाह सालेह की सरकार को लेकर एक आम धारणा भी बन गई थी कि सरकार भ्रष्ट है. देश में लोगों के पास व्यक्तिगत तौर पर हथियारों की एक बड़ी खेप मौजूद थी. इसके अलावा देश दक्षिणी हिस्से में अलकायदा से संबंधित चरमपंथ और आतंकवाद को झेल रहा था. उत्तर में देश ज़ायदी शिया आतंकियों से त्रस्त था. देश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में काफी अंतर और मतभेद है.

दरअसल, दोनों ही तरफ से एक-दूसरे को हराने की भरपूर कोशिशें चल रही हैं, लेकिन हौती विद्रोही हादी सरकार पर ज्यादा भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं. कई जानकार इस पूरे विद्रोह को देश की गरीबी से जोड़कर भी देख रहे हैं. दरअसल, यमन पश्चिम एशिया का सबसे गरीब देश माना जाता है. अली अब्दुल्लाह सालेह की सरकार के दौरान देश में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था. 2011 में जब ट्यूनीशिया में अरब क्रांति की शुरुआत हुई, तो वहां भी कई विद्रोही समूहों को लगने लगा कि सालेह की सरकार को उखाड़ कर फेंका जा सकता है. उसी के बाद इन समूहों ने देश में आंतरिक गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए. देश की राजधानी समेत लगभग सभी महत्वपूर्ण शहरों में सालेह के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए. सालेह अपना पद छोड़ना नहीं चाहते थे. वह पूरे विरोध को बहुत बेदर्दी के साथ मसलने के मूड में थे, लेकिन ऐसा नहीं कर सके. सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस दौरान भी खाड़ी के लगभग सभी देश सालेह के साथ थे. सालेह ने विरोध को दबाने की काफी कोशिशें की, लेकिन नाकाम रहे. इस दौरान जब उनपर एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के दौरान हमला हुआ, जिसमें वे बुरी तरह घायल हो गए थे, तो उसके बाद उन्होंने सरकार छोड़ दी. हादी ने उनकी अनुपस्थिति में देश की कमान संभाली और विपक्षी दलों से बातचीत भी की, लेकिन हादी ने अपने मंत्रिमंडल में एक भी हौती लीडर को जगह नहीं दी. यह भी एक मुख्य कारण रहा कि हौती ने अपना विरोध बंद नहीं किया. आखिरकार, हौती लीडर अब्दुल मलिक अल हौती के नेतृत्व में विद्रोहियों ने सना पर कब्जा कर लिया और हादी को भागना पड़ा. अब देश की स्थिति कुछ यूं है कि हादी देश से फरार हैं और हौती विद्रोहियों ने देश की सत्ता पर पूर्ण अधिकार कर लिया है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बिरादरी हौती सरकार को मान्यता नहीं दे रही है और सऊदी अरब ने हौती सरकार को सत्ता से हटाने के लिए निर्णायक जंग छेड़ दिया है, जिसमें खाड़ी के लगभग सभी महत्वपूर्ण देश उसका साथ दे रहे हैं.

ईरान का हौती को समर्थन

यमन में चल रहे सत्ता संघर्ष में ईरान बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है. वह पश्चिम एशिया में अपना दबदबा कायम रखने के लिए उन सभी जगहों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, जहां पर शिया मुसलमान हैं. हौती भी शिया मुसलमानों का ही समूह है, जो यमन की सत्ता पर काबिज होना चाहता है. ऐसा बताया जाता है कि हौती लीडर अब्दुल मलिक अल हौती के कनेक्शन ईरान से हैं और उसकी शक्ति को बढ़ाने का काम भी ईरान कर रहा है. दरअसल, देश में सल्फी मुसलमानों के साथ हौती विद्रोहियों की अदावत पुरानी है. सालेह को सत्ता से हटाने के दौरान दोनों का कई बार आमना-सामना हुआ है. ईरान के इस पूरे मामले में हौती को समर्थन देने की वजह से हौती विद्रोहियों का देश में पलड़ा भारी हो गया है.

सऊदी अरब ने लगाए डेढ़ लाख सैनिक

देश में हिंसा के खिलाफ पश्चिम एशिया के सबसे बड़े देश सऊदी ने सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है. सहयोगी सेना ने यमन की राजधानी सना में एयरपोर्ट को निशाना बनाकर हवाई हमले किए हैं, जिससे रिहायशी इलाके को बड़ा नुकसान हुआ है. सऊदी अरब के इस हमले की काफी आलोचना भी हो रही है, क्योंकि उसके इस हमले में कई आम नागरिकों के मारे जाने की खबर है. एक यूरोपीय अखबार के मुताबिक, अगर सऊदी अरब यह मुद्दा बनाकर मैदान में कूदा है कि यमन में आम नागरिक मारे जा रहे हैं, तो उसे देश में हमले करने के दौरान इस बात का ख्याल रखना होगा कि आम नागरिकों की जान बहुत कीमती है. वे वैसे भी देश में पिछले तीन साल से बने गृहयुद्ध जैसे हालात से काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं. ऐसे में आम नागरिकों पर हमला कहीं से भी उचित नहीं है. एक विदेशी चैनल के मुताबिक, विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब ने डेढ़ लाख सैनिक और 100 फाइटर जेट खड़े किए हैं. वहीं, अब जॉर्डन, यूएई, कुवैत, बहरीन, कतर और जॉर्डन भी यमन में सैन्य कार्रवाई में सऊदी का साथ दे रहे हैं. अमेरिका में सऊदी अरब के राजदूत अदेल-अल-जुबैर ने बताया कि यमन में कई जगहों पर सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों ने हवाई हमले किए हैं.

वार्ता ही एकमात्र विकल्प-बान की मून

यमन में खराब होती स्थितियों के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने भी बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में हालात पहले से ही ठीक नहीं है. ऐसे में अगर एक और देश हिंसा की चपेट में आ जाएगा, तो यह मुश्किल वाली स्थिति होगी. उन्होंने अपने प्रवक्ता के माध्यम से जारी किए गए बयान में कहा है कि यमन में सैन्य हस्तक्षेप करने वाले विभिन्न दल नागरिकों और मानवीय कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें.यमन में संकट का समाधान करने के लिए वार्ता ही एकमात्र विकल्प है. उन्होंने उल्लेख किया कि यमन सरकार के अनुरोध पर सऊदी अरब ने यमन में सैन्य हस्तक्षेप शुरू करने की घोषणा की है. इसके अलावा खाड़ी अरब देशों की सहयोग परिषद (जीसीसी) के सदस्यों आदि द्वारा समर्थन दिए जाने की खबरें मिली हैं. उन्होंने सभी पक्षों को याद दिलाया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पहले ही 22 मार्च को यमन के राष्ट्रपति मंसूर हादी की वैधता के समर्थन में बयान जारी कर चुकी है. सभी दलों और सभी सदस्य देशों से यमन की एकता, संप्रभुता, स्वतंत्रता और अखंडता को क्षति पहुंचाने की किसी भी कार्रवाई से बचने की अपील की है. सुरक्षा परिषद ने सदस्य देशों से बाहरी हस्तक्षेप के संघर्ष और अस्थिरता के उकसावे से बचने की अपील की है.

यमन संकट से क्रूड में उछाल

अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है. यमन में राजनीतिक और सैन्य संकट गहराने की खबरों से क्रूड की कीमतों में जोरदार उछाल आया है. एनर्जी एक्सपर्ट मानते हैं कि यमन संकट से खाड़ी देशों के क्रूड उत्पादन पर असर होगा, क्योंकि यमन संकट से अन्य देशों में भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं. साथ ही यमन के आस-पास क्रूड ऑयल शिपमेंट की सुरक्षा का खतरा बढ़ गया है. फिलहाल, नायमैक्स क्रूड का भाव 1.70 फीसदी उछलकर 50 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है. ब्रेंट क्रूड भी 2 फीसदी चढ़कर 57.62 डॉलर प्रति बैरल पर है.

भारत ने अपने नागरिकों को किया अलर्ट

सरकार ने यमन में फंसे भारतीय को सुरक्षित बाहर निकालने के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया है और यमन की ताजा स्थिति का जायजा लिया है. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, विदेश मंत्रालय में सचिव अनिल वाधा ने रक्षा, गृह, प्रवासी मामलों, जहाजरानी मंत्रालयों, नौसेना और वायु सेना मुख्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर यमन में फंसे कम से कम साढ़े तीन हजार नागरिकों की सुरक्षित वापसी के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सना में भारतीय दूत अमृत लुगुन से वहां की स्थिति पर पहले ही टेलीफोन पर बातचीत की थी. विदेश मंत्रालय ने यमन की स्थिति के बारे में 24 घंटे जानकारी देने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया है. यमन में फंसे लोगों में ज्यादातर नर्स हैं. गौरतलब है कि सरकार ने यमन की स्थिति गंभीर बताते हुए नागरिकों को जल्द से जल्द स्वदेश लौटने की सलाह दी थी. सरकार ने इसके पहले 21 जनवरी और 19 मार्च को निर्देश जारी कर नागरिकों को स्वदेश लौटने को कहा था.■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध, Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

> जब काका जी शिरडी यात्रा करने का विचार कर रहे थे, उसी समय उनके यहाँ एक अतिथि आया (जो शामा के अतिरिक्त और कोई न था) . शामा बाबा केअंतरंग भक्तों में से एक थे. जब उन्होंने सुना कि वे शिरडी से आ रहे तो वे एकदम शामा से लिपट गये और फिर दोनों का श्री साई लीलाओं पर वार्तालाप आरम्भ हो गया. अपने वचन संबंधी कृत्यों को पूर्ण कर वे काकाजी के साथ शिरडी लौट आये. काकाजी मस्जिद पहुंच कर बाबा के श्रीचरणों से जा लिपटे.

भक्तों को आत्मदर्शन कराते हैं साई

चौथी दुनिया ब्यूरो

साई बाबा किसी कारण भक्तों पर स्नेह करने वाले दया के सागर हैं तथा निर्गुण होकर भी भक्तों के प्रेमवश ही स्वेच्छापूर्वक मानव शरीर धारण किया. श्री साई बाबा को हम सभी को नमन करना चाहिए. भक्तों को आत्मदर्शन कराना ही सन्तों का प्रधान कार्य है. श्री साई, जो सन्त शिरोमणि है, उनका तो मुख्य ध्येय ही यही है. जो उनके श्री–चरणों की शरण में जाते है, उनके समस्त पाप नष्ट होकर निश्चित ही दिन–प्रतिदिन उनकी प्रगति होती है. उनके श्री–चरणों का स्मरण कर पवित्र स्थानों से भक्तगण शिरडी आते और उनके समीप बैठकर श्लोक पढ़कर गायत्री–मंत्र का जप किया करते थे. लेकिन जो निर्बल तथा सर्व प्रकार से दीन–हीन है और जो यह भी नहीं जानते कि भक्ति किसे कहते है, उनका तो केवल इतना ही विश्वास है कि अन्य सब लोग उन्हें असहाय छोड़कर उपेक्षा भले ही कर दे, लेकिन अनाथों के नाथ और प्रभु साई भक्तों का परित्याग नहीं करेंगे. जिन पर वे कृपा करें, उन्हें शक्ति, नित्यानित्य में विवेक तथा ज्ञान सहज ही प्राप्त हो जाता है.

वे अपने भक्तों की इच्छाएं पूर्णत: जानकर उन्हें पूर्ण किया करते हैं, इसीलिये भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाया करती है और वे सदा कृतज्ञ बने रहते हैं. जो संकट से घिरा प्राणी इस प्रकार श्री साई से प्रार्थना करता है, उनकी कृपा से उसे पूर्ण शान्ति तथा सुख–समृद्धि प्राप्त हो जाती है. इस से प्रेरित कहान दी गई है...

नासिक जिले के वणी ग्राम में काका जी वैघ नाम के एक व्यक्ति रहते थे. वे श्रीसप्तशृंगी देवी के मुख्य पुजारी थे. एक बार वे विपत्तियों में कुछ इस प्रकार ग्रसित हुए कि उनके चित्त की शांति भंग हो गई और वे बिलकुल निराश हो उठे. एक दिन अति व्यथित होकर देवी के मंदिर में जाकर अन्त:करण से वे प्रार्थना करने लगे कि हे देवि. हे दयामयी. मुझे कष्टों से शीघ्र मुक्त करो. उनकी प्रार्थना से देवी प्रसन्न हो गईं और उसी रात्रि को उन्हें स्वप्न में बोली कि तू बाबा के पास जा, वहां तेरा मन शान्त और स्थिर हो जायेगा. बाबा का परिचय जानने को काका जी बड़े उत्सुक थे, लेकिन देवी से प्रश्न करने के पूर्व ही उनकी निद्रा भंग हो गई वे विचारने लगे कि ऐसे ये कौन से बाबा हैं, जिनकी ओर देवी ने मुझे संकेत किया है. कुछ देर विचार करने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सम्भव है कि वे त्र्यंबकेश्वर बाबा (शिव) ही हों. इसलिये वे पवित्र तीर्थ त्र्यंबक (नासिक) को गये और वहां रहकर दस दिन व्यतीत किये. वे प्रात:काल उठकर स्नानादि से निवृत्त हो, रुद्र मंत्र का जप कर, साथ ही साथ अभिषेक व अन्य धार्मिक कृत्य भी करने लगे. लेकिन उनका मन पहले की तरह ही अशान्त बना रहा. तब फिर अपने घर लौटकर वे अति करुण स्वर में देवी की स्तुति करने लगे. उसी रात्रि में देवी ने पुन: स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तू व्यर्थ ही त्र्यम्बकेश्वर क्यो गया. बाबा से तो मेरा अभिप्राय था शिरडी के श्री साई समर्थ से. अब काका जी के समक्ष मुख्य प्रश्न यह उपस्थित हो गया कि वे कैसे और कब शिरडी जाकर बाबा के श्री दर्शन का लाभ उठाये. यथार्थ में यदि कोई व्यक्ति, किसी सन्त के दर्शने को आतुर हो तो केवल सन्त ही नहीं, भगवान भी उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं. वस्तुत: यदि पूछा जाय तो सन्त और अनन्त एक ही हैं और उनमें कोई भिन्नता नहीं. यदि कोई कहे कि मैं स्वत: ही अमुक सन्त के दर्शन को जाऊंगा तो इसे सपने के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है. सन्त की इच्छा के विरुद्ध उनके समीप कौन जाकर दर्शन ले सकता है. उनकी सत्त के बिना वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता. जितनी तीव्र उत्कंठा संत दर्शन की होती, तदनुसार ही उसकी भक्ति और विश्वास में वृद्धि होती जायेगी और उतनी ही शीघ्रता से उनकी मनोकामना भी सफलतापूर्वक पूर्ण होगी. जो निमंत्रण देता है, वह आदर आतिथ्य का प्रबन्ध भी करता है. काका जी के सम्बन्ध में सचमुच यही हुआ.

जब काका जी शिरडी यात्रा करने का विचार कर रहे थे, उसी समय उनके यहाँ एक अतिथि आया (जो शामा के अतिरिक्त और कोई न था) . शामा बाबा केअंतरंग भक्तों में से एक थे. जब उन्होंने सुना कि वे शिरडी से आ रहे तो वे एकदम शामा से लिपट गये और फिर दोनों का श्री साई लीलाओं पर वार्तालाप आरम्भ हो गया. अपने वचन संबंधी कृत्यों को पूर्ण कर वे काकाजी के साथ शिरडी लौट आये. काकाजी मस्जिद पहुंच कर बाबा के श्रीचरणों से जा लिपटे. उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी और उनका चित्त स्थिर हो गया. देवी के दृष्टांतानुसार जैसे ही उन्होंने बाबा के दर्शन किये, उनके मन की अशांति तुरन्त नष्ट हो गई और वे परम शीतलता का अनुभव करने लगे. वे विचार करने लगे कि कैसी अदभुत शक्ति है कि बिना कोई सम्भाषण या प्रश्नोत्तर किये अथवा आशीष पाये, दर्शन मात्र से ही अपार प्रसन्नता हो रही है. सचमुच में दर्शन का महत्व तो इसे ही कहते हैं. बाबा की अन्य लीलाएं सुनकर उन्हें अपार आनन्द हुआ और वे पूर्णत: बाबा के शरणागत हो गए. सब चिन्ताओं और कष्टों को भूलकर वे परम आनन्दित हुए. उन्होंने वहां सुखपूर्वक बारह दिन व्यतीत किये और फिर बाबा की आज्ञा, आशीर्वाद तथा उदी प्राप्त कर अपने घर लौट गये.■

feedback@chauthiduniya.com

> *श्री साई, जो सन्त शिरोमणि है, उनका तो मुख्य ध्येय ही यही है. जो उनके श्री–चरणों की शरण में जाते है, उनके समस्त पाप नष्ट होकर निश्चित ही दिन–प्रतिदिन उनकी प्रगति होती है. उनके श्री–चरणों का स्मरण कर पवित्र स्थानों से भक्तगण शिरडी आते और उनके समीप बैठकर श्लोक पढ़कर गायत्री–मंत्र का जप किया करते थे. लेकिन जो निर्बल तथा सर्व प्रकार से दीन–हीन है और जो यह भी नहीं जानते कि भक्ति किसे कहते है, उनका तो केवल इतना ही विश्वास है कि अन्य सब लोग उन्हें असहाय छोड़कर उपेक्षा भले ही कर दे, लेकिन अनाथों के नाथ और प्रभु साई भक्तों का परित्याग नहीं करेंगे.*

साई के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दु:ख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10. मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

आप की आपसी जंग

कुछ दिन चांदनी फिर अंधेरी रात–कुछ ऐसा ही नजारा आप (आम आदमी पार्टी) का नजर आ रहा है. दिल्ली में बहुमत से बनी आम आदमी पार्टी की सरकार का हाल खस्ता नजर आ रहा है. देश का विकास, दिल्ली का विकास, सबको खुशहाली देने का वादा करने वाली आप आज खुद ग़मों के चौराहों पर खड़ी है. पार्टी कमजोर होती नजर आ रही है. जहां योगेन्द्र यादव, प्रशांत भूषण को पार्टी से निकालने की बात चल रही है तो वहीं अंजलि दमानिया ने पार्टी ही छोड़ दिया. क्या संभलेगी आप जब खुद पार्टी के नेता एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं. सरकार इस सियासी खेल से कब बहार आएगी और देश के विकास के लिए काम करेगी. नेताओं ने सत्ता पर राज करने की होड़ में आम जनता को नजरअंदाज कर दिया है. सभी अपना दाव खेलने में लगे हैं. भूल गए की उन्हीं जनता की बदौलत आज वो सत्ता में हैं और जनता जब चाहेगी तब उनसे वो पावर ले सकती है. जनता को मुर्ख बनाने कला में तो जैसे इन नेताओं ने पीएचडी कर रखी है. आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा, आपसी लड़ाई कब खत्म होगी. बड़े–बड़े वादे करने वाले ये नेता कब जनता की उम्मीदों को कुचलना बंद करेंगे. देश में सरकार जनता के लिए बनाई जाती है, लेकिन यहां तो सिर्फ गद्दी पाने की वजह बन गयी है जनता.

–तेजस्विनी श्रीवास्तव, *ई–मेल द्वारा*

जैविक की कीट नाशकों को अपनाएं किसान

किसानों द्वारा रासायनिक कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल के दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं. सब्जियों, अनाज और दूध के माध्यम से कीटनाशक मानव शरीर में पहुंच रहे हैं. धान के पानी भरे खेत से कीटनाशक निकटवर्ती तालाब में पहुंचते हैं. पशु उस पानी को पीते हैं और जब मनुष्य उस पशु का दूध पीता है, तो कीटनाशक उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं. नियमत: बाजार ले जाने लायक सब्जियों को तोड़कर बाद में कीटनाशकों का छिड़काव किया जाना चाहिए, लेकिन किसान कीटनाशक का छिड़काव करने के बाद सब्जी तोड़कर मंडी पहुंचा देता है. आज कल बढ़ रही बीमारियों के मूल में कीट नाशक घर में ही तैयार करें. गौमूत्र में नीम की पत्ती, धतूरा और निष्प्रयोज्य तम्बाकू की पत्तियां सड़ाकर जैविक कीट नाशक तैयार किया जा सकता है.

–राजकिशोर पांडेय (प्रहरी)
लखीपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.

सरकार के माथे का कलंक

देश के अलग–अलग हिस्सों में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या लोकतंत्र के लिए घातक है. देश का महत्वपूर्ण घटक जो खुद अभावों में जीता है और देश के लिए अन्न उपजाता है, आज आत्महत्या के लिए मजबूर हो गया है. स्पष्ट है कि फसल खराब होने से किसानों को हुई आर्थिक क्षति असहनीय है. लिया गया कर्ज उनके लिए गले की हड्डी बन जाता है. उसे मालूम है कि बड़े–बड़े भाषण देने वाले नेता उनके नुकसान की भरपाई के लिए आगे आने वाले नहीं हैं. नेताओं के माथे पर लगा किसानों की आत्महत्या का कलंक यूं ही मिटने वाला नहीं है. फिर भी ये बड़बोले नेता आत्महत्या की इन घटनाओं से अपने को बचाने के सैकड़ों बहाने ढूंढ़ लेते हैं और कार्यवाही के नाम पर रटे–रटाये वाक्य बोलते हैं. जैसे ये राज्यों को देखना चाहिए, अधिकारियों की लापरवाही है, मीडिया तिल का ताड़ बना रहा है, हमें न सिखाएं कि क्या करना है, पीड़ित परिवार को सहायता दी जायेगी आदि–आदि. लेकिन किसानों की आत्महत्याएं इससे रूकने वाली नहीं है. मौसम की मार, खराब बीज, वन्य प्राणियों द्वारा फसल चरना, कीट प्रकोप, बीमारियां आदि से किसान को अक्सर नुकसान होता है और कभी–कभी तो उपज शून्य मिलती है. ऐसे में निराश किसान को आर्थिक मदद देने सरकार नहीं आती है तो इसके लिए विकल्प क्या बचता है? यदि सरकार समय रहते इसके नुकसान की भरपाई करती तो किसान क्यों आत्महत्या करते? इसे हर हाल में 15 दिनों के भीतर मुआवजा मिल सके इसे सुनिश्चित किया जावे. यदि ये कदम सरकार उठाती है तो निश्चित ही किसानों की आत्महत्याओं को रोका जा सकेगा और सरकार को प्रायश्चित करने का मौका मिल सकेगा. क्या ऐसा होगा?

–सुरेश वाहने (पालक), *दुर्ग, छत्तीसगढ़.*

संघ की रणनीति

कवर स्टोरी–संघ, भाजपा और मोहन भागवत (16 मार्च–22 मार्च 2015) पढ़ा. काफी प्रभावित करने वाली खबर है. संतोष भारतीय ने सही कहा है कि मोहन भागवत नरेन्द्र मोदी को राष्ट्रीय पटल पर नहीं लाना चाहते थे. संघ नहीं चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का कद आरएसएस से बड़ा हो. यदि भाजपा का कोई नेता ऊपर उठने की कोशिश करता है, तो संघ उसे उसके पर कतर देता है. संघ ने भाजपा के कई नेताओं के साथ यही किया है. लेकिन संघ 2014 लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह भाजपा को सत्ता में वापस लाना था, इसलिए मोदी को पटल पर लाया.■

–विवेक तिवारी, *बक्सर, बिहार.*

लघु कथा

मेहनत की कीमत

खुशहालपुर में नारायण नाम का एक अमीर साहूकार रहता था. उसका एक बेटा और एक बेटी थी. लड़की की शादी हुए तीन साल हो गये थे और वह अपने ससुराल में खुश थी. लड़का राजू वैसे तो बुद्धू नहीं था लेकिन गलत संगत में बिगड़ सा गया था. अपने पिता के पास बहुत पैसा है यह उसे घमंड हो गया था. दिनभर अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमना फिरना ही उसे अच्छा लगता था. जैसे–जैसे वह बड़ा हुआ पैसे खर्च करने की आदत बढ़ती गयी और वह अपने दोस्तों के कहने पर पानी की तरह पैसा बहाने लगा.

यह देख नारायण को चिंता होने लगी. उसकी इच्छा थी कि राजू बड़ा हो कर सब कारोबार संभाल ले और वह अपनी पत्नी के साथ तीर्थयात्रा पर निकल जाये. एक दिन उसने गांव के ही एक विद्वान गृहस्थ से सलाह लेने की सोची. दोनों ने मिलकर सलाह मशवरा किया. खूब बातें हुई.

दूसरे दिन नारायण ने राजू को बुलाया और कहा बेटा राजू घर से बाहर जा कर शाम होने तक कुछ भी कमाई करके लाओगे तभी रात का खाना मिलेगा. राजू डर गया और रोने लग गया. उसे रोता देख मां की ममता आड़े आ गई. मां ने राजू को एक रूपया निकालकर दिया. शाम को जब नारायण ने राजू से पूछा तो उसने वह एक रूपया दिखाया. पिता ने वह रूपया राजू को कुएं में फेंकने के लिये कहा. राजू ने बिना हिचकिचाहट वह रूपया फेंक दिया. अब नारायण को अपनी पत्नी पर शक हुआ. उसने पत्नी को उसके भाई के यहां भेज दिया.

दूसरे दिन राजू की वैसे ही परीक्षा ली गयी. इस बार राजू मायके आयी हुई अपनी बहन के सामने गिड़गिड़ाया तरस खा कर उसकी बहन ने भी उसे 5 रूपये दिये. उस दिन भी पिता के कहने पर राजू ने पैसे कुएं में फेंक दिये. फिरसे नारायण को लगा कि दाल में कुछ काला है. उसने अपनी बेटी को ससुराल वापस भेज दिया.

अब तीसरी बार राजू का इम्तहान होना था. अब उसे साथ देने वालों में से ना मां थी ना बहन थी और ना ही कोई दोस्त सामने आया. राजू सारा दिन सोचता रहा. भूख भी लगने लगी थी. राजू काम ढूंढ़ने निकल पड़ा. पीठ पर बोझा उठाकर दो घंटे मेहनत करने के बाद उसे 1 रूपया नसीब हुआ. भूख के मारे वह ज्यादा काम भी नहीं कर पा रहा था. शरीर भी थक कर जवाब देने लग गया था. सो पसीने से भीगा हुआ राजू 1 रूपया लेकर घर पहुंचा.

उसे लग रहा था पिता को अपनी हालत पर तरस आयेगा. लेकिन नारायण ने उसे सबसे पहले कमाई के बारे में पूछा. राजू ने अपना एक रूपया जेब से निकाला. पहले के भांति नारायण ने एक रूपया कूएं में फेंकने के लिये कहा. अब राजू छटपटाया. उसने अपने पिता से कहा एक रूपया कमाने के लिये आज मेरा कितना पसीना बहा है. इसे मैं नहीं फेंक सकता. जैसे ही ये शब्द उसके मुह से निकले, उसे अपनी गलती का अहसास हो गया. नारायण खुश हुआ उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पडी. अब राजू को पैसों की कीमत पता चल गयी है ऐसा सोचकर नारायण भी तीर्थयात्रा की तैय्यारी में जुट गया.

तो बच्चों मेहनत का मोल ऐसे होता है. पसीने की कीमत पसीना बहाकर ही पता चलती हैं. मेहनत पसीने से की गयी कमाई ही खरी कमाई है.■

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर–11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन–201301

आलोचना पर सवाल

अनंत विजय

शुक्रिया तुम्हारा. निर्मला जी (निर्मला जैन) या मर्दतंत्र के कुछ समर्थक अपने विद्वतापूर्ण भाषण से मेरे उपन्यास चाक, की बिक्री और पाठकों में ऐसे ही इजाफा कर देते हैं, जैसे किरन बेदी का एक इंटरव्यू आप की कई सीटों पर जीत मुकर्रर कर देता था. संदर्भ साहित्य गोष्ठियां. ये लिखा है हिंदी की वरिष्ठ लेखिका और उपन्यासकार मैत्रेयी पुष्पा ने अपने फेसबुक वॉल पर. अब इस फेसबुक पोस्ट में जिस तरह से तुलना की गई है, वह बेहद दिलचस्प है. एक उपन्यासकार यानी मैत्रेयी पुष्पा ने एक आलोचक को एक राजनीतिक शख्सियत के बरक्श खड़ा कर दिया. अपने उपन्यास को दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सफलता से जोड़ते हुए उन्होंने आलोचक निर्मला जैन को किरन बेदी से जोड़ दिया. आलोचक निर्मला जैन पर तंज कसते हुए मैत्रेयी ने साफ कर दिया कि उनकी आलोचनाओं से उनके उपन्यास की बिक्री और पाठक दोनों में इजाफा होता है. ऊपर से देखने पर यह बात छोटी और सामान्य लगती है, लेकिन अगर हम गहराई से समकालीन साहित्यिक परिदृश्य पर नजर डालें, तो मैत्रेयी ने अपने तंज के माध्यम से बड़े सवाल खड़े किए हैं. अब अगर उनके शब्दों पर गौर करें. निर्मला जी या मर्दतंत्र के कुछ समर्थक. मैत्रेयी ने अपने शब्दों से हिंदी आलोचना को कठघरे में खड़ा किया है. उन्होंने अपने उपन्यास के आलोचना के बहाने से वरिष्ठ आलोचकों की वाचिक परंपरा पर भी सवाल खड़ा किया है. दो–तीन साल पहले ही निर्मला जैन ने आलोचना के वर्तमान परिदृश्य पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि किसी कृति पर सच कहने में डर लगता है, क्योंकि लेखक बुरा मान जाते हैं. ये बात स्मृति के आधार पर लिखी जा रही है. लिहाजा, शब्दों का हेरफेर हो सकता है, लेकिन भाव बिल्कुल वही हैं. अब देखिए निर्मला जी ने जाने–अनजाने वर्तमान आलोचना की स्थिति को अपने इस वक्तव्य से सामने रख दिया. सवाल तब भी उठे थे और सवाल अब भी उठे हैं कि हिंदी आलोचना क्या इतनी डरपोक हो गई है कि वह लेखकों के नाराज हो जाने के डर से कृतियों पर टिप्पणी करना छोड़ देगी. क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कही जाएगी.

दरअसल, अगर हम समकालीन साहित्य के पिछले बीस–तीस साल के परिदृश्य पर नजर डालते हैं, तो कथा आलोचना के नाम पर लगभग सन्नाटा दिखाई देता है. आलोचना के नाम पर समीक्षात्मक लेख लिखे जा रहे हैं, जिनमें कृतियों पर परिचयात्मक लेख होते हैं. तिस पर से आलोचकों का तुर्रा ये कि वही हिंदी साहित्य की दशा और दिशा तय करते हैं. आलोचकों की इस प्रवृत्ति को कई लेखकों ने भी बढ़ावा दिया, जब वो फौरी सफलता और चर्चा के लिए आलोचकों के आगे हाथ बांधे खड़े होने लगे. आलोचकों में जैसे–जैसे यह प्रवृत्ति बढ़ी तो हिंदी में उखाड़–पछाड़ का खेल शुरू हो गया. सबने अपने–अपने गढ़ और मठ बना लिए और आलोचक मठाधीश की भूमिका में आ गए. सेंसेक्स की तरह कृतियों को उठाने और गिराने का खेल शुरू हो गया. साहित्य बाजार में तब्दील हो गया. नामवर जी ने हिंदी में आलोचना की जिस वाचिक परंपरा को आगे बढ़ाया, उसको कई लोगों ने लपक लिया. बजाए गंभीर अध्ययन, मनन और चिंतन के इस परंपरा को आगे बढ़ाने से हिंदी आलोचना की छवि को ठेस लगी है. नामवर जी का तो अध्ययन इतना गहरा है कि वो जब कुछ कहते हैं, तो उसमें एक संदर्भ भी होता है और मूल्यांकन की दृष्टि भी होती है. नामवर सिंह जिस तरह से लगातार नई पीढ़ी के लेखन से खुद को अपडेट करते हैं, वह उनकी ताकत है. लिहाजा, जब वो बोलते हैं, तो पूरा हिंदी साहित्य सुनता है. नामवर जी ने कहीं कहा भी है– मुझ पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि आलोचना में मैं रणनीति अपनाता हूं. यह भी कहा जाता है कि यदि मैं किसी लेखक का नाम ले लूं या उसके बारे में कुछ कह दूं तो वह मुख्यधारा में स्थापित हो जाता है, जिसे छोड़ देता हूं वह यूं ही पड़ा रहता है. दरअसल, राजनीति में तो हाशिये पर चले जाने से नुकसान होता है, पर साहित्य में हाशिया बहुत महत्वपूर्ण होता है. हमने देखा है कि हिंदी ही नहीं, उर्दू और प्राय: सभी भाषाओं में जो लेखक हाशिये पर रहे थे, आज महत्वपूर्ण लेखक हैं. त्रिलोचन, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह की बात छोड़ भी दें तो निराला और गालिब के साथ यही हुआ. प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि मिल्टन ने तो लिखा भी है–दे ऑल्सो सर्व हू स्टैंड एंड वेट. नामवर सिंह के बाद की पीढ़ी के आलोचक इस हैसियत को हासिल नहीं कर पाए. खासकर कथा आलोचना में तो बिल्कुल ही नहीं. हाशिये को महत्वपूर्ण बताना कोई हंसी–ठट्ठा नहीं है. यह तो अनुभव और अध्ययन से ही संभव है.

नामवर जी ने हिंदी में आलोचना की जिस वाचिक परंपरा को आगे बढ़ाया, उसको कई लोगों ने लपक लिया. बजाए गंभीर अध्ययन, मनन और चिंतन के इस परंपरा को आगे बढ़ाने से हिंदी आलोचना की छवि को ठेस लगी है. नामवर जी का तो अध्ययन इतना गहरा है कि वो जब कुछ कहते हैं, तो उसमें एक संदर्भ भी होता है और मूल्यांकन की दृष्टि भी होती है. नामवर सिंह जिस तरह से लगातार नई पीढ़ी के लेखन से खुद को अपडेट करते हैं, वह उनकी ताकत है. लिहाजा, जब वो बोलते हैं, तो पूरा हिंदी साहित्य सुनता है. नामवर जी ने कहीं कहा भी है–मुझ पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि आलोचना में मैं रणनीति अपनाता हूं. यह भी कहा जाता है कि यदि मैं किसी लेखक का नाम ले लूं या उसके बारे में कुछ कह दूं तो वह मुख्यधारा में स्थापित हो जाता है, जिसे छोड़ देता हूं वह यूं ही पड़ा रहता है.

अब अगर हम मैत्रेयी पुष्पा के कथन पर गौर करें तो वह आलोचना में उन लोगों पर भी निशाना साधती हैं, जो मर्दतंत्र के समर्थक हैं. फेसबुक पोस्ट पर मैत्रेयी पुष्पा से कई लोगों ने यह जानने की भी कोशिश की कि ये मर्दतंत्र समर्थक कौन हैं. जवाब नहीं मिला. अपनी रचनाओं की नायिकाओं के माध्यम से स्त्री विमर्श के नये आयाम गढ़नेवाली मैत्रेयी पुष्पा जब आलोचना में मर्दतंत्र की बात करती हैं, तो वह बड़े सवाल खड़ी करती हैं. हिंदी आलोचना में मर्दतंत्र के उन समर्थकों की पहचान होनी चाहिए. इस पहचान की तलाश में अगर आगे बढ़ते हैं, तो मर्दतंत्र की जड़ें देशभर के हिंदी विश्वविद्यालयों के हिंदी विभागों के आचार्यों के कमरों में मिलती हैं. इन कमरों में बैठे आचार्य विद्वान आलोचक हैं. विद्वान आलोचक (स्कॉलर क्रिटिक) शब्द पहली बार ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी से निकलनेवाले जर्नल–एसेज ऑन क्रिटिसिज्म में सामने आया था और एफ डब्ल्यू वीटसन ने इसका प्रयोग किया था. हमारे देश के विश्वविद्यालयों के हिंदी विभागों में बैठे आलोचक सच में स्कॉलर क्रिटिक यानी विद्वान आलोचक हैं. उनसे पाठालोचन की अपेक्षा ठीक है, वह किताबों का संपादन कर सकते हैं, लेकिन उनसे सर्जनात्मक आलोचना की अपेक्षा नहीं की जा सकती है. हिंदी विभागों के ये स्कॉलर क्रिटिक अपनी महत्ता साबित करने और अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए बहुधा बयानों का सहारा लेते रहते हैं. हिंदी विभागों के इन आलोचकों का समकालीन साहित्य से भी वास्ता रह गया हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता. उनके लिए डॉ रामविलास शर्मा आदर्श हैं, जो कहा करते थे कि वह दूसरों का लिखा नहीं पढ़ते हैं. पढ़े बगैर अपने पूर्व के अध्ययन के आधार पर ज्ञान देकर आज के आलोचक अपने आपको ही एक्सपोज करते हैं. अब वक्त आ गया है कि हिंदी आलोचना खासकर कथा आलोचना के बारे में उसके औजारों और सिद्धांतों के बारे में गंभीरता से विचार हो. मार्क्सवादी आलोचना के औजार भोथरे हो चुके हैं. दुनिया की अलग–अलग भाषाओं में आलोचना की सैद्धांतिकी पर गंभीर बातें होती रही हैं. नये–नये औजार विकसित किए जा रहे हैं, जिसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं. पश्चिम में फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म ने शेक्सपीयर को नये सिरे से एक नई दृष्टि के साथ उद्घाटित किया. वहां से होते हुए जब ये स्त्री विमर्श के रूप में हिंदी साहित्य में पहुंचा, तो राजेन्द्र यादव ने उसको एक अलग ही दिशा में मोड़ दिया. स्त्री विमर्श के आधार पर किसी रचना का समग्रता से मूल्यांकन नहीं हो सका, क्योंकि हमने स्त्री विमर्श के नाम पर कुछ और ही शुरू किया.ये कुछ ऐसा था, जिसमें विमर्श नाम का रह गया. आज की आलोचना के सामने सबसे बड़ा संकट अपने साख को बचाए रखने की है. आलोचकों को एक ऐसी दृष्टि विकसित करनी होगी, जिससे वे रचनाकारों की तरह कृतियों के पार जाकर उसे देख सकें. आलोचकों के सामने यह संकट होता है कि वे रचनाकारों की तरह रचना के पार जाकर देख नहीं पाते हैं, वे तो पाठक के आधार पर अपनी दृष्टि गढ़ते हैं और फिर उसी गढ़ी हुई दृष्टि के आधार पर रचनाओं का मूल्यांकन करते हैं. इसका नतीजा यह होता है कि बहुधा आलोचक कृतियों को खोलने से चूक जाते हैं और जब तक इस चूक को सुधारा जाता है या उसकी कोशिश होती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. अब भी वक्त है कि आलोचना अपनी एक नई शैली नई दृष्टि विकसित करे और व्यक्तिगत आग्रहों और दुराग्रहों से ऊपर उठकर रचना को रचना के स्तर पर देखें और उसका मूल्यांकन करें. इससे कम से कम आलोचना की साख तो बची रहेगी और अगर साख बची रहेगी तो फिर एक विधा के रूप में और मजबूत और समकालीन होने में देर नहीं लगेगी.■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

व्यंग्य

मुण्डन

हरिशंकर परसाई

कि सी देश की संसद में एक दिन बड़ी हलचल मची. हलचल का कारण कोई राजनीतिक समस्या नहीं थी, बल्कि यह था कि एक मंत्री का अचानक मुण्डन हो गया था. कल तक उनके सिर पर लंबे घुंघराले बाल थे, मगर रात में उनका अचानक मुण्डन हो गया था.

सदस्यों में कानाफूसी हो रही थी कि इन्हें क्या हो गया है. अटकलें लगने लगीं. किसी ने कहा, शायद सिर में जूं हो गईं हों. दूसरे ने कहा, शायद दिमाग में विचार भरने के लिए बालों का परदा अलग कर दिया हो. किसी ने कहा, शायद इनके परिवार में किसी की मौत हो गई. पर वे पहले की तरह प्रसन्न लग रहे थे.

आखिर एक सदस्य ने पूछा, अध्यक्ष महोदय! क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय मंत्री महोदय के परिवार में क्या किसी की मृत्यु हो गई है?

मंत्री ने जवाब दिया, नहीं.

सदस्यों ने अटकलें लगाईं कि कहीं उन लोगों ने ही तो मंत्री का मुण्डन नहीं कर दिया, जिनके खिलाफ वे बिल पेश करने का इरादा कर रहे थे.

एक सदस्य ने पूछा, अध्यक्ष महोदय! क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि उनका मुण्डन हो गया है? यदि हां तो क्या वे बताएंगे कि उनका मुण्डन किसने कर दिया है?

मंत्री ने संजीदगी से जवाब दिया, मैं नहीं कह सकता कि मेरा मुण्डन हुआ है या नहीं!

कई सदस्य चिल्लाये, हुआ है! सबको दिख रहा है.

मंत्री ने कहा, सबको दिखने से कुछ नहीं होता. सरकार को दिखना चाहिए. सरकार इस बात की जांच करेगी कि मेरा मुण्डन हुआ है या नहीं.

एक सदस्य ने कहा, इसकी जांच अभी हो सकती है. मंत्री महोदय अपना हाथ सिर पर फेरकर देख लें.

मंत्री ने जवाब दिया, मैं अपना हाथ सिर पर फेरकर हरगिज नहीं देखूंगा. सरकार इस मामले में जल्दबाजी नहीं करती. मगर मैं वायदा करता हूं कि मेरी सरकार इस बात की विस्तृत जांच करवाकर सारे तथ्य सदन के सामने पेश करेगी.

सदस्य चिल्लाये, इसकी जांच की क्या जरूरत है? सिर आपका है और हाथ भी आपके हैं. अपने ही हाथ को अपने सिर पर फेरने में मंत्री महोदय को क्या आपत्ति है?

मंत्री बोले, मैं सदस्यों से सहमत हूं कि सिर मेरा है और हाथ भी मेरे हैं. मगर हमारे हाथ परम्पराओं और नीतियों से बंधे हैं. मैं अपने सिर पर हाथ फेरने के लिए स्वतंत्र नहीं हूं. सरकार की एक नियमित कार्य–प्रणाली होती है. विरोधी सदस्यों के दबाव में आकर मैं उस प्रणाली को भंग नहीं कर सकता. मैं सदन में इस संबंध में एक वक्तव्य दूंगा.

शाम को मंत्री महोदय ने सदन में वक्तव्य दिया–

अध्यक्ष महोदय! सदन में यह प्रश्न उठाया गया कि मेरा मुण्डन हुआ है या नहीं? यदि हुआ है, तो किसने किया है? ये प्रश्न बहुत जटिल है और इस पर सरकार जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले सकती. मैं नहीं कह सकता कि मेरा मुण्डन हुआ है या नहीं. जब तक पूरी जांच न हो जाए, सरकार इस संबंध में कुछ नहीं कह सकती. हमारी सरकार तीन व्यक्तियों की एक जांच समिति नियुक्त करती है, जो इस बात की जांच करेगी. जांच समिति की रिपोर्ट मैं सदन में पेश करूंगा.

सदस्यों ने कहा, यह मामला कुतुबमीनार का नहीं, जो सदियों जांच के लिए खड़ी रहेगी. यह आपके बालों का मामला है, जो बढ़ते और कटते रहते हैं. इसका निर्णय तुरंत होना चाहिए.

मंत्री ने जवाब दिया, कुतुबमीनार से हमारे बालों की तुलना करके उनका अपमान का अधिकार सदस्यों को नहीं है. जहां तक मूल समस्या का संबंध है, सरकार जांच के पहले कुछ नहीं कह सकती.

जांच समिति सालों जांच करती रही. इधर मंत्री के सिर पर बाल बढ़ते रहे.

एक दिन मंत्री ने जांच समिति की रिपोर्ट सदन के सामने रख दी.

जांच समिति का निर्णय था कि मंत्री का मुण्डन नहीं हुआ.

सत्ताधारी दल के सदस्यों ने इसका स्वागत हर्षध्वनि से किया.

सदन के दूसरे भाग से शर्म–शर्म, की आवाजें उठीं. एतराज उठे– यह एकदम झूठ है. मंत्री का मुण्डन हुआ था.

मंत्री मुस्कुराते हुए उठे और बोले, यह आपका ख्याल हो सकता है. मगर प्रमाण तो चाहिए. आज भी अगर आप प्रमाण दे दें तो मैं आपकी बात मान लेता हूं.

ऐसा कहकर उन्होंने अपने घुंघराले बालों पर हाथ फेरा और सदन दूसरे मसले को सुलझाने में व्यस्त हो गया.■

feedback@chauthiduniya.com

उधार मांगने आया दोस्त

वह आएगा तो पहले चुपचाप बैठेगा कुछ देर
बहुत संभावना है कि चाय ठंडी हो जाएगी
जिसे तुम्हारी याद दिलाने पर जल्दी–जल्दी पी लेगा शर्बत की तरह
उससे उसके आने की वजह कभी मत पूछना
यह भले पूछ लेना कि सफ़र में कोई तकलीफ तो नहीं हुई
लम्बे समय से फ़ोन न कर पाने की असमर्थता जताते उस चेहरे में देख लेना उसकी सफाई
बात का विषय बदल देना यह कह कि छोड़ो यार मैंने ही कौन सा तुम्हें फोन किया
उसकी बातों को घुमा–फिरा कर खुद ले आना पैसों की तरफ और पूछ लेना अपने आप
कुछ पैसों की ज़रूरत हो तो बताओ, मेरा एक चेक अभी क्लियर हुआ है कल ही
किसी पुराने दोस्त को उधार मांगते देखना एक यातना है
अगर तुम्हें पहले से पता हो तो कोशिश करना इसे न्यूनतम करने की
दुनिया हर पल बदल रही है
इसमें मौसमों का बदलना शामिल करना और उससे करने लगना गिरते तापमान की बातें
परिवार की सलामती की बात पूछना
उसके स्वाभिमान की शीशे के सामान की तरह रक्षा करना
यहां पंक्ति कोई दूसरी आनी चाहिए लेकिन बात सिर्फ यही है
किसी पुराने दोस्त को उधार मांगते देखना वाकई बहुत बड़ी यातना है

विमल चन्द्र पांडेय

(ज्ञानपीठ नवलेखन पुरस्कार से सम्मानित युवा कथाकार व कवि)

> इसका कैमरा इतना शक्तिशाली है कि वह किसी भी डिजिटल कैमरे से बेहतर प्रदर्शन करता है. इतना ही नहीं यह हमेशा स्टैंडबाई में रहेगा जिससे पलक झपकते ही तस्वीर उतारी जा सकेगी. इस फोन में 32, 64 और 128 जीबी इंटरनल स्टोरेज का विकल्प है. यह कई रंगों में उपलब्ध है.

दुनिया का पहला सिम-फ्री फोन

सोनी ने जापान में अपना पहला सिम फ्री मोबाइल फोन सोनी एक्सपीरिया जे1(j1) कॉम्पैक्ट लॉन्च किया है. इस फोन की खासियत ये है कि इसमें सिम का इस्तेमाल नहीं होगा. इस फोन की कीमत लगभग 30,000 रुपये रखी गई है. Sony Xperia J1 Compact (D5788) कंपनी का पहला एलटीई कम्युनिकेशन प्ले सिम डिवाइस है. ये डिवाइस मोबाइल वर्चुअल ऑपरेटर को सपोर्ट करता है. इसका मतलब इसमें सिम की जरूरत नहीं है और वॉइस कॉल्स और टेक्स्ट मैसेज सभी जापान में एनटीटी डोकोमो द्वारा एक खास पैकेज से दिए जाएंगे. अगर इस फोन को लेना है तो यूजर्स को सिर्फ एनटीटी डोकोमो(NTT DOCOMO) का कनेक्शन ही लेना होगा. इस फोन में 20.7 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है और 2.2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इसके अलावा, इस फोन में 2.2 गीगाहर्ट्ज का क्वाड-कोर प्रोसेसर है. सोनी के इस स्मार्टफोन में 4.3 इंच की स्क्रीन दी गई है. इसके अलावा, इस फोन में 2जीबी रैम मल्टीटास्किंग के लिए दी गई है. ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड किटकैट 4.4.4 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है. 16जीबी मेमोरी के साथ इस फोन में माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट है. कनेक्टिविटी के मामले में 4जी, एलटीई, जीपीएस, वाई-फाई, ब्लूटुथ और एनफीसी जैसे फीचर्स दिए गए हैं. ये फोन 138 ग्राम वजन का है. ये डिवाइस वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ प्रोटेक्शन के साथ आएगा. सोनी का ये फोन भारतीय मार्केट में आता है या नहीं यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन विदआउट सिम वाला फोन अपने आप में एक नया एक्सपेरिमेंट हैं. ■

सैमसंग का सबसे शक्तिशाली स्मार्टफोन

सैमसंग ने अपने शक्तिशाली स्मार्टफोन गैलेक्सी एस6 और गैलेक्सी एस6 एज को भारत में लॉन्च किया है. ये बेहद स्लिम फोन हैं. गैलेक्सी एस6 एज में तीन स्क्रीन हैं. मुख्य स्क्रीन सामने है जबकि दो स्क्रीन किनारों पर हैं. कंपनी का दावा है कि दुनिया में कोई भी फोन इनका मुकाबला नहीं कर सकता है. ये स्मार्टफोन के मानदंड सदा के लिए बदल देंगे.

कंपनी ने गैलेक्सी एस6 के 32 जीबी संस्करण की कीमत 49,900 रुपये और 64 जीबी की कीमत 55,900 रुपये तथा 128 जीबी की कीमत 61,900 रुपये रखी है. गैलेक्सी एज की कीमत 58,900 रुपये है. सैमसंग गैलेक्सी एस6 में दुनिया का पहला 14 एनएम प्रोसेसर है और बेहतर कंप्यूटिंग के लिए यह 64 बिट से लैस है. यह बेहद कार्यकुशल है और बैटरी का उपयोग कम से कम करता है. इसकी बैटरी महज 10 मिनट में चार्ज हो जाती है. इसमें वायरलेस चार्जिंग की भी सुविधा है. इसका कैमरा इतना शक्तिशाली है कि वह किसी भी डिजिटल कैमरे से बेहतर प्रदर्शन करता है. इतना ही नहीं यह हमेशा स्टैंडबाई में रहेगा जिससे पलक झपकते ही तस्वीर उतारी जा सकेगी. इस फोन में 32, 64 और 128 जीबी इंटरनल स्टोरेज का विकल्प है. यह कई रंगों में उपलब्ध है. इसका कैमरा 16 एमपी का है और कम रोशनी में भी बेहतरीन तस्वीर उतारता है. इसके लिए यह महज 0.7 सेकेंड का समय लेता है. इसके फ्रंट कैमरे से सेल्फी वीडियो बनाना बहुत ही आसान है. ■

कारों से भी महंगी बाइक्स

यह बाइक 1,131 सीसी की है. इसमें इन लाइन थ्री सिलेंडर, फोर स्ट्रोक और लिक्विड कूल्ड पॉवर प्लांट है. यह 10,200 आरपीएम पर 155.6 बीएचपी की जबर्दस्त ताकत पैदा करता है. कीमत के लिहाज से दूसरी सबसे महंगी बाइक है बेनेली टीएनटी 899 और यह रफ्तार के शौकीनों के लिए है. यह नेकेड मोटर साइकिल है और स्पोर्ट्स बाइक है. इसमें लिक्विड कूल्ड पॉवर प्लांट है और इसका इंजन 898 सीसी का है. बेनेली टीएनटी 600 जीटी की कीमत 5.63 लाख रुपये है और यह 600 सीसी इंजन से लैस है.

बाइक्स के शौकीनों के लिए देश में एक से बढ़कर एक बाइक्स आ गई हैं. भारतीय कंपनी डीएसके मोटोव्हील्स ने इतालवी कंपनी बेनेली के साथ मिलकर पांच शानदार बाइकें लॉन्च की हैं. लेकिन ये मोटर साइकिलें प्रीमियम क्लास की हैं और इनकी कीमत 2.83 लाख रुपये से 11.81 लाख रुपये तक है. इनमें सबसे महंगी बाइक बेनेली टीएनटी 1130 है जिसकी कीमत 11.81 लाख रुपये है. यह बाइक 1,131 सीसी की है. इसमें इन लाइन थ्री सिलेंडर, फोर स्ट्रोक और लिक्विड कूल्ड पॉवर प्लांट है. यह 10,200 आरपीएम पर 155.6 बीएचपी की जबर्दस्त ताकत पैदा करता है. कीमत के लिहाज से दूसरी सबसे महंगी बाइक है बेनेली टीएनटी 899 और यह रफ्तार के शौकीनों के लिए है. यह नेकेड मोटर साइकिल है और स्पोर्ट्स बाइक है. इसमें लिक्विड कूल्ड पॉवर प्लांट है और इसका इंजन 898 सीसी का है. बेनेली टीएनटी 600 जीटी की कीमत 5.63 लाख रुपये है और यह 600 सीसी इंजन से लैस है. इसे भार ढ़ोने के उपयुक्त बनाया गया है. बेनेली टीएनटी 600 आई की कीमत 5.15 लाख रुपये है और यह स्पोर्टी लुक वाली बाइक है. इसका फोर स्ट्रोक इंजन 300 सीसी का है और यह 11,500 आरपीएम पर 36.2 बीएचपी की ताकत देता है. बेनेली की सबसे सस्ती बाइक है टीएनटी 300 और इसकी कीमत 2.83 लाख रुपये है. यह भी फोर स्ट्रोक 300 सीसी के इंजन से लैस है. कंपनी ने इनकी बिक्री के लिए अपने एक्सक्लुसिव शो रूम बनाए है. इसके अलावा वह कुछ और शो रूम बनाने की तैयारी में है. ■

2000 रु. से कम कीमत के मल्टी फीचर्स हेडफोन

अगर आप गाना सुनने के शौकीन हैं, तो आप अपने शौक को वायरलेस हेडफोन से पूरा कर सकते हैं. ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पर वायरलेस हेडफोन पर कई अच्छे ऑफर मिल जाते हैं. ऐसे में कम कीमत का अच्छा हेडफोन आपके संगीत को और मजेदार बना सकता है. सबसे अच्छी बात यह है कि इन हेडफोन को कम्प्यूटर और मोबाइल दोनों पर ब्लूटुथ से कनेक्ट करके इस्तेमाल किया जा सकता है. हम आपको ऐसे ही ब्लूटुथ हेडफोन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी कीमत भी 2000 रुपए से कम है. ■

नोकिया बीएच-503 वायरलेस ब्लूटुथ हेडफोन

नोकिया कंपनी के इस ब्लूटुथ वायरलेस हेडफोन को यूजर्स ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स से 1,198 रुपये में खरीद सकते हैं. इसका मॉडल नंबर बीएच-503 है. खूबसूरत डिजाइन वाला ये नोकिया वायरलेस हेडफोन ब्लैक कलर में उपलब्ध है. इस हेडफोन में म्यूजिक को कंट्रोल करने के लिए प्ले, पॉज, नेक्स्ट, प्रीवियस के बटन दिए हैं. इतना ही नहीं, इससे वॉल्यूम को भी कंट्रोल किया जा सकता है. इन सब के साथ, आपके मोबाइल पर कॉल आता है तो हेडफोन की मदद से उसे अटैंड किया जा सकता है. म्यूजिक सुनने या बात करने के दौरान ये 8 घंटे का बैकअप देता है. ये हेडफोन उन सभी मोबाइल के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, जिनमें ब्लूटुथ मौजूद है. वहीं, कम्प्यूटर या लैपटॉप पर भी इसे ब्लूटुथ की मदद से कनेक्ट किया जा सकता है. ■

आईबॉल विब्रो बीटी 02 वायरलेस ब्लूटुथ हेडफोन

आईबॉल कंपनी के इस ब्लूटूथ वायरलेस हेडफोन को यूजर्स ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स से 1,449 रुपये में खरीद सकते हैं. इसका मॉडल नंबर विब्रो बीटी02 है. यह वायरलेस हेडफोन ब्लैक कलर में उपलब्ध है. म्यूजिक सुनने के साथ इस हेडफोन से आप बात भी कर सकते हैं. 3 घंटे में इस हेडफोन को फुल चार्ज करके 10 से 11 घंटे का बैकअप लिया जा सकता है. करीब 10 मीटर की रेंज में भी इससे क्लियर आउटपुट मिलता है. हेडफोन में म्यूजिक को कंट्रोल करने के लिए प्ले, पॉज, नेक्स्ट, प्रीवियस के बटन दिए हैं. इतना ही नहीं, इससे वॉल्यूम को भी कंट्रोल किया जा सकता है. यह हेडफोन उन सभी मोबाइल के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, जिनमें ब्लूटुथ मौजूद है. वहीं, कम्प्यूटर या लैपटॉप पर भी इसे ब्लूटुथ की मदद से कनेक्ट किया जा सकता है. ■

टीम इंडिया ने गंवा दिया मौका

नवीन चौहान

विश्व कप में टीम इंडिया का विजय रथ सेमी–फाइनल में आकर रुक गया. भारतीय टीम को मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 95 रनों से मात दी. 328 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही भारतीय टीम 47 वें ओवर में 233 रनों पर ढेर हो गई. सेमी–फाइनल से पहले भारतीय टीम ने सात मैच खेले और सातों मैचों में विजयी रही. यह भारतीय टीम के विश्वकप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक है. भारतीय टीम एक भी मैच हारे बगैर सेमीफाइनल तक पहुंची. विश्वकप से पहले गेंदबाजी को टीम इंडिया की सबसे कमजोर कड़ी माना जा रहा था, लेकिन गेंदबाजों ने ऐसी सभी धारणाओं को गलत ठहराते हुए बेहतरीन गेंदबाजी की और सबको अचंभे में डाल दिया. भारतीय गेंदबाजों ने पहले सात मैचों में 70 विकेट चटकाए. सेमी–फाइनल मुकाबले में भी गेंदबाज सात ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने में कामयाब रहे. लेकिन इस बार उन्हें इसके लिए ज्यादा रन खर्च करने पड़े. सेमी फाइनल में गेंदबाजी में वो पैनापन दिखाई नहीं दिया जैसा पिछले सात मैचों में दिखाई दिया था.

टीम इंडिया विश्वकप खेल रही दूसरी टीमों के खिलाफ तो बीस साबित हुई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उसके सामने इक्कीस साबित हुई. भारतीय खिलाड़ियों ने टेस्ट और त्रिकोणीय सीरीज की असफलता से उबरते हुए विश्व कप में बेहतरीन वापसी की. खिलाड़ियों का साझा प्रयास टीम को सेमीफाइनल तक ले गया, लेकिन उनका यह प्रयास विश्व खिताब बचा पाने के लिए नाकाफी था. कुल मिलाकर विश्व कप में टीम इंडिया के प्रदर्शन को अच्छा कहा जा सकता है लेकिन बेहतरीन नहीं. भारतीय टीम के सामने ग्रुप स्टेज से नॉकऑउट स्टेज तक कोई ऐसी चुनौती नहीं आई, जिससे उसकी कमियां और कमजोरियां उजागर होतीं. हर मैच में कोई एक खिलाड़ी मैच निकाल ले गया और टीम की कमजोरियां छिपी रह गईं. अंततः यही सेमीफाइनल में टीम इंडिया की हार की प्रमुख वजह बना. टॉस की भी सेमी फाइनल में निर्णायक भूमिका रही. यदि भारतीय टीम टॉस जीत जाती तो परिणाम कुछ अगल होता. प्रशंसक मायूस जरूर हैं लेकिन उन्हें इस बात का संतोष है कि टीम इंडिया अपने से बेहतर टीम से हारी.

चार महीने तक ऑस्ट्रेलिया में गुजारना टीम इंडिया के लिए बेहद फायदेमंद रहा. ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों के अनुरूप बेहतर तरीके से ढलने की वजह से टीम इंडिया ने दूसरी टीमों के खिलाफ टीम इंडिया ने जीत हासिल की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वह जीत का मंत्र ढूंढ पाने में नाकामयाब रही. गेंदबाज दूसरी टीमों के खिलाफ लय में दिखाई दिये लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने आते ही गेंदबाजी एक बार फिर पटरी से उतर गई. सेमी–फाइनल से पहले विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी सेमी फाइनल में 68 रन खर्च करके एक विकेट भी नहीं ले सके. वहीं उमेश यादव एक बार फिर लेग स्टंप के बाहर गेंद करते दिखाई दिए. भले ही उन्होंने मैच में चार विकेट लिए लेकिन इसके लिए उन्होंने 72 रन लुटाए. मोहित शर्मा खुश किस्मत रहे कि इंशात शर्मा और भुवनेश्वर कुमार विश्व कप से ठीक पहले चोटिल हो गए और उन्हें विश्व कप में खेलने का सुनहरा मौका मिल गया. उन्होंने विश्वकप में सभी मैच खेले और ऐन मौकों पर टीम को सफलता भी दिलवाई. लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने भी 75 रन देकर 2 विकेट लिए. जब किसी टीम के स्ट्राइक बॉलर बड़े मैच में इतने ज्यादा रन लुटायें तो टीम के जीतने की संभावनायें पहले ही धूमिल हो जाती हैं. सेमी–फाइनल में अश्विन ने कुछ सधी हुई गेंदबाजी की, नहीं तो ऑस्ट्रेलियाई स्कोर और भी बड़ा होता. दूसरी टीमों को भारतीय गेंदबाजों की लेंथ के बारे में ज्यादा समझ नहीं थी, इसी वजह से वे उनके खिलाफ सफल हुए. लेकिन इन चार महीनों में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ इतने अभ्यस्त हो गए, उन्हें भारतीय गेंदबाजों का सामना करने में किसी तरह की परेशानी नहीं हुई. ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज पिछले मैच से आगे खेलने उतरे हों. जिन शॉर्ट पिच गेंदों पर भारतीय तेज गेंदबाजों ने विश्वकप में सबसे ज्यादा(25 प्रतिशत) विकेट हासिल किए. उनका वह हथियार भी स्टीव स्मिथ और एरोन फिंच जैसे बल्लेबाजों के सामने बेअसर साबित हुआ.

कहते हैं कि अंत भला तो सब भला. ऐसा भारतीय टीम के लिए नहीं हो सका. चार महीने पहले टेस्ट मैचों से शुरू हुआ हार का सिलसिला विश्व कप सेमी–फाइनल तक बदस्तूर जारी रहा. विश्वकप में भी भारतीय टीम का आगाज ऑस्ट्रेलिया से अभ्यास मैच हार के साथ हुआ था और अंत भी सेमी–फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों ही हार से हुआ. टीम इंडिया आस्ट्रेलिया के सामने मानसिक तौर पर हारी हुई दिखाई दी. सेमीफाइनल में 327 रनों का पीछा करते हुए भारतीय टीम पहले 12 ओवरों तक तो मैच में बनी रही, लेकिन शिखर धवन और विराट कोहली के लापरवाही भरे शॉट खेलकर ऑउट होते ही टीम का हौसला पस्त हो गया. इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को उबरने का मौका नहीं दिया, पूरी टीम 47 वें ओवर में 233 रनों पर ढेर हो गई. भारतीय शेर कंगारूओं के सामने पस्त हो गए. भारतीय टीम के साथ ऐसा ही कुछ 2003 के विश्वकप में भी हुआ था. टीम इंडिया को उस विश्व कप में भी केवल दो हार मिली थीं. दोनों मैच में ऑस्ट्रेलिया ने ही भारत को मात दी थी. 2015 में भी वही इतिहास दोहराया गया है. पहले अभ्यास मैच से लेकर सेमी–फाइनल तक टीम इंडिया को दो हार मिलीं. दोनों बार ऑस्ट्रेलिया ने ही भारत को हराया.

टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार महीने लंबे दौरे में एक भी मैच नहीं जीत सकी. इसका सीधा मतलब यह है कि खिलाड़ियों ने अपनी खामियों में सुधार नहीं किया न ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के लिए कोई प्रभावशाली योजना भी नहीं बन सकी. टीम इंडिया के गेंदबाजों के पास टेस्ट सीरीज के हीरो रहे स्टीव स्मिथ का एकबार फिर तोड़ नहीं था. स्मिथ ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के खिलाफ शतकीय पारी खेली. उन्होंने 11 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 93 गेंदों पर 105 रन बनाये. उनकी एरोन फिंच के साथ दूसरे विकेट के लिए हुई शतकीय साझेदारी मैच को टीम इंडिया से दूर ले गई. स्टीव स्मिथ दिसंबर 2014 से सेमी–फाइनल तक भारत के खिलाफ 921 रन बना चुके हैं. पुराने रिकॉर्ड भी भारत के विरुद्ध थे. सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया नहीं हारा है. प्रशंसकों को अनहोनी को होनी करने वाले कप्तान धोनी पर यकीन था कि वो टीम इंडिया को लगातार दूसरी बार विश्व चैंपियन बनायेंगे, लेकिन इस बार उनका जादू नहीं चल सका. कहा जाता है कि फुटबॉल इज गेम ऑफ पॉवर, हॉकी इज गेम ऑफ ट्रिक एंड क्रिकेट इज गेम ऑफ चांस. इस गेम ऑफ चांस में भारतीय कप्तान टॉस हार गये और बड़े स्कोर के आगे टीम इंडिया बैकफुट पर चली गई. कई लोगों को विश्व कप से पहले यह आशा भी नहीं थी कि टीम इंडिया विश्व कप सेमीफाइनल तक पहुंच भी पाएगी, लेकिन टीम ने सभी को गलत ठहराते हुए अच्छा प्रदर्शन किया. धोनी को सेमी–फाइनल में हारने का मलाल भले न हो, लेकिन उन्हें इस बात का मलाल लंबे समय तक रहेगा कि वो एक लंबे दौरे में ऑस्ट्रेलिया को एक बार भी पटखनी नहीं दे सके. मशहूर शायर मिर्जा ग़ालिब ने कहा था, ***न हो मरना तो फिर जीने का मज़ा क्या है***, यानी अगर मौत नहीं होगी तो जिंदगी का लुत्फ नहीं उठाया जा सकता है, उसी तरह खेल में हार के बाद जीत और जीत के बाद हार न हो तो खेल का मजा क्या है.■

navinonline2003@gmail.com

कैसा रहा टीम इंडिया का विश्व कप का सफर

भारत ने आईसीसी विश्व कप–2015 में शुरुआत धमाकेदार तरीके से की. भारत को ग्रुप बी में जगह दी गई थी. पूल बी में भारत के साथ पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका, वेस्टइंडीज, जिंबाब्वे, युएई और आयरलैंड की टीमें थीं. टीम इंडिया ने विश्व कप खिताब बचाने के मिशन का आगाज 15 फरवरी को एडिलेड में चिरप्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत से किया. भारतीय टीम शानदार गेंदबाजी और बेहतरीन फील्डिंग के बल पर पाकिस्तान को 76 रनों से मात दी और विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ अजेय रहने का रिकॉर्ड कायम रखा. पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत से भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार मिली हार की वजह से टूटा मनोबल वापस लौट आया. इसके बाद भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के साथ हुआ, जिसके खिलाफ टीम इंडिया विश्व कप में कभी जीत नहीं दर्ज कर सकी थी. पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत का मोमेंटम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी जारी रहा और भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 130 रनों से मात देकर ग्रुप में नंबर एक पर रहने के संकेत दे दिए. भारत ने विश्वकप का तीसरा मैच पर्थ में यूएई के खिलाफ खेला. टीम इंडिया ने यूएई को 9 विकेट से हरा दिया है. यूएई के 102 रनों के जवाब में भारत ने 9 विकेट रहते ही 19वें ओवर में मैच जीत लिया. इसके बाद पर्थ में ही वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने 182 रनों का पीछा करते हुए छह विकेट के नुक्सान पर लक्ष्य हासिल कर लिया. वेस्टइंडीज को 4 विकेट से हराते ही टीम इंडिया का क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का रास्ता साफ हो गया. इसके साथ ही विश्व कप में भारत ने लगातार चौथी जीत भी दर्ज की. अपने पांचवें लीग मैच में आयरलैंड के खिलाफ खेलते हुए भारत ने आयरलैंड को 259 रनों पर समेट दिया और लक्ष्य का पीछा करते हुए 37 वें ओवर में दो विकेट के नुक्सान पर यह लक्ष्य हासिल कर लिया. इसके बाद टीम इंडिया ने अपने आखिरी लीग मैच में जिम्बाब्वे को 6 विकेट से मात दी और विश्वकप में जीत का सिक्सर जड़ा. इस मैच में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं होने के बावजूद रैना और धोनी की 196 रन शानदार साझेदारी ने टीम इंडिया की नैया पार लगाई. बांग्लादेश के खिलाफ मेलबर्न में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुक्सान पर 302 रन बनाये. इसके बाद बांग्लादेश को गेंदबाजों ने 193 रनों पर ढेर कर दिया और लगातार दूसरी बार विश्वकप के सेमी–फाइनल में जगह बनाई.■

धोनी फिलहाल संन्यास नहीं लेंगे

टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने विश्व कप के सेमी-फाइनल में हार के बाद संन्यास के सवाल पर कहा कि मैं अभी केवल 33 साल का हूं, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूं. इसके बाद 2016 में होने वाले टी–20 विश्वकप पर फोकस करूंगा. 2019 का विश्वकप मैं खेलूंगा या नहीं इसका निर्णय मैं भारत में खेले जाने वाले टी–20 विश्वकप के बाद करूंगा. धोनी ने 2011 और 2015 के विश्वकप को मिलाकर विश्वकप में लगातार 11 मैच जीतने का नया भारतीय रिकॉर्ड बनाया. इससे पहले यह रिकॉर्ड सौरव गांगुली के नाम दर्ज था. इसके साथ ही धोनी ने अपनी कप्तानी में 100 से ज्यादा एक दिवसीय मैच जीतने वाले विश्व के तीसरे कप्तान होने का गौरव हासिल किया. धोनी ने अपनी बल्लेबाजी के बल पर वेस्टइंडीज और जिंबाब्वे के खिलाफ मैचों में भारतीय जीत में अहम योगदान दिया.■

टॉप भारतीय बल्लेबाज

खिलाड़ी	मैच	पारी	रन	औसत	शतक	अर्धशतक	उच्चतम
शिखर धवन	8	8	412	51.50	2	1	137
रोहित शर्मा	8	8	330	47.14	1	2	137
विराट कोहली	8	8	305	50.83	1	0	107
सुरेश रैना	8	6	284	56.80	1	2	110*
महेंद्र सिंह धोनी	8	6	237	59.25	0	2	85*
अजिंक्य रहाणे	8	7	208	34.66	0	1	79

भारतीय गेंदबाज

गेंदबाज	मैच	ओवर	मेडन	विकेट	औसत	इकोनॉमी	बेस्ट
उमेश यादव	8	64.25	5	18	17.83	4.98	4/31
मोहम्मद शमी	7	61.0	7	17	17.29	4.81	4/35
मोहित शर्मा	8	63.0	4	13	24.15	4.98	3/48
आर अश्विन	8	77.0	6	13	25.38	4.28	4/25
रविंद्र जड़ेजा	8	66.4	0	09	39.66	5.35	2/23

हार का ठीकरा अनुष्का पर

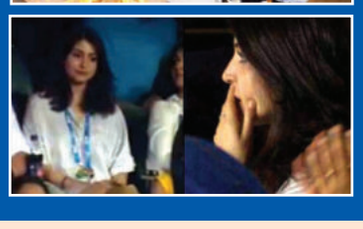

भारत में क्रिकेट को धर्म की तरह माना जाता है. जब टीम इंडिया ने साल 2011 में विश्व कप जीता था, आम से लेकर खास तक हर कोई सड़क पर जीत का जश्न मनाता नज़र आ रहा था. लेकिन इस बार जब सेमी–फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया के सामने हार का सामना करना पड़ा. विराट कोहली केवल एक रन बनाकर आउट हो गए. दर्शकों ने इसकी वजह सेमी–फाइनल देखने सिडनी पहुंची विराट की गर्ल फ्रेंड अनुष्का पर फूटा. अभिनेता कमाल खान ने बेवकूफी भरा ट्वीट करके प्रशंसकों से अनुष्का के घर पर पत्थर फेंकन की अपील कर डाली. कुछ ऐसा ही साल 1996 के विश्वकप में भी हुआ था. सेमी–फाइनल में भारत श्रीलंका से हार गया था. प्रशंसकों ने इसके लिए कप्तान अजहरुद्दीन की प्रेमिका और अभिनेत्री संगीता बिजलानी को जिम्मेदार ठहराया था. मैच से पहले भी अनुष्का और विराट को लेकर कई तरह के मैसेज सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर शेयर हो रहे थे, लेकिन हार के बाद उन संदेशों का कैरेक्टर ही बदल गया. प्रशंसकों ने उसे भद्दा स्वरूप दे दिया और सारी हदें पार कर दीं. यह बेहद शर्मनाक और निंदनीय है यह महिलाओं के खिलाफ पुरुषों की दुर्भावना को दिखाता है. इसके बाद इस मामले को लेकर क्रिकेट से अलग महिलाओं के सम्मान को लेकर बहस छिड़ गई. ■

बॉयोपिक से वापसी करेंगी विद्या

विद्या बालन ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने अभिनय के बल पर एक ख़ास जगह बनाई है. लेकिन पिछले एक साल विद्या दूसरी अभिनेत्रियों से पिछड़ती दिखीं. बॉबी जासूस और शादी के साइड इफैक्ट्स जैसी असफल फिल्मों के बाद विद्या थोड़ा ब्रेक लेती दिखीं. लिहाजा, उम्मीद की जा रही है कि विद्या एक बार फिर जोरदार वापसी करेंगी. सिल्क स्मिता के किरदार को पर्दे पर उतारने के बाद विद्या एक बार फिर बॉयोपिक फिल्म में नज़र आने वाली हैं. विद्या बॉयोपिक को लेकर हमेशा उत्साहित रहती हैं. विद्या इस बार बॉयोपिक में सुचित्रा सेन का किरदार निभायेंगी. सुचित्रा सेन की गिनती भारतीय सिनेमा की सबसे टैलेंटेड और ख़ूबसूरत एक्ट्रेस में होती है. ऐसे तो विद्या के पास एक साथ दो बॉयोपिक के ऑफर थे, जिसमें एक पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पर थी, जबकि दूसरी सूचित्रा सेन पर. विद्या ने बेनजीर की बॉयोपिक को न कह दिया, जिसके बाद उस फिल्म के लिए रवीना टंडन को फाइनल किया गया है. वहीं, सुचित्रा सेन के किरदार को निभाने के लिए विद्या काफी उत्साहित हैं. सुचित्रा सेन की नातिनों रायमा और रिया ने काफी पहले इस बारे में बात की थी कि उनकी नानी पर फिल्म की योजना है. लिहाजा, जब विद्या से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी. ख़बरों के अनुसार, विद्या इन दिनों कत्थक भी सीख रही हैं. सुचित्रा सेन अपने जमाने की मशहूर डांसर थीं. फिलहाल, विद्या बालन इमरान हाशमी के साथ अपनी फिल्म हमारी अधूरी कहानी की शूटिंग में व्यस्त हैं. ■

कंगना बनीं राष्ट्रीय पुरस्कारों की क्वीन

62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म	कोर्ट
सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय	फिल्म मैरी कॉम
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता	विजय (नानू अवनल्ला अवालू-कन्नड़)
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री	कंगना राणावत (क्वीन)
सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री	बलजिंदर कौर (पगड़ी द ऑनर)
सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता	बॉबी सिम्हा(जिगर ठंडा)
सर्वश्रेष्ठ निर्देशन	श्रीजीत मुखर्जी (शोतूशकोन) (बंगला)
सर्वश्रेष्ठ गायक (मेल)	सुखविंदर सिंह
सर्वश्रेष्ठ गीतकार	एनए मुथुकुमार (सैवम)
बेस्ट डायलॉग	विशाल भारद्वाज(हैदर)
बेस्ट म्यूज़िक	विशाल भारद्वाज(हैदर)
बेस्ट कॉस्टयूम	डॉली आहलुवालिया(हैदर)
बेस्ट कोरियोग्राफी	सुदेश अदाना (हैदर)

62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हो गई. इसमें वर्ष 2014 में भारतीय सिनेमा के लिए सर्वश्रेष्ठ योगदान देने वाले लोगों और फिल्मों को पुरस्कृत किया जाएगा. क्वीन, हैदर और मैरीकॉम ने राष्ट्रीय पुरस्कारों में कई पुरस्कार बटोरे हैं. चैतन्य तम्हाने की फिल्म कोर्ट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया. अन्य फिल्म पुरस्कारों में सफलता के झंडे गाड़ चुकी विकास बहल की कंगना रानावत स्टारर फिल्म क्वीन राष्ट्रीय पुरस्कारों में भी छाई रही. क्वीन को बेस्ट हिन्दी फिल्म और कंगना रानावत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया. यह कंगना का दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है. इससे पहले कंगना को साल 2010 में फिल्म फैशन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था. बेस्ट ऐक्टर का पुरस्कार कन्नड अभिनेता विजय को दिया जाएगा. उन्हें कन्नड फिल्म नानू अवनल्ला अवालू में भावनात्मक किरदार अदा करने के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया. इस दौड़ में उन्होंने पीके के लिए आमिर खान, हैदर के लिए शाहिद कपूर और मुन्नारिईपू के लिए ममूटी को पीछे छोड़ा. फिल्म मैरीकॉम को सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक फिल्म चुना गया है. भारतीय न्याय व्यवस्था की खामियों पर केंद्रित फिल्म कोर्ट राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराही गई है. विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध उपन्यास हैमलेट पर बनी शाहिद कपूर अभिनीत हैदर को भी पांच पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई. हैदर को सर्वाधिक राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं. बेस्ट डायलॉग और म्यूज़िक के लिए विशाल भारद्वाज, बेस्ट कॉस्टयूम के लिए डॉली आहलुवालिया, बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए सुदेश अदाना और फिल्म के बिस्मिल गीत के लिए सुखविंदर सिंह को सर्वश्रेष्ठ गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा.

सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार बांग्ला फिल्मकार श्रीजीत मुखर्जी की झोली में फिल्म चतुष्कोण के लिए गया. चतुष्कोण को सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी और स्क्रीनप्ले (मूल) के लिए भी सम्मानित किया जाएगा. मलयाली फिल्म नाइनटीन ऐटी थ्री के लिए गोपी सुंदर को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व संगीत के राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा. सर्वश्रेष्ठ गीतकार के सम्मान से तमिल फिल्म सैवम में गीत लिखने वाले एनए मुथुकुमार को पुरस्कृत किया जाएगा. इसके गीत अझागु के लिए गायिका उत्तरा उन्नीकृष्णन सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का खिताब पाने में सफल रहीं. इस बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए हरियाणवी एक्ट्रेस बजिंदर कौर को चुना गया है. यह किसी हरियाणवी अभिनेत्री का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार है. किसी निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार बांग्ला फिल्म आशा जओआर माझे के लिए आदित्य विक्रम सेनगुप्ता के नाम रहा. पर्यावरण संरक्षण की श्रेणी में सबसे अच्छी फिल्म मलयालम भाषा की फिल्म उत्ताल रही. ■

शशिकपूर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार

भारत सरकार ने मशहूर फ़िल्म अभिनेता और निर्माता शशि कपूर को फिल्मों में उनके योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की है. शशि कपूर का जन्म 18 मार्च, 1938 में कोलकाता में हुआ था. उनसे पहले उनके पिता पृथ्वीराज कपूर और बड़े भाई राज कपूर को भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है. वह यह पुरस्कार पाने वाले कपूर खानदान के तीसरे सदस्य हैं. अभिनेता के रूप में जब जब फूल खिले, आ गले लग जा, रोटी, कपड़ा और मकान, सत्यम शिवम सुंदरम, शर्मीली, दीवार, कभी-कभी, नमक हलाल, और सिलसिला उनके करियर की प्रमुख फ़िल्में रहीं. दीवार फिल्म का उनका डॉयलॉग मेरे पास मां है हिन्दी फिल्मों के सबसे लोकप्रिय डॉयलाग में से एक है. इस फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन थे, जिनके साथ उनकी जोड़ी काफी हिट थी. अभिनय के साथ-साथ शशि कपूर ने कई फ़िल्मों का निर्माण भी किया जिनमें जुनून, कलियुग, उत्सव और विजेता प्रमुख हैं.

शशि कपूर करीब तीन साल से बीमार हैं. उन्हें एक समय तो सप्ताह में दो बार डायलिसिस कराना पड़ता था. आज भी हर महीने तकरीबन दस दिन वह अस्पताल में ही गुजारते हैं. शशि कपूर की फिल्म 36 चौरंगी लेन ऑस्कर के लिए भेजी गई थी. उसे श्रेष्ठ फिल्म माना गया, लेकिन ऑस्कर इसलिए नहीं दिया जा सका, क्योंकि उसे फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में भेजा गया था और अंग्रेजी में बनी होने के कारण अमेरिका में उसे फॉरेन कैटेगरी की फिल्म नहीं माना गया. शशि कपूर ने शेक्सपिएराना थिएटर में ज्योफ्रे कैंडल के मार्गदर्शन में अंग्रेजी नाटकों में अभिनय किया. उनकी पहली फिल्म इस्माइल मर्चेंट और आइवरी जेम्स की हाउसहोल्डर भी अंग्रेजी में हैं. उनका स्वाभाविक रुझान हमेशा अंग्रेजी नाटकों के प्रति रहा. उनकी फिल्म जुनून को साल 1978 की सर्वश्रेष्ठ हिन्दी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था. ■

कलाकार हूं, हीरोइन नहीं चित्रांशी

चौथी दुनिया ब्यूरो

आपको चक दे इंडिया की छोटे कद की हरियाणवी लड़की कोमल चौटाला तो याद ही होगी. उनका असली नाम चित्रांशी रावत है. वह उत्तराखंड के देहरादून की रहने वाली हैं. असल जिंदगी में एक राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रह चुकीं रावत ने आठ साल पहले फिल्म चक दे इंडिया से अपने फिल्मी करियर की बेहतरीन शुरुआत की थी. आठ साल बाद उन्हें हालिया रिलीज फिल्म ब्लैक होम में लीड एक्ट्रेस की भूमिका अदा करने का मौका मिला है. चित्रांशी ने चक दे इंडिया में हॉकी उठाई, फैशन में अपना जादू चलाया, लक में भाग्य आजमाया और अब ब्लैक होम में तीखी मिर्ची बनी हैं.

चित्रांशी को अब तक बॉलीवुड में जो भी किरदार मिले हैं, तकरीबन सभी में उन्हें टॉमबॉय के रूप में ही दिखाया गया है. इस बार भी वह कुछ उसी तरह की भूमिका में हैं, लेकिन इस बार वह लीड रोल में हैं. हां एक बात जो खास है, वह यह कि मिर्ची का किरदार उनके पहले के किरदारों से जरा हट के है. उनके किरदार में थोड़ा नयापन है. हालांकि इस किरदार को एक लड़के को दिमाग़ में रख कर लिखा गया था. निर्देशक को विश्वास था कि चित्रांशी इस किरदार को बखूबी निभा सकती हैं. हालांकि इस तरह के किरदार उन्हें सूट करते हैं, क्योंकि उनका वास्तविक हाव-भाव भी टॉमबॉय की तरह ही है.

राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रह चुकीं चित्रांशी अपने हॉकी के जुनून के कारण ही बॉलीवुड में पहुंचीं. फिल्म चक दे इंडिया में कोमल चौटाला के किरदार ने उन्हें रातों-रात एक जाना-पहचाना चेहरा बना दिया था. इसके बाद उन्हें मधुर भंडारकर की अवॉर्ड विनिंग फिल्म फैशन में काम करने का मौका मिला. फैशन में उन्होंने सोमू नाम के फैशन कॉर्डिनेटर का किरदार अदा किया और अपने अभिनय की छाप छोड़ी. मधुर भंडारकर के साथ फैशन में काम करने के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि वह एक्टिंग कर सकती हैं. यह फिल्म उनके जीवन का एक अहम मोड़ साबित हुई. अब उन्हें फिल्म जगत में होने से खुशी होती है, लेकिन उन्हें इस बात का मलाल है कि हॉकी में देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाईं.

फिल्म ब्लैक हाउस में उनके कैरेक्टर को मिर्ची नाम दिया गया है और वह अपनी भूमिका से न्याय करते हुए तीखी नज़र भी आई हैं. फिल्म में उनका किरदार समाज के उस स्याह पक्ष को दिखाता है, जो अपनी कजन का रेप करने की कोशिश कर रहे अपने सगे भाई की हत्या कर रिमांड होम की सजा काट रही हैं. वह फिल्म में एक बिंदास किरदार में हैं और रिमांड होम में सजा काटने आईं कमजोर लड़कियों की मदद करती हैं. साथ ही वह जेल प्रशासन से नफरत करती हैं, जो यहां की लड़कियों से वैश्यावृत्ति जैसे अवैध काम करवाता है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य दबी और कमजोर लड़कियों की मदद करना ही है. आशीष देव की इस फिल्म में उनका रोल शारीरिक और मानसिक रूप से बेदह चुनौतीपूर्ण था, जिसके साथ चित्रांशी ने पूरा न्याय किया है.

हालांकि निर्देशक ने फिल्म के सब्जेक्ट पर पांच साल कड़ी मेहनत की है. उन्होंने इस रोल के लिए चित्रांशी से बात की और उन्हें इसके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार किया. चित्रांशी के लिए उस रोल में ढल पाना बेहद मुश्किल था. इस भूमिका को निभाने के बाद चित्रांशी ने कहा कि इस रोल को करने के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मेरा परिवार मुझसे बहुत प्यार करता है. हकीकत में रिमांड होम में रहने वाली लड़कियों के लिए लड़ने वाला कोई नहीं है. मैंने इस फिल्म में अभिनय करके यह महसूस किया है. चूंकि यह फिल्म सत्य घटना पर आधारित है और फिल्म में उन विषयों को उठाया गया है, जिन मुद्दों पर समाज में खुले तौर पर बात नहीं होती है और अकसर उन मामलों को छिपाने या उनपर परदा डालने की कोशिश की जाती है.

चित्रांशी का मानना है कि वह एक कलाकार हैं, हीरोइन नहीं. वह किस्मत में यकीन करती हैं, लेकिन किस्मत पर पूरी तरह निर्भर नहीं हैं. वह मानती हैं कि अब तक उनकी किस्मत ने उनका बहुत साथ दिया है. वह कहती हैं कि छोटे कद की होने के बाद भी उन्हें फ़िल्मों में काम करने का मौका मिला. उनका मानना है कि सफलता के लिए आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है. इसके साथ ही सही समय का इंतजार करना चाहिए. बॉलीवुड में यदि कोई आठ साल हो और केवल पांच फिल्मों में काम करे तो इसे आप क्या कहेंगे. हालांकि वह इन सालों में सफलता के शिखर पर तो नहीं पहुंच पाईं, लेकिन उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई. वह एक गुड़िया की तरह नहीं दिखना चाहतीं, बल्कि अच्छा अभिनय करना चाहती हैं. ब्लैक होम के उनके किरदार की समीक्षक और दर्शक दोनों तारीफ कर रहे हैं. एक कलाकार के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है. उनकी इस फिल्म का उद्देश्य रिमांड होम्स के उस काले सच को दिखाना है, जहां घना अंधेरा है और लोगों की नज़रें वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं. अपने परिवार से बिछड़ने वाली लड़कियों को रिमांड होम्स में बाल अपराधियों के साथ रखा जाता है और पुनर्वास के नाम पर उनसे न जाने क्या-क्या करवाया जाता है. समाज के स्याह पक्ष को दिखाना ही फिल्म का एकमात्र उद्देश्य है.

चित्रांशी का मानना है कि बॉलीवुड में सफलता नेटवर्किंग क्षमता पर निर्भर करती है. उन्होंने अब तक ऐसी भूमिकाएं करने से मना किया है, जो पारंपरिक रूप से और फिल्म जगत के परिप्रेक्ष्य में सही हैं. वह ऐसी भूमिकाएं नहीं करना चाहती हैं. वह बॉलीवुड में अपनी शर्तों पर काम करना चाहती हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

चित्रांशी ने चक दे इंडिया में हॉकी उठाई, फैशन में अपना जादू चलाया, लक में भाग्य आजमाया और अब ब्लैक होम में तीखी मिर्ची बनी हैं.

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

बिहार झारखंड

06 अप्रैल –12 अप्रैल 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

प्यार और एक लंबा इंतजार! पेज 20

वास्तु विहार®
एक विश्वस्तरीय टाउनशिप
AN ISO : 9001-2008 & 14001 COMPANY

9 लाख में 2 BHK FLAT

वह भी मात्र 18,000/- की 36 किश्तों में
*Rates may vary project & state wise.

अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी फिर भी भारत में सबसे किफायती
1 Builder • 9 States • 58 Cities • 104 Projects
• स्विमिंग पूल • शॉपिंग सेन्टर
• 24x7 बिजली, पानी एवं सुरक्षा
www.vastuvihar.org
Customer Care : 080 10 222222

दर्जा और पैकेज पर अड़े नीतीश

अगर राज्य के हित की बात आएगी तो नीतीश किसी से भी जोर-आजमाइश के लिए तैयार हैं और कोई भी कुर्बानी देने से नहीं हिचकेंगे. उनके विरोधी उन्हें इस बात के लिए निशाने पर लेते रहे हैं कि उनके लिए अपना हित ही सर्वोपरि हैं और वह किसी भी हाल में नरेंद्र मोदी से नहीं मिलेंगे, लेकिन अब ऐसे विरोधियों के मुंह बंद हैं. उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि नरेंद्र मोदी से मुलाकात को वे किस नजरिये से देखें. खैर अपनी दिल्ली यात्रा में नीतीश कुमार ने जिस तरह से मुलाकात का दौर चलाया, उससे यह साबित हो गया कि तमाम संकटों के बीच आज भी राष्टीय राजनीति में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है.

सरोज सिंह

नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की मुलाकात कब होगी और किस माहौल में होगी, यह एक ऐसा सवाल था जिसका जबाव हर कोई जानने के लिए लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था. दरअसल भाजपा से संबंध टूटने के बाद यह सवाल पैदा हुआ और 26 मार्च को इसका जबाव सभी के सामने आ गया. नरेंद्र मोदी से मुलाकात से पहले नीतीश कुमार दर्जनों बार कह चुके थे कि बिहार के विकास की बात पर वह किसी से भी मिलने से परहेज नहीं करेंगे. 26 मार्च को नीतीश ने अपने कहे को सच किया और नरेंद्र मोदी से अपनी मुलाकात में यह टो टूक कह दिया कि बिहार की हक़मारी हो रही है, इसलिए केवल विशेष पैकेज से काम नहीं चलेगा बल्कि विशेष राज्य का दर्जा भी देना होगा. नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार ने साफ किया कि 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के लागू होने से प्रदेश के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं की हिस्सेदारी में कमी आई है. इससे बिहार का नुकसान हुआ है और इसकी हर हाल में भरपाई होनी चाहिए. नीतीश कुमार ने साफ किया कि सन 2000 में बिहार के बंटवारे के बाद पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के तहत राज्य को मिलने वाली विशेष सहायता राशि पर प्रश्न चिन्ह लग गया है. इस पर जल्द से जल्द संदेह दूर होना चाहिए. विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य को महज दस फीसदी रकम देनी होगी, इससे राज्य का बेहतर विकास होगा.

दरअसल नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की मुलाकात जिस पृष्ठभूमि में हुई, उसे लेकर राजनीतिक गलियारे में अटकलों का बाज़ार गर्म हो गया है. चंद दिनों पहले ही संघ की एक बैठक में यह कहा गया था कि बिहार भाजपा के लिए चुनावी मैदान इतना आसान नहीं है, इसलिए बेहतर होगा वह जदयू के साथ एक बार फिर अपने रिश्तों को मजबूत करे. संघ के इस इशारे के बाद यह बात तेजी से फैली की लगता है एक बार फिर बिहार में भाजपा और जदयू का गठबंधन परवान चढ़ सकता है. इस बीच लालू प्रसाद के गरम तेवरों ने इन अटकलों को और मजबूत कर दिया कि जदयू और भाजपा का मिलन फिर संभव है. नरेंद्र मोदी जिस गर्मजोशी से नीतीश कुमार से मिले उससे भी यह आभास हुआ कि राजनीति में कुछ भी संभव है. लेकिन नीतीश कुमार ने बड़ी ही चतुराई से इस मामले में किसी को कोई राय बनाने का मौका नहीं दिया. नरेंद्र मोदी से मुलाकात के ठीक बाद वह मुलायम सिंह से मिलने चले गए. वह मुलाकात भी जबरदस्त रही और बाहर यह बताया गया कि महागठबंधन को लेकर जल्द ही कोई शुभ समाचार बाहर आएगा. नीतीश कुमार यहीं नहीं ठहरे और अगले दिन उन्होंने लालू प्रसाद और अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की. नीतीश कुमार की इन ताबड़तोड़ मुलाकातों का फल यह निकला कि महागठबंधन की बंद पड़ी गाड़ी एक बार फिर निकल पड़ी. अपने दिल्ली प्रवास में नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि वह अब भी सबसे आगे दौड़ रहे हैं और भाजपा विरोध की राजनीति में वह सबसे अहम किरदार हैं. दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी से मुलकात में बिहार के हित का मुद्दा, खासकर विषेश पैकेज और दर्जा पर ठोस मांग कर, उठाकर उन्होंने यह संदेश दिया कि वह अहंकारी नहीं हैं बल्कि सही बात उठाने से पीछे नहीं हटने वाले लोगों में हैं.

अगर राज्य के हित की बात आएगी तो वह किसी से भी जोर–आजमाइश के लिए तैयार हैं और कोई भी कुर्बानी देने से नहीं हिचकेंगे. नीतीश कुमार के विरोधी उन्हें इस बात के लिए निशाने पर लेते रहे हैं कि उनके लिए अपना हित ही सर्वोपरि हैं और वह किसी भी हाल में नरेंद्र मोदी से नहीं मिलेंगे, लेकिन अब ऐसे विरोधियों के मुंह बंद हैं. उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की इस मुलाकात को वे किस नजरिये से देखें. खैर अपनी दिल्ली यात्रा में नीतीश कुमार ने जिस तरह से मुलाकात का दौर चलाया, उससे यह साबित हो गया कि तमाम संकटों के बीच आज भी राष्टीय राजनीति में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है. ■

feedback@chauthiduniya.com

नरेंद्र मोदी से मुलाकात के ठीक बाद नीतीश मुलायम सिंह से मिलने चले गए. वह मुलाकात भी जबरदस्त रही और बाहर यह बताया गया कि महागठबंधन को लेकर जल्द ही कोई शुभ समाचार बाहर आएगा. नीतीश कुमार यहीं नहीं ठहरे और अगले दिन उन्होंने लालू प्रसाद और अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की.

नीतीश को आगे कर चुनाव लड़ने की तैयारी

लालू प्रसाद के तेवर इन दिनों चाहे जैसे भी हों पर जमीनी सच्चाई तो यही है कि नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाने के अलावा उनके पास कोई रास्ता है ही नहीं. राजद का एक बड़ा तबका यह मानता है कि बिहार में नीतीश कुमार की छवि एक विकास पुरुष की है. सुशासन उनके एजेंडे में पहली प्राथमिकता पर है जिसे बिहार की जनता बेहद पसंद करती है. बिहार में लड़ाई उन्हें नरेंद्र मोदी से लड़नी है. नरेंद्र मोदी की यूएसपी भी सुशासन और विकास ही है. ऐसे में जनता को यह तय करना है कि सुशासन और विकास के मुद्दे पर कौन किससे बेहतर है.

नीतीश कुमार ही ऐसा चेहरा हैं जिसे लेकर नरेंद्र मोदी से लड़ाई लड़ी जा सकती है. लालू प्रसाद चूंकि खुद चुनाव नहीं लड़ सकते तो ऐसे में नीतीश के चेहरे के अलावा और कोई चेहरा नरेंद्र मोदी के सामने टिकेगा, यह समझना कोई मुश्किल काम नहीं. पार्टी लाइन वाले लोगों से हटें तो सूबे की आम जनता के बीच अभी भी नीतीश कुमार सबसे लोकप्रिय हैं. चौथी दुनिया के हालिया सर्वे में भी यह बात सामने आई है कि नीतीश कुमार सूबे के तमाम नेताओं से काफी आगे हैं. यह इसी सर्वे का प्रभाव है कि लालू प्रसाद के तेवर नरम पड़े हैं और राजद की तरफ से अनावश्यक बयानबाजी कम हुई है. जानकार सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार के नाम पर लालू प्रसाद को भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उनकी अपनी कुछ शर्ते हैं जिसे वह आमने सामने बैठकर तय कर लेना चाहते हैं. बताया जाता है कि दिल्ली में लालू प्रसाद के साथ मुलाकात में कई मसलों पर खुलकर बात हुई. नीतीश कुमार के नाम पर तो कांग्रेस को कोई दिक्कत है ही नहीं. कांग्रेस तो बस एक सम्मानजनक समझौता चाहती है. बताया जाता है कि कांग्रेस के दिल्ली में बैठे कई नेता भी लालू प्रसाद को समझा रहे हैं कि नीतीश को आगे करके ही बिहार में चुनाव लड़ा जाए.

कांग्रेस के रणनीतिकारों का आंकलन है कि जीतनराम मांझी के अलग हो जाने हो सकता है भाजपा को फायदा मिले, इसलिए होशियारी इसी में हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही बिहार में एक साथ होकर मजबूती से चुनाव लड़ा जाए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपने सहयोगी दलों के साथ भाजपा बिहार का किला फतेह भी कर सकती है. कांग्रेस के इस दबाव का असर भी दिख रहा है और चीजें अब सही रास्ते पर आने लगी हैं. नीतीश कुमार ने भी साफ कर दिया है कि सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ने के लिए वह तैयार हैं और यह तय है कि यहां इन सांप्रदायिक ताकतों का मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा.■

एक नज़र

रिहैब-मीट-2015 का आयोजन

फिर मिलेंगे अगले साल एक नये विषय के साथ का संकल्प लेकर, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित, पुनर्वास-विशेषज्ञों का तीन दिवसीय महा-सम्मेलन 'रिहैब-मीट-2015' विगत 15 मार्च को संपन्न हो गया. इस वर्ष का 'रिहैब-मीट प्रोफेशनल्स एक्सीलेंस अवार्ड-2015 प्रसिद्ध अस्थि-रोग विशेषज्ञ डा कमकल होदा, नाक-कान-गला रोग विशेषज्ञ डॉ. रविशंकर, नेत्र-रोग विशेषज्ञ डॉ. अंजनी कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. रीति कुमारी, थेरेपिस्ट डॉ. उदय नारायण सिंह तथा ऑप्टोमेट्रिस्ट शहंशाह इकबाल को दिया गया. बेउर,पटना स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च के सभागार में, 13 मार्च, 2015 से आयोजित, इस छठवें पुनर्वास सम्मेलन के मुख्य विषय 'वृद्धावस्था की समस्याएं और निदान' पर अगले तीन दिनों में आयोजित हुआ. रिहैब-मीट-2015 के सफलता पूर्वक आयोजन के लिए, आयोजन समिति के अध्यक्ष आकाश सुलभ, आयोजन सचिव डा अनुज कुमार गुप्ता, सह-सचिव प्रो. विधुपिया, प्रो. अनिल कुमार साह, डा तपसी डे, डॉ. संजीत कुमार, डॉ. पी. कुमार, प्रो. नीतू यादव, प्रो. रणजीत कुमार, प्रो. विवेक कुमार, डॉ. असगर अली खान, सुखेदार मेजर एस के झा, डॉ. राजेश झा, मो. समद अली, डॉ. मनोज कुमार तथा डॉ. प्रभात कुमार समेत दर्जनों स्वयंसेवकों ने महीनों कड़ी मेहनत की.

– निक्की सिंह

श्रीनिवास मिश्रा सुरसंड से करेंगे दावेदारी

2015 में होने वाले विधानसभा की तैयारी का आगाज राष्ट्रीय लोकसमता पार्टी के संयुक्त सचिव श्रीनिवास मिश्रा ने कर दिया है, वे सीतामढ़ी जिले के सुरसंड विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं. मिश्र ने इस विधानसभा से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है. 2000 में समता पार्टी से राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले श्रीनिवास मिश्रा ने जार्ज फर्नांडिस की अगुआई में 13 वर्षों तक राजनीति का ज्ञान प्राप्त किया, इसी बीच 2005 में टिकट के लिए प्रयास किया, परंतु टिकट नहीं मिल पाया. समता व जदयू के विलय होने के बाद श्रीनिवास को प्रदेश जदयू का सचिव बनाया गया. इसके बाद 30 जून 2013 को जदयू को अलविदा करते हुए 27 जुलाई 2013 को सीतामढ़ी के राजेन्द्र भवन में राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा व प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार की उपस्थिति में रालोसपा का दामन थामा. मालूम हो कि सामाजिक कार्यकर्ता श्रीनिवास पूर्णरूपेण समाज की बेहतरी और उसके विकास के लिए समर्पित हैं. उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में संयुक्त छात्र युवा संघर्ष मोर्चा, भारत वन निर्माण संघर्ष समिति, किसान बचाओ मंच के बैनर तले संघर्ष किया है. इतना ही नहीं बीपीएल एपीएल से वंचित लोगों के लिए धरना -प्रदर्शन किया. अभी तक श्रीमिश्र ने सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के पंचायत में 485 विकलांगों को उपकरण, 453 लोगों को वृद्धा पेंशन के अलावा अन्य समाज उपयोगी कार्य करने का काम किया है. 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान लोसपा के प्रदेश अध्यक्ष अरूण कुमार ने कहा था कि जिले में दो भूमिहारों को टिकट दिया जाएगा. श्री मिश्र ब्राह्मण जाति से आते हैं. हांलाकि इलाके में उनकी सक्रियता के हिसाब से यह माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें टिकट दे सकती है. लेकिन यह बात अभी भविष्य की गर्त में छिपा हुआ है कि पार्टी आलाकमान चुनावों के मद्देनजर क्या निर्णय लेता है? ■

– जय शंकर पाण्डेय

बिना शराब के भी ...
हो सकता है लिवर खराब

ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

Dr. V.C. Thakur
कन्सलटेन्ट फिजिशियन (पेट, लिवर, किडनी छाती एवं हृदय रोग विशेषज्ञ)

आज-कल लीवर के खराबी वाले मामलों का भी संख्या काफी बढ़ चुकी है डॉ. वी.सी. ठाकुर से हुई बातचीत के दौरान हुई चर्चा के कुछ अंश प्रस्तुत है। उन्होंने कहा कि जीवनशैली में बदलाव के कारण लिवर संक्रमण व इससे जुड़े रोग तेजी से सामने आ रहे हैं। शरीर में लिवर की भूमिका एक प्रयोगशाला जैसी है जहां पित्त बनता है और रस धातु से रक्त धातु का निर्माण होता है। लिवर को हम अंग और ग्रंथी दोनो ही कह सकते हैं। यह शरीर की पांच सौ से अधिक महत्वपूर्ण गतिविधियों में भाग लेती है, कार्बोहाइड्रोट, प्रोटीन और वसा के पाचन में भी लिवर की बड़ी भूमिका है। यह शरीर का एकलौता अंग है, जो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को आसानी से बदल सकता है। आगे उन्होंने बताया कि शराब नहीं पीने वालो को भी हो सकता है फैटी लिवर क्योंकि फैट की मात्रा ज्यादा होने पर फ्रोइब्रोसिस में बदल जाता है, फैट की जगह फाइवर की मात्रा अधिक हो जाती है, लिवर में सिकुड़न आ जाती है और पहले की तुलना में अधिक कठोर भी हो जाता है। समय पर उपचार नहीं हुआ तो यह लिवर कैन्सर में बदल जाता है। लिवर फैटी होने पर रक्तचाप की भी बीमारी हो जाती है आदमी का संतुलन बिगड़ जाता है। लिवर के प्रमुख रोगों में: हेपटाईटिस – वायरस से होने वाली हेपटायटिस लिवर की बीमारियों का दूसरा बड़ा कारण माना जाता है। ■

URSLIV Tab. Ursodeoxycholic Acid 300 mg
Carbo - XT Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
AREX Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
Siliplex Cap Syp. Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus
ARIZOL -D Cap Omerprazole 20 mg & Domperidone 10 mg

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
NOKSIRA A Division of AriskonPharma
- चित्रा भारती

बक्सर

उपद्रवियों ने थाने को फूंक चौकीदार को दफन कर दिया

जयमंगल पाण्डेय

पुलिस की नाजायज वसूली और डंडे का भय नहीं होता तो ट्रक चालक बक्सर में पांच लोगों को नहीं रौंदता और न शायद उन्मादी भीड़ थाने को फूंक कर चौकीदार को जिन दफन करती. तीन घण्टे तक उपद्रवी हिंसा का तांडव करते रहे और पुलिस जान बचा कर दुबकी रही. हजारों लोगों की उन्मादी भीड़ की विध्वंसक कारवाई से प्रशासनिक विफलता भी पुरी तरह से उजागर हो गयी. बक्सर में 11 मार्च की शाम भयानक विनाश की त्रासदी पुलिसिया धांधली तथा प्रशासनिक चूक का परिणाम है. यह सब वाकया बक्सर में उसी गोलम्बर के पास हुआ, जहां से पुलिस अधीक्षक के आवास की दूरी लगभग तीन सौ मीटर है.

वहीं से प्रतिदिन बालू लदे हजारों ट्रक यूपी में जाते हैं, जिससे पुलिस वालों की मोटी कमाई होती है. बालू माफियाओं का गिरोह भी सक्रिय है और दोनों तालमेल से अपने-अपने धंधे को अंजाम देते हैं. आदतन पुलिस वालों की जबरन वसूली से एक ट्रक चालक इतना मदहोश हो गया कि तेजी से भागते छोटे-बड़े वाहनों को रौंदते हुए निकल गया और बैरियर पर ट्रक को खड़ा कर भाग निकला. इस दरम्यान पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गयी और आधा दर्जन लोग घायल हो गये. इस घटना से लोगों का आक्रोश भड़क उठा और तोड़फोड़ तथा आगजनी शुरू हो गयी. फेसबुक और व्हाट्सएप्प जैसे सोशल माध्यमों द्वारा 15 से 30 लोगों के मारे जाने की अफवाह ने आग में घी डालने का काम किया फिर तो भीड़तंत्र का कारवां बढ़ता गया और उन्मादी हुई भीड़ बेलगाम हो गयी. घटनास्थल के बगल में स्थित औद्योगिक थाने की पुलिस त्वरित कारवाई करने के बदले सुस्त रही. तोड़फोड़ करते भीड़ निजी वाहनों में आग लगाने लगी. पुलिस जब हरकत में आयी, तब तक हजारों की भीड़ काफी उग्र हो गयी थी. पुलिस पर भी हमला बोल दिया और पुलिस के ब्रज वाहन तथा अग्निशमन की गाड़ी में भी आग लगा दी.

चेकपोस्ट में आग लगा कर सरकार टैक्स के एक लाख 10 हजार रूपये लूट भी लिए गये. मौके पर पहुंचे बक्सर के अनुमण्डलाधिकारी पर भी भीड़ टूट पड़ी. वे जान बचाने के लिए एक निजी अस्पताल में घुस गये. तांडव मचाते उपद्रवी औद्योगिक थाना पर पहुंचे. उससे पहले पुलिस वाले वहां से भाग कर निजी घरों में दुबक गये. थाने पर अकेले मौजूद चौकीदार मदन यादव को पकड़ कर उपद्रवियों ने पहले धुनाई की और फिर एक कमरे में उसे बंद कर आग लगा दी गयी. फिर पुलिस की दो जीप तथा थाने में जप्त वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया. आग की लपटो में तड़पता हुए चौकीदार जिन्दा दफन हो गया. औद्योगिक थाना तथा चेक पोस्ट में जल रहे कारतूसों के विस्फोट से ऐसा दहशत हुआ, जिससे घर में दुबके लोग अनहोनी की आशंका से कांप रहे थे. सूत्र यहां तक बताते हैं कि पुलिस अधीक्षक बार-बार थानाध्यक्ष को फोन कर रहे थे. उपद्रवी तीन घंटे तक शहर में विध्वंस तथा विनाश का तांडव मचाते रहे और मौत तथा घायलों को लेकर अलग ही कोहराम हो रहा था. लेकिन इस दरम्यान पुलिस तथा प्रशासन के अधिकारियों को घटनास्थल पर आने की हिम्मत नहीं हुई. यानि सुशासन सरकार में पुरी तरह जंगलराज का नंगा नृत्य होता रहा. उपद्रवी जब थक कर वापस लौट गये तो प्रशासन के अधिकारियों ने घटनास्थल पर जाकर विधि-व्यवस्था की कमान संभाली. तब तक काफी देर हो चुकी थी और आग से करोड़ो रूपये की संपत्ति राख हो गई थी. औद्योगिक थाने में लगी आग से पुलिस के रिकॉर्ड तथा मालखाना भी जल गये. इस थाना क्षेत्र में पकड़े गये कई चर्चित गांजा तस्करों तथा कुख्यातों से संबंधित पुलिस रिकॉर्ड के जलने से कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं.

इस घटना से विधि-व्यवस्थाा तथा जानमाल की सुरक्षा को लेकर कई अहम सवाल उठ खड़े हुए हैं. जिलाधिकारी रमण कुमा ने प्रशासनिक चूक स्वीकार करते हुए कहा कि मेरी लाख कोशिश के बाद विधि व्यवस्था के जिम्मेदार अधिकारी अपने को तैयार नहीं रखते. घटना का जायजा लेने के बाद आई.जी.ए.के. आम्बेडकर तथा डी.आई.जी.मो.ए. रहमान ने भी प्रेस कांफ्रेंस में प्रशासनिक लापरवाही की बात स्वीकार की. इस घटना में दर्ज हुई चार प्राथमिकी में 45 नामजद तथा 1500 अज्ञात अभियुक्तों की पहचान और बदनाम पुलिस की कार्रवाई पर संदेह किया जाने लगा है. बक्सर के सांसद अश्विनी कुमार चौबे ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि पुलिस दोषी लोगों पर कारवाई करे. निर्दोष लोगों को फंसाने पर पार्टी चुप नहीं रहेगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

अपनी शक्ति का एहसास दिलाने में जुटी है भाजपा

इंतेज़ारुल हक़

पूर्वी चंपारण जिले का राजनीतिक तापमान इन दिनों काफी गरम है.विधान सभा चुनाव का समय जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है वैसे-वैसे राजनीतिक दल समारोहों व अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगे हैं. दिल्ली के चुनाव में करारी हार का सामना कर चुकी भाजपा यहां पूरी तरह से सक्रिय हो गयी है और जोड़-तोड़ की गणित तैयार करने के साथ-साथ केन्द्र सरकार की उपलब्धियों को मुद्दा बनाकर आम जनता के बीच पहुंचने का प्रयास करने लगी है. कहीं सदस्यता अभियान चलाये जा रहे हैं तो कहीं भाजपा मिलन समारोह के बहाने जनता से जुड़ने की कोशिश हो रही है. बीते दिनों मोतिहारी के डाक बंगला स्कूल परिसर में आयोजित मिलन समारोह व हरसिद्धि के पूर्व विधायक व लोजपा के कद्दावर नेता महेश्वर सिंह द्वारा अपने समर्थकों के साथ भारत सरकार के केन्द्रीय कृषि मंत्री व स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह व भाजपा विधायकों की मौजूदगी में भाजपा में शामिल होना इसका ज्वलन्त नमूना है. मिलन समोरोह में जिस तरह से केन्द्र सरकार की उपलब्धियों को केन्द्रीय मंत्री राधामोहन सिंह द्वारा रखा गया और पूर्व की सरकार के साथ-साथ बिहार की नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की गयी उससे यह साफ झलक रहा था कि भाजपा आगामी चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और वह नीतीश-लालू को पछाड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर जनता को अपने पक्ष में तैयार कर रही है. मंत्री ने पूर्वी चंपारण की छह महत्वपूर्ण सड़कों को राजमार्ग का दर्जा देने, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 14 वर्ष तक की लड़कियों के नाम से एक-एक हजार रुपये जमा कराने ,गरीबों को अटल पेंशन देने की घोषणाएं की थी.

वहीं मिलन समारोह के मौके पर महेश्वर सिंह ने भाजपा को अपना पुराना घर बताते हुए कहा कि उन्होने 1973 में जनसंघ से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और बाद में राधामोहन सिंह के प्रभाव में आकर भाजपा में गये. उन्होंने भाजपा की प्रशंसा की और कहा कि भाजपा में संस्कार हैं और यहां केवल विकास की बात होती है. उन्होंने केन्द्रीय मंत्री राधामोहन सिंह के कार्य कलापों की सराहना की और कहा कि कृषि विश्वविद्यालय का मोतिहारी में आना विकास का पक्षधर है. मिलन समारोह की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सुनिल मणि तिवारी ने किया जबकि मौके पर पूर्व विधान पार्षद गंगा प्रसाद, विधायक सचिन्द्र प्रसाद सिंह, प्रमोद कुमार, कृष्णनन्दन पासवान, पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, नगर के उप सभापति मोहिबुल हक खां, मंकेश्वर सिंह, श्यामबाबू यादव, सुरेश सहनी, डॉ. लालबाबू प्रसाद, किरण सिंह, पंकज सिंह, यशवन्त सिंह, रामबाबू सिंह, अरुण यादव आदि ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये थे.दूसरी तरफ बिहार की सत्ताधारी दल जदयू व राजद भी खामोश नहीं बैठे हैं और नीतीश के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीधे जनता तक पहुंचने का अभियान चला रहे हैं.नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद जदयू के नेता व कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और संगठन को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं.जदयू के जिलाध्यक्ष प्रमोद सिन्हा व युवा जदयू के जिलाध्यक्ष विपिन पटेल बताते हैं कि पूरे जिले में संगठन को मजबूत बनाया जा रहा है और अधिक से अधिक लोग नीतीश कुमार से प्रभावित हो जदयू से जुड़ रहे हैं.वहीं दूसरी तरफ राजद सुप्रीमो लालू यादव, भारत सरकार के परिवहन मंत्री नीतीन गडकरी,भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पाण्डेय समेत सभी पार्टियों के दिग्गज विभिन्न कार्यक्रमों के बहाने मे पहुंच कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने व आगामी चुनाव की बाबत हर तरह से तैयार रहने का आह्वान कर रहे हैं. कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें भी हो रही है और उन्हें कई तरह का टास्क भी दिया जा रहा है.कूल मिलाकर चंपारण का राजनीतिक तापतान इन दिनों काफी गरम है और सभी राजनीतिक पार्टिया अपनी मुहिम में जुट गयी हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

अन्य ख़बरें

गणगौर विसर्जन महोत्सव

सीतामढ़ी शहर के कोट बाजार स्थित रामविलास मंदिर के समीप गणगौर विसर्जन महोत्सव का आयोजन किया गया. बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में संयोजक डॉ. विजय सर्राफ, राधेश्याम शर्मा, मुन्ना वर्मा, जनार्दन भरतिया, पंकज गोयनका, ओम प्रकाश अग्रवाल, राजेश कुमार सुंदरका, महिला समिति की अध्यक्ष सरिता सर्राफ, सोनम सरावगी, पुष्पा लोहिया, अलका अग्रवाल, वीणा सरावगी, सरिता अग्रवाल, गायत्री अग्रवाल व मालाभवसिंका समेत अन्य थे.

– विम्मी कुमारी

अनाप-शनाप बक रही भाजपा

सीतामढ़ी जिला जदयू उपाध्यक्ष सज्जन सुंदरका ने कहा कि आम जनता के संज्ञान से भाजपा गायब हो चुकी है. अबकी बार बिहार में जदयू नये अंदाज में जनभावना के बीच स्थान पायेगा. जिले की राजनीति पर चर्चा करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में सीतामढ़ी के किसी कोने में भाजपा मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगी. पीएम नरेंद्र मोदी की चुनावी घोषणाओं की सच्चाई को जनता देख चुकी है. जनता यह जान चुकी है कि जदयू ही वह पार्टी है जो लोगों की आशाओं पर खरा उतर सकती है.

– ब्रजेश कुमार

महायज्ञ आयोजित

बेला थाना क्षेत्र के भगवतीपुर गांव में श्री सीताराम नाम विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया. आयोजन कर्ता श्री श्री 108 श्री राम लखन जी महाराज ने बताया कि विशाल कलश शोभा यात्रा निकाला गया. जो मरहा नदी से जल भर कर भगवतीपुर, कन्हमां, रघुनाथपुर गांव घूमते हुए रामजानकी मंदिर तथा भूत भावन भोलेनाथ मंदिर के प्रांगण के मंडप तक पहुंची. वैदिक मंत्रोच्चारण द्वारा पूजा पाठ करा कर कलश स्थापन किया गया. विष्णु महायज्ञ स्थल पर मौत का कुआं, सरकश, झूला, जादूगर व रामलीला से लेकर कृष्णलीला तक की मनोहारी झांकी मूर्तियां बनाई गई थीं. ■

– रूपा कुमारी

सीतामढ़ी-शिवहर

चुनावी अखाड़े का कौन होगा सफल खिलाड़ी ?

बिहार विधान परिषद एवं बिहार विधानसभा चुनाव का समय ज्यों- ज्यों करीब आ रहा है, सीतामढ़ी व शिवहर जिले में चुनावी गतिविधियां जोर पकड़ने लगी है. तकरीबन सभी दल के राष्ट्रीय व प्रदेश स्तरीय नेताओं का दौरा भी शुरू हो चुका है. जाति व पार्टी के आधार पर सभी ने अपने राजनीतिक शक्ति परीक्षण का केंद्र फिलहाल राजधानी पटना के गांधी मैदान को बना लिया है. कार्यकर्ता सम्मेलन व आमसभा के बहाने सभी राजनीतिक दल द्वारा अपना शक्ति प्रदर्शन करने की मुहिम भी शुरू है. कल तक एक साथ रहने वाले नेता अब दो-दो हाथ करने को बेताब नजर आने लगे हैं. कोई गठबंधन तो कोई अपने ही बूते चुनावी दंगल में ताल ठोंकने को आतुर है. राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने फिलहाल अपने नेताओं के बुलावे पर नंगे पांव दौड़ लगाने का अभ्यास भी शुरू कर दिया है. परंतु जिले में चुनावी अखाड़े का सफल पहलवान कौन बनेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं. सीतामढ़ी व शिवहर जिले में कई नये व पुराने राजनीतिक चेहरे हैं, जिनकी बदौलत पार्टी को कहीं मजबूती मिलने तो कहीं मायूसी में डूबने की आशंका भी व्यक्त की जाने लगी है...

वाल्मीकि कुमार

लोकतंत्र के चुनावी महापर्व का इंतजार तकरीबन उन सभी को पूरे पांच साल तक रहता है, जिनके ज़ेहन में राजनीति का सुनहरा सपना हर पल हर दिन एक नये अंदाज के साथ सोता और जागता है. जो जीत जाते हैं, वे अगली बार के लिए कतार में लगने को तैयार होते हैं, तो हारने वाले भी हार कर भी हार मानने को तैयार नहीं होते. नतीजा होता है कि प्रत्येक चुनाव में क्षमता से अधिक संख्या में प्रत्याशियों का सभी क्षेत्रों में जमावड़ा होने लगता है. जबकि सभी यह जानते है कि चुनावी नतीजे महज दो प्रत्याशियों के बीच सिमट कर रह जाते हैं. बहुदलीय शासन प्रणाली को इसके लिए पूर्णत: जिम्मेदार माना जाता है. आज कोई भी जिस दल से निर्वाचित होता है, गारंटी नहीं कि अगली बार वह चेहरा उस दल के लिए ही समर्पित होगा. परंतु एक सामान्य कार्यकर्ता की कर्तव्यनिष्ठा उसे ताउम्र एक ही पार्टी का झंडा ढोने के लिए विवश कर देती है.

फिलहाल बिहार में विधान परिषद स्थानीय निकाय व विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है. सीतामढ़ी व शिवहर जिले में भी इसको लेकर सरगर्मी बढ़ने लगी है. चुनावी चर्चाओं के बीच एक सवाल जोर पकड़ने लगा है कि नये चेहरों के अलावा दोनों ही जिले में पुराने राजनीतिक चेहरों की चुनावी बिसात क्या हो सकती है? यह चर्चा का विषय माना जा सकता है. कारण कि दोनों ही जिले की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले पुराने चेहरों को भी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत रखने की विवशता है. अगर पुराने चेहरे राजनीति से खुद किनारा कर लेंगे तो उनकी राजनीति अतीत का अध्याय बन कर रह जायेगी. दूसरा कारण यह है कि नये चेहरों को भी मार्गदर्शक की दरकार होने की संभावना से इंकार नही किया जा सका है. ऐसे में सीतामढ़ी व शिवहर जिले में राजनीति की दिशा क्या होगी? फिलहाल कहना मुश्किल प्रतीत होता है. इसका कारण है कि राजद, जदयू, भाजपा, लोजपा, रालोसपा, बसपा व सपा समेत अन्य दल अपनी पीठ आप ही ठोंके जा रही है. अब एक नजर सीतामढ़ी जिले पर डालें तो भाजपा गठबंधन के रालोसपा सांसद राम कुमार शर्मा है. जबकि जदयू के पूर्व सांसद द्वय नवल किशोर राय व डॉ. अर्जुन राय, राजद के पूर्व सांसद सीताराम यादव व पूर्व मंत्री डॉ. रामचंद्र पूर्वे जिले में राजनीति का केंद्र हैं. इनके अलावा तिरहुत स्नातक क्षेत्र से विधान पार्षद देवेशचंद्र ठाकुर, पूर्व मंत्री नवल किशोर शाही, पूर्व विधायक जयनंदन प्रसाद यादव व नगीना देवी हैं. इनकी राजनीतिक बैठकें भी चलती रहती हैं. जहां तक भाजपा गठबंधन के तहत निर्वाचित रालोसपा सांसद राम कुमार शर्मा का सवाल है तो उन्होंने जिले की राजनीति में पहला कदम रखा है. सांसद बनने के बाद भी अब तक सीतामढ़ी जिले में रालोसपा अपनी मजबूत पकड़ बनाने में कामयाब नहीं हो पायी है. और तो और जिले में पार्टी का कार्यालय तक कार्यकर्ताओं को पता नहीं है. ऐसे हालात में आगामी चुनावों में पार्टी क्या कर सकती है, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है. वैसे पार्टी के कई नेता जिले में लगातार कसरत कर रहे हैं.

जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के पुन: सीएम बनने के बाद नये उत्साह का प्रवाह कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है. परंतु जिले की राजनीति में दल के दो पूर्व सांसद का अपनी डफली अपना राग चर्चा का केंद्र बना है. बताया जाता है कि जदयू के पूर्व सांसद डॉ अर्जुन राय चुनाव में पार्टी की लुटिया डुबोने के बाद जिले से चलते बने हैं. परंतु कभी कभार अपने चहेतों के बीच बैठकर स्थानीय अखबारों में जगह पाते रहते हैं. वहीं दूसरी ओर पार्टी के पूर्व सांसद नवल किशोर राय समय निकाल कर जिला पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहने का प्रयास करते हैं. मतलब यह कि एक दल के होने के बाद भी दोनों कभी साथ बैठकर पार्टीहित में ठोस रणनीति पर विचार से परहेज करते हैं. नतीजा है कि जिले में पार्टी कार्यकर्ता दो खेमे में विभाजित होने को विवश हो गये है.

अर्जुन राय, देवेशचंद्र ठाकुर, डॉ. रामचंद्र पूर्वे, एन.के. साहनी, जे.एन. यादव, लवली आनंद, नगीना देवी, रमा देवी, मो. अनवारुल हक, रघुनाथ झा, राम कुमार शर्मा, सीताराम यादव, नवल किशोर राय, सूर्यदेव राय

अब तिरहुत स्नातक क्षेत्र से विधान पार्षद देवेशचंद्र ठाकुर की राजनीतिक भूमिका पर चर्चा आवश्यक है. पिछले चुनाव में श्री ठाकुर जदयू से खफा होकर बतौर निर्दलीय चुनावी समर में उतरे थे. चुनाव में जीत के बाद अब उनकी मंशा भाजपा का दामन थामने की है. चर्चा यह भी चल रही है कि सीतामढ़ी जिले के किसी विधानसभा क्षेत्र में स्वयं अथवा किसी करीबी को चुनावी मैदान में भाजपा से बतौर प्रत्याशी उतारने वाले हैं. वैसे फिलहाल उनका भाजपा में पदार्पण जिले में चर्चा का केंद्र बना है. पूर्व मंत्री सह प्रदेश राजद अध्यक्ष डॉ रामचंद्र पूर्वे सोनबरसा विधानसभा सीट से पूर्व में निर्वाचित हो चुके हैं. अब सोनबरसा परिहार विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तित हो चुका है. चर्चा चल रही है कि इस बार पुन: उनकी मंशा बतौर प्रत्याशी क्षेत्र में वापसी की है. चुनावी चर्चा के बाद संभावित नये चेहरों के बीच राजनीतिक समीकरण पर विचार का दौर भी शुरू हो गया है. सुरसंड से राजद की टिकट पर चुनाव जीत चुके पूर्व विधायक जयनंदन प्रसाद यादव ने पिछले लोकसभा चुनाव के मौके पर राजद से नाता तोड़ कर जदयू प्रत्याशी के पक्ष में आने की घोषणा कर दी थी. तब से लेकर अब तक उनके दलगत राजनीतिक स्थायित्व को लेकर चर्चाओं दौर जारी है. वैसे अब सुरसंड सीट पुपरी विधानसभा क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो गया है. चल रही चर्चाओं पर यकीन करें तो कार्यकर्ता उन्हें पुराने घर वापसी को लेकर दवाब बना रहे हैं. इधर, रुन्नीसैदपुर सीट से जीत दर्ज करा चुके पूर्व मंत्री नवल किशोर शाही अब भी क्षेत्र की राजनीति में पैठ बना कर चुनावी वक्त के इंतजार में है. वहीं बथनाहा से लोजपा की विधायक रह चुकी पूर्व विधायक नगीना देवी भी रीगा सीट से चुनावी समर में आने का राह टटोल रही है. बथनाहा को परिवर्तित कर रीगा क्षेत्र बनाया गया है. बथनाहा क्षेत्र से ही पूर्व मंत्री सूर्यदेव राय भी राजद की टिकट पर चुनाव जीते थे.

कुल मिलाकर देखा जाये तो इनके अलावा और भी कई पुराने व नये राजनीतिक चेहरे ह, जो जिले की राजनीति में अपनी पहचान को लेकर प्रयासरत है. चल रही चर्चाओं पर भरोसा करे तो इक्त दलगत नेताओं की भावना का अनादर पार्टी नेतृत्व के लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है. संभव है कि सभी नेता स्वयं अथवा अपने चहेतों के लिए पार्टी नेतृत्व पर टिकट की दावेदारी को लेकर दवाब डालने का प्रयास करे. ऐसे में अगर सफलता नहीं मिलती है तब नेताओं की गुपचुप चुनावी रणनीति पार्टी के लिए घातक हो सकती है. खेमेबाजी की स्थिति में दलगत नुकसान के सामने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है. दूसरी ओर शिवहर जिला भी राजनीति में अव्वल रहा है. वर्तमान में भाजपा की रमा देवी सांसद है. जबकि पूर्व सांसद रघुनाथ झा, पूर्व सांसद मो अनवारूल हक व पूर्व सांसद आनंद मोहन की धर्मपत्नी सह पूर्व सांसद लवली आनंद के अलावा पूर्व विधायक अजित कुमार झा समेत अन्य जिले की राजनीति में शामिल है. 2015 के विधानसभा चुनाव में इन नेताओं की भूमिका अहम होने की पूर्ण संभावना है. परंतु देखना यह है कि इनमें किस नेता अथवा उनके चहेतों को चुनाव में मौका मिलता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

मधुबनी में मना मिथिला महोत्सव

चौथी दुनिया ब्यरो feedback@chauthiduniya.com

मिथिला महोत्सव इस बार दरभंगा के बदले मधुबनी वाट्सन हाई स्कूल के मैदान में मनाया गया. इससे पहले पूर्व में दो बार इस महोत्सव का आयोजन दरभंगा में हुआ था. महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने किया. अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने मिथिला की विरासत व संसकृति का बखान करते हुए कहा, कि मिथिला की संस्कृति मधुबनी पेंटिंग से मेल खाती है. इसके विकास के लिए मिथिला चित्रकला चालू कर दिया जाएगा. इस संस्थान के माध्यम से मिथिला की सभी विधा पर काम किया जाएगा ताकि मिथिला पेंटिग विश्वमानचित्र पर ख्याति प्राप्त कर सके. मुख्यमंत्री ने अपने भाषण के दौरान कहा कि यहां की भाषा और बोलचाल बड़ा ही मीठा व मधुर है. मुख्यमंत्री अपने संबोधन के बीच विधान परिषद के पूर्व सभापति स्व0 ताराकांत झा की चर्चा करते हुए कहा कि तारा बाबू ने मिथिला के विकास के लिए ही निरन्तर काम किया .

मुख्यमंत्री ने बलिराजगद की चर्चा करते हुए कहा, कि यह स्थल 122 एकड़ में अपने ऐतिहासिक विरासत को समेटे हुए है. और यह देश का सबसे बड़ा पुरातत्व स्थल है, इस जगह का उत्खनन होने से मिथिला के कई नए अध्याय जुड़ेंगे. बलिराजद के उत्खनन में आज तक किसी भी सरकार नें दिलचप्पी नहीं ली, इस पुरातात्विक स्थल का उत्खनन नहीं हो पाने के कारण मिथिला के हजारो वर्षो का इतिहास दफन हो चुका है, लेकिन जब राज्य सरकार ने इस जगह के उत्खनन का कार्य करना शुरू किया, तो केन्द्र ने भी बाद में सहयोग करने की बात कहीं जबकि पूर्व में केन्द्र सरकार इस कार्य को अनसूना कर दिया था. मुख्य अतिथि बिहार सरकार कैबिनेट मंत्री रामलखन राम रमण थे जबकि रमारोह की अध्यक्षता पर्यटन मंत्री जावेद इकबाल अंसारी ने किया. मिथिला महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम से पहले में मुख्यमंत्राी ने टाउन क्लब मैदान में विधान पार्षद विनोद कुमार सिंह द्वारा आयोजित त्रिस्तरीय पंचायती राज्य एवं नगर निकाय प्रतिनिधि समागम को भी संबोधित किया भले ही यह कार्यक्रम पंचायती राज व नगर निकाय प्रतिनिधि का था. लेकिन कार्यक्रम में दस प्रतिशत जनप्रतिनिधि भी उपस्थित नहीं हुए थे. ■

एक नज़र

मुख्यमंत्री को सौंपा मांग पत्र

मधुबनी वाटसन हाई स्कूल में आयोजित मिथिला महोत्सव के उद्घाटन समारोह में आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रो. शीतलाम्बर झा ने 21 सूत्रीय मांगों से संबंधित स्मार-पत्र सौंपा. स्मार-पत्र में श्री झा ने प्रखण्ड से लेकर जिला स्तर तक के भ्रष्ट अधिकारियों को बर्खास्त करने, बिस्फी प्रखंड का नाम परिवर्तित कर कवि कोकिल विद्यापति के नाम करने, विद्या पति की जन्स्थली को राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल घोषित करने, मैथिली शिक्षकों को नियुक्ति के साथ-साथ मिथिलांचल में मैथिली विषय को अनिवार्य घोषित करने, जिले को बाढ़ व सुखे से निजात दिलाने, जिला 20 सूत्रीय कमेटी निगरानी समिति में जिला एवं प्रखंड में कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व देने, मधुबनी शहर का पानी निकासी का प्रबंध करने, मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों का आधुनिककिरण करने,रैयाम लोहट व सकरी चीनी मिल को अविलम्ब चालू करने, मधेपुर प्रखण्ड के समीप गांधी आश्रम की जमीन को भू-माफिया से मुक्त कराने, रहिका स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा व्याप्त भ्रष्टाचार एवं 15 वर्षो से एक ही जगह पदस्थापित होने की जांच करने, रामपट्टी को प्रखण्ड बनाने, जिले के सभी अनुमंडल के व्यवहार उच्च न्यायालय स्थापना करने, बेनीपट्टी अनुमंडल के व्यवहार न्यायालय चालू करने एवं बंद पड़े नलकूपों को अविलंव चालू करने सहित अनेको मांग से संबंधित स्मार-पत्र को सौंपा.

– जय शंकर पांडेय

महायज्ञ का आयोजन

पूर्वी चम्पारण जिले के डुमरिया घाट थाना क्षेत्र के रामपुर खजुरिया चौक पर रुद्र चण्डी महायज्ञ का आयोजन किया गया.इस अवसर पर कलश यात्रा निकाली गयी जहां बड़ी संख्या में कुंवारी कन्याओं के साथ महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया. स्थानीय गण्डक नदी बाराघाट से जल भरकर गाजे-बाजे के साथ भक्त महायज्ञ स्थल पर पहुंचे. यज्ञ पूजा समिति के सदस्य सियाराम सिंह ने बताया कि इस यज्ञ में मथुरा वृन्दावन से रासलीला मण्डली तथा दूर-दूर से प्रवचन वाचक आये हुए थे. मौके पर पूजा समिति के सचिव संजय कुमार द्विवेदी, अध्यक्ष नवल किशोर सिंह, आयोजन कर्ता सुधाकर पाण्डेय तथा श्री कान्त सिंह, रामाशंकर सिंह, गौरीशंकर सिंह, जीतन पाण्डेय आदि उपस्थित थे.

डीएस को बनाया बंधक

बिहार नवयुवक सेना के सदस्यों ने सदर अस्पताल की कुव्यवस्था एवं व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ अस्पताल में घंटों बवाल काटा एवं उपाधीक्षक को उनके कक्ष में बंधक बनाया. इस दौरान सिविल सर्जन डॉ. मीरा वर्मा का भी घेराव करना चाहा किन्तु वे वहां से फरार हो गईं. पुलिस के आने के बाद मामला शांत कराया. प्राप्त खबर के अनुसार बिहार नवयुवक सेना के सदस्यों ने सदर अस्पताल की कुव्यवस्था एवं अस्पताल प्रशासन के भ्रष्टाचारी रवैये सहित अनेक मांगों को ले कुछ दिन पूर्व सीएस डॉ. वर्मा को अल्टीमेटम दिया था एवं कहा कि अगर व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो बीस मार्च को अस्पताल में तालाबंदी की जाएगी. किन्तु इसमें अस्पताल प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की सुधार नहीं की गयी थी. बाद में पुलिस के आने के बाद मामला शांत हुआ. बिहार नवयुवक सेना के अध्यक्ष अनिकेत पांडेय ने डीएस को ज्ञापन सौंपा एवं अपनी मांगों को दोहराया.

शिक्षक संघ ने निकाला जुलूस

टीईटी-एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ ने सरकार पर भेद-भाव करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया. शिक्षकों ने डाक बंगला स्कूल परिसर से जुलूस निकाला जो समाहरणालय तक गया. इसके बाद डीएम को अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा. उनकी मुख्य मांगे चरणबद्ध तरीके से वेतन मान देने, शिक्षा नीति में बदलाव करने आदि शामिल है. समाहरणालय के समक्ष आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सरकार एक तरफ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात करती है तो दूसरी तरफ शिक्षकों को न्यूनतम मजदूरी देकर उन्हें अपमानित करती है. जबतक शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान नहीं मिलता तबतक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करना बेमानी होगी. सभा को प्रदेश अध्यक्ष मार्कण्डेय पाठक, जिलाध्यक्ष प्रियरंजन सिंह, सुरेन्द्र यादव, राम विनय वर्मा, ब्रजेन्द्र कुमार, प्रकाश यादव, चेतन आनन्द, राकेश शर्मा, अवधेश पासवान, अशोक तिवारी, मुकेश कुमार, प्रभात कुमार, ज़की अहमद, दीपेन्द्र कुमार, अजीत कुमार, प्रदीप कुमार, देव कुमार यादव, हारुन रशीद, ब्रजकिशोर सिंह, जमाल हुसैन, अनिल कुमार, सत्यम कुमार व सदरे आलम समेत बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित थे.

बिहार दिवस पर कार्यक्रमों की धूम

बिहार दिवस के अवसर पर जिले भर में कार्यक्रमों की धूम मची रही और सभी संस्थानों सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ संगठनों द्वारा बिहार दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. जिला प्रशासन द्वारा मोतिहारी के गांधी मैदान में बिहार दिवस का आयोजन किया गया जहां अनेक रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां की गयी तथा बिहार के विकास के लिए चलायी जा रही योजनाओं पर चर्चा की गयी. डुमरियाघाट थानाक्षेत्र के रा.उ.म. विद्यालय सरेया व एनपीएस नोनेया पाण्डेय टोला में बिहार दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया. मौके पर प्रधान शिक्षक लालबाबू यादव व प्रधान शिक्षक सुनील प्रसाद के नेतृत्व में शिक्षकों व टोला सेवकों की मौजूदगी में सुबह में प्रभातफेरी निकाला गयी और विद्यालय परिसर में अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये. मौके पर शिक्षकों में चन्द्र भूषण कुमार, शिला कुमारी, आशा कुमारी, नमीता कुमारी, केशव कुमार कश्यप, अशोक कुमार श्रीवास्तव, अनिल कुमार, रामबाबू चौधरी, टोला सेवक में राजेन्द्र राम, दिनेश कुमार, पंकज कुमार बैठा मौजूद रहे.

– इंतेज़ारूल हक़

सम्मान समारोह आयोजित

गोगरी अनुमंडल के परबत्ता प्रखंड के उच्च विद्यालय कन्हैयाचक परिसर में पंचायत प्रतिनिधियों का विधान परिषद सदस्य सह विरोधी दल के मुख्य सचेतक रजनीश कुमार द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. सभी की अध्यक्षता माधवपुर पंचायत की मुखिया शांति देवी ने की. जबकि मंच संचालन मिथिलेश कुमार ने किया. सभा को संबोधित रजनीश कुमार ने किया. उन्होंने कहा कि सभी पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान ही मेरा सम्मान है. मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता सह भाजपा सदस्य बाबूलाल शौर्य ने कहा कि हर हाल में लोगों का अपने विकास के लिए खुद संकल्पित होना होगा. इस मौके पर विभिन्न पंचायतों से आये जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी-अपनी बातों को रखा. पंचायत प्रतिनिधियों के अतिरिक्त कई भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित थे. मौके पर मुखिया राम बालक सिंह, पुष्पमनुज, अंजु कुमारी, बबलू रजक, मो. इरफान आलम, धर्म शीला देवी, रामानुज प्रसाद रमण, मो. अफताब आलम, जितेन्द्र यादव, दुर्गेश चौधरी, अनन्त चौधरी, पियूष हजारी, पृथ्वी राज चौहान, सुनील कुमार चौरसिया सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे.

– गीता कुमार

प्यार और एक लंबा इंतजार!

एक लंबे इंतजार के बाद 2000 में दोनों फिर से दिल्ली में मिले. प्रवीण ने अनामिका से पूछा- क्या तुमने मुझसे जो शादी का वादा किया था, उस पर अभी भी कायम हो? इसका जवाब अनामिका ने हां में दिया. तब प्रवीण ने अनामिका को अपने संभ्रांत परिवार से जुड़े होने की बात बताई. इसके बाद दोनों के बीच सब सामान्य रहा. लेकिन प्रवीण के घर में किसी की मृत्यु हो जाने के कारण वो घर वापस आ गए. इसके बाद शुरू हुआ घर वाले और समाज का सामना. अपने घरवालों के दबाव में आकर प्रवीण ने अनामिका से शादी करने के लिए मना कर दिया. लेकिन इस बात को अनामिका ने बड़ी ही सहजता से लिया और प्रवीण से कहा कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, तुम जहां शादी करना चाहते हो कर लो, लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती.

आखिरकर शायद भगवान को भी इन दोनों की हालत पर दया आ गई और प्रवीण के छोटे भाई प्रशांत ने इन दोनों के रिश्ते को सुधारने के लिए एक फरिश्ते के जैसा काम किया. उन्होंने अपने घर में लोगों को अनामिका और प्रवीण के रिश्ते के बारे में बताया. इतना ही नहीं प्रशांत ने अपने घर वालों को मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. फिर अनामिका के ससुर ने दिल्ली जाकर उनसे मुलाकात की और उन्होंने इस शादी के लिए मंजूरी दे दी.

राधिका

प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेग़ाना होता है. कुछ इसी गाने के बोल की ही तरह है भाजपा युवा मोर्चा की उपाध्यक्ष अनामिका सिंह और उनके पति प्रवीण सिन्हा की प्रेम कहानी. इन दोनों ने जिंदगी के एक लंबे संघर्ष के बाद अपने प्यार को पाया है. वो कहते हैं कि दिल में अगर किसी के प्रति सच्चा प्यार हो तो उसके सामने कड़े से कड़ा संघर्ष भी बौना साबित हो जाता है. इन दोनों के मामले में ये कहावत बिल्कुल सटीक साबित हुई है. भले ही दो प्यार करने वालों को जुदा करने के लिए कोई कितना भी दम लगाए, लेकिन जीत सच्चे प्यार करने वालों की ही होती है.

अनामिका और प्रवीण की पहली मुलाकात 1997 में दिल्ली में हुई थी. ये दोनों दिल्ली में एक सेमीनार में हिस्सा लेने गए थे. इसी सेमीनार में प्रवीण ने अनामिका को पहली बार देखा था, लेकिन प्रवीण ने खुद अनामिका से आकर कुछ नहीं कहा. सेमीनार के बाद प्रवीण के एक दोस्त आदित्य पांडे अनामिका से आकर मिले और नोट्स देने का आग्रह किया. आदित्य की नोट्स देने वाली बात को अनामिका ने मान लिया. फिर सिलसिला आगे बढ़ा और इसी दौरान अनामिका और प्रवीण पहली बार रूबरू हुए. धीरे-धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे. अनामिका बताती हैं कि मैं और प्रवीण दोनों हीं संभ्रांत परिवार से ताल्लुक रखते हैं. लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे ये सच नहीं बताया था. बल्कि उन्होंने ये कहा था कि वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं. लेकिन इस बात का मुझ पर कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ा. अनामिका आगे कहती हैं कि इसके बाद शायद प्रवीण के दोस्तों ने मेरी परीक्षा लेने के लिए मुझसे एक सवाल पूछा और वो ये था कि- क्या आप प्रवीण से शादी करेंगी?'. इस सवाल के जवाब में मैंने हां कह दिया. इसके बाद आया एक दूसरे से जुदा होने का समय. सेमीनार के ख़त्म होने के बाद दोनों अपने-अपने घर चले गए. इसके बाद दोनों के बीच थोड़ी दूरी आ गई. दोनों की दो साल में बस दो से तीन बार हीं बात हुई. अनामिका आगे बताती हैं कि मेरा कॉलेज चलता रहा. मैं अपनी पढ़ाई करती रही. लेकिन इस दौरान मेरा ध्यान किसी और की तरफ नहीं गया. इस तरह समय बीतता चला गया.

एक लंबे इंतजार के बाद 2000 में दोनों फिर से दिल्ली में मिले. प्रवीण ने अनामिका से पूछा- क्या तुमने मुझसे जो शादी का वादा किया था, उस पर अभी भी कायम हो?' इसका जवाब अनामिका ने हां में दिया. तब प्रवीण ने अनामिका को अपने संभ्रांत परिवार से जुड़े होने की बात बताई. इसके बाद दोनों के बीच सब सामान्य रहा. लेकिन प्रवीण के घर में किसी की मृत्यु हो जाने के कारण वो घर वापस आ गए. इसके बाद शुरू हुआ घर वाले और समाज का सामना. अपने घरवालों के दबाव में आकर प्रवीण ने अनामिका से शादी करने के लिए मना कर दिया. लेकिन इस बात को अनामिका ने बड़ी ही सहजता से लिया और प्रवीण से कहा कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, तुम जहां शादी करना चाहते हो कर लो, लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती. अनामिका कहती हैं कि उनके इस बुरे समय में उनकी मां ने उनका पूरा साथ दिया. अनामिका की मां ने कहा कि प्यार किसी से और शादी किसी और से, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है. अगर अनामिका किसी और से शादी नहीं करना चाहतीं तो उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं होगी. यहां पर इन दोनों के बीच का एक खूबसूरत रिश्ता कुछ समय के लिए थम सा गया. अनामिका बताती हैं कि उस दौरान मैं बहुत बीमार रहने लगी. उस समय मैं दिल्ली में दूरदर्शन में नौकरी कर रही थी. फिर एक समय आया, जब प्रवीण ने अनामिका के सामने ये शर्त रखी कि तुम मीडिया का जॉब छोड़ दो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूं. फिर क्या था अनामिका ने बिना कुछ सोचे अपनी नौकरी छोड़ दी. लेकिन एक बार फिर घरवालों के दबाव में आकर प्रवीण ने शादी से इंकार कर दिया.

लेकिन आखिरकर शायद भगवान को भी इन दोनों की हालत पर दया आ गई और प्रवीण के छोटे भाई प्रशांत ने इन दोनों के रिश्ते को सुधारने के लिए एक फरिश्ते के जैसा काम किया. उन्होंने अपने घर में लोगों को अनामिका और प्रवीण के रिश्ते के बारे में बताया. इतना ही नहीं प्रशांत ने अपने घर वालों को मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. फिर अनामिका के ससुर ने दिल्ली जाकर उनसे मुलाकात की और उन्होंने इस शादी के लिए मंजूरी दे दी. फिर क्या था इन दोनों के सालों के धैर्य ने उन्हें एक-दूसरे से मिला दिया. आखिरकर 1 मई 2007 को इन दोनों की शादी बड़े ही धूम-धाम से हुई. इस तरह दोनों की प्रेम कहानी अपने अंजाम तक पहुंच गई. आज दोनों ही अपनी-अपनी फील्ड में सफल हैं, साथ हीं एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं. उनका एक बेटा है, अधिराज, जो केजी में पढ़ता है.■

feedback@chauthiduniya.com

Mob. : 9386745004, 9204791696
www.iiher.org,
Email : anilsulabh6@gmail.com

INDIAN INSTITUTE OF HEALTH EDUCATION & RESEARCH
Health Institute Rd, Beur (Near Central Jail), Patna -2.
(Recongnised by Govt. of Bihar, RCI, Govt. of India, IAP & ISPO)
AFFILIATED TO MAGADH UNIVERSITY, BODHGAYA

POST GRADUATE COURSES :

Name of Courses		Eligibility	Duration
MPT	Master of Physiotherapy	BPT	2yrs.
MOT	Master of Occupational Therapy	BOT	2yrs.
DEGREE COURSES			
BPT	Bachelor of Physiotherapy	I.Sc (Bio)	4yrs.+6 Months of Internship
BOT	Bachelor of Occupational Therapy	I.Sc (Bio)	4yrs.+6 Months of Internship
BPO	Bachelor of Prosthetic & Orthotic	I.Sc	4yrs.+6 Months of Internship
BASLP	Bachelor of Audiology & Speech Language Pathology	I.Sc	3yrs.+1 year of Internship
BMLT	Bachelor of Medical Laboratory Technology	I.Sc	3yr.+6 Months of Internship
BMRIT	Bachelor of Radio Imaging Technology	I.Sc	3yrs.+6 Months of Internship
B.Ophth.	Bachelor of Ophthalmology	I.Sc	4yr.+6 Months of Internship
B.Ed.	(Special Education)	Graduate	1yr.
1 YEAR ABRIDGED DEGREE FOR DPT / DOT			
DIPLOMA COURSES :			
DPT	Diploma In Physiotherapy	I.Sc (Bio)	3yrs.+6 Month of Internship
D-X-Ray	Diploma In X-Ray Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DMLT	Diploma In Medical Laboratory Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DECG	Diploma In E.C.G.	I.Sc (Bio)	2yr.
DOTA	Diploma In O.T. Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DHM	Diploma In Hospital Management	Graduate	1yr.
CMD	Certificate in Medical Derssing	Matirc with Science & English	1yr.

ADMISSION OPEN

Form & Prospectus -
Can be obtained from the office against a payment of Rs. 500/-. only by cash. Send a DD of Rs. 550/- only in the favour of Indian Institute of Health Education & Research, Patna, for postal delivery.

डा. अनिल सुलभ
निदेशक प्रमुख

"टी.आई." ब्राण्ड शटरपत्ती
क्वालिटी में सर्वोत्तम

मजबूती हमारी सुरक्षा आपकी.....

AL अलीगढ़ लॉक्स TM प्रा.लि.

पीरमुहानी,जगत जननी माता मन्दिर के नजदीक, पटना-3
फोन : 0612-3293208, 6500301, Email : aligarhlocks@gmail.com
अपने क्षेत्र बिहार का प्रथम एवं एकमात्र TM प्रतिष्ठान नक्कालों से सावधान
कृपया हमारे इस नाम से मिलते-जुलते प्रतिष्ठान को देख भ्रमित न हों।

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

06 अप्रैल –12 अप्रैल 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड

प्रकृति और सरकार दोनों ने किया तबाह

खुदकुशी की भेंट चढ़ा किसान वर्ष

“बेमौसम बारिश और ओलों ने किसानों की जिंदगी तबाह कर दी है. बुंदेलखंड के जिलों में तो हजारों गांव ऐसे हैं जहां खेतों में कुछ बचा ही नहीं है. किसान सदमे में हैं और प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में किसानों की मौतें लगातार हो रही हैं. सरकार ने राहत के बतौर महज दो सौ करोड़ रुपये देने की घोषणा तो कर दी, लेकिन किसानों तक वह राहत पहुंचाने में भी नौकरशाही आड़े आ रही है. अफसर सरकार को गुमराह कर रहे हैं.”

प्रभात रंजन दीन

हाथरस में किसान ने आग लगाकर आत्महत्या की, बांदा में दो किसान भाइयों ने आत्मदाह कर लिया, जालौन में किसान ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली... इस तरह की खबरों के साथ ही आज कल सुबह की शुरुआत होती है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय रेडियो पर भूमि अधिग्रहण के बारे में किसानों को अपने मन की बात समझा रहे थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहे थे, उस समय प्रदेश के किसान आत्महत्या कर रहे थे. खबर लिखे जाने तक उत्तर प्रदेश के 65 किसान अपनी जान दे चुके थे. खबर प्रकाशित होने तक यह संख्या और बढ़ चुकी होगी, ऐसी ही आशंका है. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह वर्ष किसान-वर्ष के रूप में घोषित है. बेमौसम बारिश या प्राकृतिक आपदा तो नेताओं के लिए एक बहाना है, क्योंकि जिस देश में लाखों किसान गलत कृषि नीति, जबरन भूमि अधिग्रहण, फसलों की लागत का मूल्य नहीं मिल पाने, शासन-प्रशासन और बैंकों द्वारा प्रताड़ित किए जाने के कारण आत्महत्या कर रहे हों, वहां बारिश तो एक बहाना ही है.

किसानों की दुखद मौतों का सियासी सच यह भी है कि 20 मार्च को विधानसभा में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के आत्महत्या करने की बात को ही नकार दिया था. सरकार ने 25 किसानों की मौत को स्वीकार किया था, आत्महत्या को नहीं. सरकार के उच्च स्तरीय नुमाइंदे किसानों की मौतों को उनकी बीमारी या घरेलू कलह बताने की नीच हरकतों में मुब्तिला हैं. सरकार ने आधिकारिक तौर पर माना है कि बेमौसम बारिश और ओले से एक हजार करोड़ का नुकसान हुआ है. जनवरी से मार्च के तीन महीनों में हुआ इतना बड़ा नुकसान तकरीबन दो दशकों में कभी नहीं हुआ. सरकार ने विधानसभा में बताया कि नुकसान की जानकारी केंद्र सरकार को भेजी गई है और 500 करोड़ रुपये की तत्काल सहायता मांगी है. जबकि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री डॉ. संजीव बालियान ने कहा कि यूपी सरकार ने प्रारंभिक तौर पर बारिश और ओलावृष्टि से 26 जिलों में फसलों को 50 फीसदी से ज्यादा क्षति बताई. बालियान ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसानों की मदद के लिए आपदा राहत कोष से जो 200 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है, उसमें 75 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार का है. ध्यान दें कि अभी दो सौ करोड़ रुपये स्वीकृत ही हुए हैं. किसानों तक राहत पहुंचाने की सरकार की जो गति है, उसे देखते हुए यह हो सकता है कि अगली आपदा तक भी राहत राशि पीड़ित किसान परिवारों तक न पहुंच पाए.

बेमौसम बारिश और ओलों ने किसानों की जिंदगी तबाह कर दी है. बुंदेलखंड के जिलों में तो हजारों गांव ऐसे हैं जहां खेतों में कुछ बचा ही नहीं है. किसान सदमे में हैं और प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में किसानों की मौतें लगातार हो रही हैं. सरकार ने राहत के बतौर महज दो सौ करोड़ रुपये देने की घोषणा तो कर दी, लेकिन किसानों तक वह राहत पहुंचाने में भी नौकरशाही आड़े आ रही है. अफसर सरकार को गुमराह कर रहे हैं. न तो सही तरीके से मौका मुआयना किया जा रहा है और न ही मुआवजा राशि का समुचित आंकलन किया जा रहा है. मुआवजे में भी सिफारिशें चल रही हैं. जिनकी कोई पहुंच नहीं है, वह ठगे और मरे जा रहे हैं. कुछ लोगों ने इसकी शिकायत सरकार तक पहुंचाई, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही. कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता प्रदीप माथुर ने कहा कि सरकार भले ही अपनी पीठ थपथपा रही हो, पर जमीनी हकीकत यही है कि पीड़ित किसान परिवारों को मदद नहीं मिल रही है. शासन-प्रशासन की पूरी ऊर्जा इसी कोशिश में लगी है कि फसलों की बर्बादी के कारण किसानों की मौत से इन्कार किया जाए और उनकी मौतों को बीमारी, घरेलू कलह और बढ़ते हुए कर्ज को जिम्मेदार बताया जाए. कई मामलों में तो अधिकारियों ने मौतों को स्वाभाविक बताकर मुआवजा देने से भी इन्कार कर दिया है. राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान और महासचिव अनिल दुबे ने भी कहा कि फसलों के नुकसान से किसानों की मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार मुआवजा देना तो दूर उनकी सुध भी नहीं ले रही है. सरकार किसानों का बिजली बिल माफ नहीं कर रही है और न ही फसल क्षतिपूर्ति के लिए पर्याप्त धन मुहैया करा रही है. प्रदेश सरकार के किसान विरोधी आचरण के कारण किसानों में घोर हताशा और निराशा व्याप्त है. रालोद नेताओं ने फसल की बर्बादी का आकलन कराकर किसानों को उचित मुआवजा देने, मरने वाले किसानों के परिजनों को तत्काल मुआवजा राशि देने, प्रभावित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने, प्रभावित क्षेत्रों के किसानों का छह माह का बिजली बिल माफ करने, वर्तमान फसल के कृषि ऋण से सम्बन्धित सभी कर्जे माफ करने, केंद्र सरकार द्वारा घोषित गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रदेश सरकार की तरफ से 500 रुपये प्रति कुन्तल बोनस देने, किसानों का पिछला व वर्तमान सत्र का गन्ना मूल्य तत्काल भुगतान कराने और जायद की फसल के लिए बीज और खाद पर अनुदान देने की मांग की है.

किसानों की मौत तो हर बार होती है, इस बार बेमौसम बारिश के सिर पर ठीकरा फूटा है. उत्तर प्रदेश में किसानों की मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. अभी 22 मार्च को ही बुंदेलखंड में फसल की बर्बादी के चलते पांच और अलीगढ़ में एक किसान की मौत हो गई. मरने वालों में जालौन के तीन, बांदा और महोबा के एक-एक किसान शामिल हैं. जालौन में एक किसान ने जहर खाकर जान दे दी. कुछ अन्य किसानों की सदमे से मौत हुई. फसलों की बर्बादी के कारण उत्तर प्रदेश में मरने वाले किसानों की संख्या अब 65 के पार चली गई है. जालौन में डकोर ब्लॉक के काबिलपुर गांव के रहने वाले किसान रामबिहारी ने दो एकड़ जमीन पर मटर बोई थी. पिछले दिनों बारिश और ओले से उनकी अधिकांश फसल का नुकसान हो गया. परेशान रामबिहारी ने जहरीला पदार्थ खा कर जान दे दी. उनकी उम्र 48 साल थी. रामबिहारी पर बैंक और साहुकारों का 15 लाख रुपये का कर्ज भी था. यहीं के चुर्खी थाना क्षेत्र के गांव खाखरी निवासी 50 साल के महावीर सिंह की 12 बीघा फसल बर्बाद हो गई. वे फसल देख कर खेत पर ही अचेत हो गए और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई. जालौन में ही माधोगढ़ तहसील के कस्बा जगम्मनपुर के 55 वर्षीय भगवान शंकर चौरसिया के सात बीघा खेत में मसूर व मटर की फसल खराब हो गई, उनकी भी सदमे से मौत हो गई.

(शेष पृष्ठ 18 पर)

सरकारी ढिंढोरों में किसानों की मौत का कोई जिक्र नहीं

अतिवृष्टि व ओलावृष्टि से हुई क्षति से किसानों को राहत के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से 200 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जाने का ढिंढोरा तो प्रदेश सरकार लगातार पीट रही है, लेकिन किसानों की मौत के मामले में कुछ नहीं बोल रही. सरकार ने 30 जिलों में किसानों की फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए आकस्मिकता निधि से 200 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत किए जाने का खूब प्रचार किया है. प्रभावित जिलों में आगरा, फतेहपुर, जालौन, सोनभद्र, कानपुर नगर, अमेठी, चित्रकूट, ललितपुर, इटावा, हमीरपुर, बांदा, पीलीभीत, उन्नाव, महोबा, कन्नौज, मिर्जापुर, इलाहाबाद, सहारनपुर, बदायूं, आजमगढ़, झांसी, फिरोजाबाद, लखीमपुर खीरी, मुजफरनगर, औरैया, प्रतापगढ़, फैजाबाद, मुरादाबाद, कानपुर देहात और बिजनौर शामिल किए गए हैं. दो सौ करोड़ को बड़ी धनराशि बताते सरकार थक नहीं रही है. सरकार ने राज्य आपदा मोचक निधि से कृपापूर्वक 44 करोड़ रुपये की बड़ी धनराशि अलग से प्रदान की है. केंद्र से पांच सौ करोड़ रुपये मांगे गए हैं, लेकिन केंद्र को अब तक पूरी रिपोर्ट नहीं भेजी गई है. दो सौ करोड़ रुपये की आपदा राहत राशि की स्वीकृति का बखान कर रही उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आत्महत्याओं और मौतों पर मौन है. ■

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

भाजपा का चिंतन

डॉ. दिलीप अग्निहोत्री

उत्तर प्रदेश भाजपा की चित्रकूट में पिछले दिनों चिंतन बैठक समाप्त हुई. पार्टी ने समय रहते और सटीक समय पर चिंतन का कार्य सम्पन्न किया. प्रदेश में दो वर्ष बाद विधानसभा चुनाव होने हैं. समय का सदुपयोग करना संगठन की जिम्मेदारी है और समय की मांग भी है. बैठक में हुए निर्णयों पर क्रियान्वयन किया जा सका तो पार्टी की स्थिति में सुधार होगा. गोपनीय बैठक के बाद उत्तर प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि विधानसभा में जीत हासिल करने का रोडमैप बना लिया गया है. अब उस पर अमल होगा. इसके अलावा पार्टी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी दमखम के साथ हिस्सा लेगी. यह विधानसभा चुनाव का रिहर्सल होगा. विधानसभा में जीत का रोड मैप क्या होगा, इसका खाका फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया गया है. लेकिन इसमें संदेह नहीं प्रदेश भाजपा की चिंतन बैठक वस्तुतः कुछ समय में उभरी चिन्ताओं से प्रेरित थी. यदि सब कुछ पार्टी नेताओं की आशाओं के अनुरूप होता, तो चिंतन बैठक की उतनी आवश्यकता नहीं भी रहती.

लोकसभा चुनाव के बाद तो प्रदेश भाजपा में गजब का उत्साह था. प्रदेश का संगठन तो इस सफलता की कल्पना तक नहीं कर सकता था. लोकसभा चुनाव की सफलता नरेन्द्र मोदी के करिश्मे, तत्कालीन प्रभारी अमित शाह और कई वरिष्ठ नेताओं के जमीनी प्रबन्धन के चलते मिली थी. इसके बाद प्रदेश भाजपा को विश्वास था कि इस लहर के चलते वह विधानसभा चुनाव में भी शानदार सफलता प्राप्त करेगी. लोकसभा चुनाव में भाजपा लगभग तीन सौ सीटों पर आगे थी. लेकिन यह उत्साह अधिक समय तक कायम नहीं रह सका. विधानसभा के उपचुनाव तथा छावनी परिषद के चुनाव प्रदेश संगठन ने अपने दम पर लड़े थे. लेकिन इसमें बड़ी निराशा मिली. यह सही है कि इन सीमित चुनावों से भविष्य के बड़े निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते, लेकिन इसका संदेश पूरे प्रदेश में तो गया ही. लोकसभा चुनाव के बाद जितने घटनाक्रम हुए, उन्हीं में चिंतन के तत्व समाहित हैं. कई जगह लोकसभा सदस्यों ने ही पार्टी के घोषित उम्मीदवारों का सहयोग नहीं किया था. ये बातें बिना किसी चिंतन के साफ थी. इन्हीं पर सुधार की आवश्यकता थी. एक तो अनावश्यक मुद्दों से बचा जाए. सबका साथ, सबका विकास की नीति पर अमल जारी रखा जाए. इसके अलावा पार्टी के नेता आपसी मतभेद भुलाकर कार्य करें. वैसे दिल्ली के चुनाव ने भी प्रदेश संगठन को काफी परेशान किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरगामी रणनीति पर अमल कर रहे हैं. उनकी सरकार जिस प्रकार की आर्थिक नीतियां बना रही हैं, उनके परिणाम देखने के लिये इंतजार करना होगा. इसमें संदेह नहीं कि आर्थिक नीतियों के बेहतर परिणाम मिलेंगे. लेकिन इसमें समय लगेगा. ऐसे में प्रदेश संगठनों को अपनी सक्रियता बढ़ानी होगी. जहां भाजपा विपक्ष में है वहां विकास को ही मुख्य मुद्दा बनाना होगा. बिजली, पानी, सड़क, कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार, किसानों की समस्याएं आदि पर जुझारू संघर्ष करना होगा. यदि इन्हीं मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाए तो फिर किसी अन्य मसले की आवश्यकता नहीं होगी. लव जिहाद, धर्मांतरण, घर वापसी जैसे मुद्दों ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है. सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में ही इन मुद्दों को तूल मिला. विधानसभा उपचुनाव लव जिहाद के मुद्दे पर लड़ने का फैसला बहुत गलत था. इस प्रकार के मुद्दों ने उत्तर प्रदेश ही नहीं, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, दिल्ली सब जगह पार्टी का नुकसान किया. इस प्रकार का बयान देने वाले नेता खुद को चर्चित रखना चाहते हैं. वे यह कार्य पार्टी हित और पार्टी की साख की कीमत पर करते हैं. ऐसे में इन नेताओं पर लगाम कसने की आवश्यकता है. यदि इसके बाद भी वे नहीं मानते तो इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना जाना चाहिए. पार्टी की घोषित नीति पर सभी लोग अमल करें तो मतभेद की गुंजाइश नहीं रहेगी.

भाजपा के लोकसभा सदस्यों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए. लोकसभा सदस्य हों, या अन्य वरिष्ठ नेता, किसी को यह गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि वह अपनी लोकप्रियता से विजयी हुए हैं. सभी को मोदी-मोदी रटने से ही जीत नसीब हुई है. अन्यथा लम्बे समय से पार्टी का ग्राफ लगातार उतार पर था. प्रदेश से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के नेता भी गिरते ग्राफ को रोकने में विफल रहे थे. इस अवधि में पार्टी को लगातार निराशा मिली थी. विनय कटियार, रमापति राम त्रिपाठी, केशरीनाथ त्रिपाठी, ओमप्रकाश सिंह, सूर्य प्रताप शाही अपना ही चुनाव नहीं जीत सके थे. कल्याण सिंह से केशरीनाथ तक रहे प्रदेश अध्यक्ष ... जबकि विनय कटियार, ओमप्रकाश सिंह, सूर्य प्रताप शाही जैसे पूर्व अध्यक्ष अब जनाधार का दावा नहीं कर सकते. नितिन गडकरी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब दो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजनाथ सिंह व कलराज मिश्र ने दो अलग-अलग स्थानों से जन सम्पर्क यात्राएं निकाली थीं लेकिन पार्टी का ग्राफ बढ़ाने में दोनों नाकाम रहे. आज आवश्यकता है कि जिसका जो दायित्व है, उसे वह निष्ठा के साथ अहंकार मुक्त होकर पूरा करे. वरिष्ठ राजनीतिक प्रेक्षकों का भी मानना है कि लोकसभा सदस्यों को जनता से सतत सम्पर्क में रहना चाहिए. कई सांसद अभी से दुर्लभ हो गये हैं. उनका अहंकार चर्चा में है. यह मानसिकता नहीं बदली गई तो पार्टी का भला नहीं होगा. प्रदेश संगठन को अपना दायित्व पूरा करना चाहिए. अन्य नेता सहयोग दें, तभी भाजपा सफल हो सकती है. भाजपा के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता का भी यही मानना है. ■

सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा

सरकार को करोड़ों का नुकसान

सूफी यायावर

उत्तर प्रदेश सरकार की अंदरूनी अराजकता का आधिकारिक पर्दाफाश हुआ है. महालेखाकार की रिपोर्ट कहती है कि शासन की अंदरूनी अराजकता के कारण सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ. कैग कहता है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार, चोरी और गबन बेतहाशा है. सरकारी विभागों की चोरी, गबन, दुर्विनियोग और सरकारी सामग्रियों की हानि के कारण राज्य सरकार को आठ करोड़ 91 लाख 23 हजार रुपये का नुकसान हुआ है. शासन की अराजकता का ही परिणाम है कि बजट की राशि खर्च किए बगैर अनुपूरक अनुदान ले लिया जाता है. महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में 142 ऐसे मामले उजागर किए हैं जिनमें चोरी और गबन हुए और सरकार को क्षति पहुंची. 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संदर्भ में भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में विभिन्न मदों में हुई यह क्षति उजागर की गयी है. चोरी के सर्वाधिक 33 मामले सिंचाई विभाग में उजागर हुए हैं. कैग ने सिंचाई विभाग में 15.84 लाख की चोरी पकड़ी. कृषि विभाग में 1.47 लाख, पशुपालन में 1.78 लाख, सहकारिता में 1.28 लाख, शिक्षा विभाग में 6.60 लाख, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में 11.91 लाख, लोक निर्माण में 1.63 लाख, ग्राम विकास में 1.38 लाख और बाट माप विभाग में 1.01 लाख की चोरी पकड़ी गई है. इस तरह कुल 65 चोरियां सामने आई हैं. दुर्विनियोग के 10 मामलों में सरकार को 64.89 लाख रुपये का चूना लगा. इसमें भी सर्वाधिक तीन मामले सिंचाई विभाग के हैं. सिंचाई विभाग को इससे 29.72 लाख की क्षति हुई. कृषि, शिक्षा, लोक निर्माण और प्राविधिक शिक्षा विभाग में दुर्विनियोग के कई मामले आए. कुल 24 मामलों में 171.74 लाख की क्षति सामने आई. महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में गबन के 43 मामले उजागर किए हैं. इस गबन में सरकार को छह करोड़ 11 लाख 70 हजार रुपये का नुकसान हुआ. सिंचाई विभाग में चोरी के 33 मामलों के अलावा कृषि विभाग में एक, पशुपालन में 11, सहकारिता में एक, शिक्षा विभाग में दो, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में आठ, लोक निर्माण में तीन, ग्राम विकास विभाग में पांच और बाट माप विभाग में चोरी का एक मामला पकड़ा गया. दूसरी तरफ शासनिक अराजकता का हाल यह है कि मूल बजट की राशि खर्च किए बगैर सरकार अनुपूरक अनुदान ले लेती है. उत्तर प्रदेश सरकार के इस रवैये पर भी कैग ने चिंता जताई है. विधान मंडल के सदनों में विपक्ष के इन आरोपों को सत्ता पक्ष नकार देता है लेकिन तथ्य यही कहता है. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सीएजी) के नवीनतम प्रतिवेदन से इस प्रवृत्ति की पुष्टि होती है. कैग ने पाया कि वर्ष 2013-14 में 46 मामलों में 3687.52 करोड़ रुपये का अनुपूरक अनुदान एकदम गैरजरूरी था क्योंकि मूल बजट की राशि ही खर्च नहीं की जा सकी थी. इस संबंध में सीएजी रिपोर्ट ने कई विभागों की हालत सामने रखी है. प्राथमिक शिक्षा विभाग अपने मूल बजट का 2337 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर सका लेकिन इसके लिए 230 करोड़ रुपये का अनुपूरक अनुदान ले लिया गया. समाज कल्याण विभाग (स्पेशल कम्पोनेंट प्लान) अपने मूल बजट का 595 करोड़ नहीं खर्च सका, इसके बावजूद इसे 720 करोड़ रुपये का अनुपूरक अनुदान दिया गया. गृह विभाग को 192 करोड़ रुपये का अनुपूरक अनुदान दिया गया जबकि यह मूल बजट का 790 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर सका. कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग को 112 करोड़ रुपये का पूरक अनुदान मिला जबकि इसका मूल बजट का 483 करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ. राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) अपने मूल बजट का 102 करोड़ रुपया नहीं खर्च कर सका लेकिन इसे 100 करोड़ रुपये का अनुपूरक अनुदान दिया गया. सिंचाई विभाग (निर्माण) को 544 करोड़ का अनुपूरक अनुदान मिला जबकि इसके पास मूल बजट का 194 करोड़ रुपया बचा रह गया. उच्च शिक्षा विभाग अपने मूल बजट का 344 करोड़, अल्पसंख्यक विभाग 184 करोड़, न्याय विभाग 216 करोड़, चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) 165 करोड़, व्यावसायिक शिक्षा विभाग 98 करोड़, हथकरघा उद्योग 56 करोड़, नगर विकास विभाग 67 करोड़, सचिवालय प्रशासन विभाग 54 करोड़ और चिकित्सा विभाग 71 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर सका, लेकिन इन सभी विभागों के लिए अनुपूरक अनुदान ले लिया गया.

मार्च आता है तो पैसा बहाया जाता है

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट में कुल पूंजीगत खर्चे की आधी धनराशि अकेले मार्च महीने में खर्च की. रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2013-14 में सरकार ने बजट में दर्शाये गए कुल पूंजीगत व्यय का 50.11 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 23.37 प्रतिशत मार्च में ही खर्च किया. इस तरह वित्तीय वर्ष के आखिरी महीने में कुल बजट की 24 फीसद धनराशि खर्च की गई. बजट में सड़कों व सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय का 47.25 प्रतिशत, विद्युत परियोजनाओं का 44 प्रतिशत, मुख्य सिंचाई का 23.79 प्रतिशत, शहरी विकास का 67.95 प्रतिशत, पर्यटन का 26.2 प्रतिशत मार्च में खर्च हुआ. रिपोर्ट में इसे वित्तीय प्रबंधन की गंभीर समस्या बताया गया.

सहायता अनुदान बांट दिए, पर दस्तावेज पूरे नहीं

सीएजी रिपोर्ट के अनुसार 2013-14 तक राज्य सरकार की ओर से सहायता अनुदान के तौर पर दिए गए 111348.81 करोड़ रुपये के उपभोग प्रमाणपत्र अप्राप्त थे. अप्राप्त उपभोग प्रमाणपत्रों की संख्या 436814 है. राज्य सरकार द्वारा खास मकसद के लिए खोले जाने वाले व्यक्तिगत डिपॉजिट खातों को बंद कर नियमानुसार उनमें बची धनराशि को सरकारी लेखे में वापस न करने के कारण ऐसे 1494 खातों में 5410 करोड़ रुपये की धनराशि अवरुद्ध हो गई है. कैग की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2005 से लेकर 2013 की अवधि में बजट आवंटन से अधिक खर्च की गई 17743.99 करोड़ रुपये की धनराशि का विनियमितीकरण नहीं कराया है.

वीआइपी दौरे पर खर्च कर दिए 1.36 करोड़

सैफई महोत्सव से लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में मुख्यमंत्री के दौरे में सुरक्षा और हेलीपैड तैयार करने में एक करोड़ 36 लाख 27 हजार 730 रुपये खर्च कर दिए गए. पुलिस मुख्यालय ने तीन मार्च को इन खर्चों के संदर्भ में शासन को प्रस्ताव भेजा था. गृह विभाग के विशेष सचिव सूर्य नारायण शुक्ल ने एडीजी पीएचक्यू को भेजे गए पत्र के जरिए बताया कि उक्त धनराशि के भुगतान के लिए स्वीकृति दे दी गई है. ■

प्रकृति और सरकार दोनों ने किया तबाह

खुदकुशी की भेंट चढ़ा किसान वर्ष

पृष्ठ 17 का शेष

महोबा के ग्राम ननौरा निवासी 58 साल के रामकिशुन ने साधन सहकारी समिति लुहेड़ी से 40 हजार रुपये और साहूकारों से चार लाख रुपये का कर्ज ले रखा था. अच्छी पैदावार की उन्हें उम्मीद थी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. खेत में ही वे मरे हुए पाए गए. बांदा में अतर्रा के अनथुवा गांव के किसान रामअवतार कुशवाहा ने दो वर्ष पूर्व बैंक की महोतरा शाखा से एक लाख 20 हजार रुपये कर्ज लिए थे. खेत से लौटते समय ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा. अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई. अलीगढ़ के छर्रा क्षेत्र में भी एक किसान की फसल खराब होने के सदमे से मौत हो गई. बांदा में एक किसान ने खुद को गोली मार ली. उरई में सदमे से मरने वाले किसानों की संख्या तीन है. बांदा के थाना बिसंडा क्षेत्र के सिकलोढ़ी गांव निवासी किसान रामनरेश उर्फ राजा बाबू द्विवेदी (35) ने राइफल से खुद को गोली मार ली. परिजन जिला अस्पताल लेकर आए जहां डाक्टरों ने राजा बाबू को मृत घोषित कर दिया. परिजनों ने बताया कि फसल खराब होने से राजा बाबू परेशान थे. बैंक से 80 हजार का कर्ज ले रखा था. बांदा में ही कर्ज लेकर बटाई के खेत पर बोई फसल नष्ट हो जाने से क्षुब्ध युवा किसान ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली. बचाने में बड़ा भाई भी बुरी तरह झुलस गया. दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आत्मदाह का प्रयास करने वाले किसान की हालत गंभीर है. मरने वाले किसानों की फेहरिस्त में जालौन के 12, उन्नाव के पांच, महोबा के पांच, हमीरपुर के चार, इटावा के चार, बांदा के तीन, फर्रुखाबाद के तीन, चित्रकूट के एक और कानपुर देहात के एक किसान शामिल हैं. इनके अलावा अलीगढ़ और हाथरस जिले में अब तक 23 किसानों की मौत हो चुकी है. इनमें अलीगढ़ के सात और हाथरस के 16 किसान शामिल हैं. अलीगढ़ में अतरौली, जट्टारी और हरदुआगंज क्षेत्रों में किसानों की मौतें हुई हैं. जसपुरा थाना क्षेत्र के नांदादेव निवासी सिद्धा (35) ने फसल चौपट जाने के कारण रविवार की सुबह खुद पर केरोसिन डालकर आत्महत्या का प्रयास किया. बड़ा भाई रामप्रसाद उसे बचाने के दौरान झुलस गया. दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. माधोगढ़ स्थित रामपुरा के जगम्मनपुर कस्बे में भगवानशंकर (55) सुबह खेत पर गए थे. खेत में ही वे मृत मिले. कुठौद ब्लॉक के आल गांव में सुघर बाबू (55) के पास तीन बीघा खेती थी. इलाहाबाद बैंक से उन्होंने एक लाख का कर्ज ले रखा था. फसल बर्बाद होने से सदमे के कारण उनकी मौत हो गई. मरने वाले किसानों में हमीरपुर के सरीला में दो तथा महोबा, जालौन, मऊरानीपुर तथा कानपुर देहात के सिकंदरा में एक-एक किसान शामिल हैं. राठ के कोटबाजार के किसान रफीक पुत्र कल्लू औड़ेरा रोड पर अपने खेत देखने गया था. फसल तबाह देख कर सदमे में रफीक की मौत हो गई.

फसलों की बर्बादी से आहत किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या, दिल का दौरा पड़ने व सदमे से हो रही मौतों और मुआवजे की बंदरबांट के संदर्भ में सामाजिक संस्था रिहाई मंच की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मांग पत्र भी भेजा गया है. 11 सूत्री सवालों और 14 सूत्री मांगों वाले इस पत्र के जरिए प्रदेश सरकार की मुआवजा नीति और किसानों की आत्महत्या के बाद प्रदेश सरकार की गैर जिम्मेदाराना कार्यशैली पर सवाल उठाया गया है. किसानों की मौत के आंकड़ों को कहीं अधिक बताते हुए रिहाई मंच ने तथ्यों को दबाने, गलत तथ्य प्रस्तुत करने और दायित्वों के निर्वहन में घनघोर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. मंच ने किसान आत्महत्या और सदमे के कारण हो रही किसानों की मौतों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समेत विभिन्न परिदृश्यों को समझने व इसके एक निश्चित हल के लिए जांच आयोग के गठन की भी मांग की है.

रिहाई मंच कार्यकारी समिति के सदस्य अनिल यादव, हरे राम मिश्र, मसीहुद्दीन संजरी और लक्ष्मण प्रसाद ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि एक तरफ यह वर्ष किसान वर्ष के रूप में घोषित है, दूसरी तरफ फसलों की बर्बादी व किसान आत्महत्या जैसे सवालों पर सरकार आपराधिक उपेक्षा बरत रही है. फसलों की बर्बादी के कारण किसानों पर खड़ी आपदा के समय उत्तर प्रदेश सरकार को किसानों के साथ खड़ा होकर उनके आर्थिक नुकसान की भरपाई करनी चाहिए थी, ऐसे वक्त में सरकार आंकड़ों के जरिए किसानों की मौतों को झुठलाने का प्रयास कर रही है.

अभी झेली थी सूखे की मार

उत्तर प्रदेश का किसान राजनीतिक और प्राकृतिक आपदाएं झेलने के लिए ही बना है. कभी अतिवृष्टि और बाढ़ तो कभी वृष्टिहीनता और सूखा. अभी पिछली गरमी में किसानों ने भीषण सूखे की मार झेली थी. प्रदेश के 44 जिले सूखाग्रस्त घोषित हुए थे. तब भी उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र से छह हजार करोड़ रुपये मांगे थे. प्रदेश सरकार की इस मांग पर केंद्र सरकार ने कहा था कि मांग भेजने में प्रदेश सरकार ने अत्यधिक विलम्ब कर दिया है. इस तरह उस बार भी राहत का मामला सियासत की पेंच में फंस गया था. केंद्र ने प्रदेश सरकार की लापरवाही उजागर करते हुए कहा था कि केंद्र ने कृषि विकास के लिए राज्य सरकार को जो 565 करोड़ रुपये का पैकेज दिया था. उसमें से वह मात्र 334 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाई. किसानों और आम नागरिकों के प्रति सरकारी उपेक्षा का हाल यह है कि मायावती की सरकार के समय में किसानों की मदद के लिए 50 रुपये से लेकर 80-90 रुपये तक के चेक दिए गए थे. ऐसे अनेक किसान थे जिन्होंने अपने चेक फाड़कर फेंक दिए थे. ■

नुकसान की भरपाई के लिए सरकार की तरफ से जारी 200 करोड़ रुपये का प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आकलन किया जाए तो पहले चरण की बारिश से पीड़ित किसानों में यह राशि 740 रुपये प्रति हेक्टेयर होगी. लेकिन अगर पूरे फसल बर्बादी वाले किसानों में इसे बांटा जाएगा तो यह 200-300 रुपये प्रति हेक्टेयर और छोटी जोत के किसानों तक पहुंचते-पहुंचते यह राशि 100-50 रुपये रह जाएगी. जबकि उत्पादन को आधार मानकर प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने की आवश्यकता थी.

रिहाई मंच कार्यकारी समिति के सदस्य अनिल यादव, हरे राम मिश्र, मसीहुद्दीन संजरी और लक्ष्मण प्रसाद ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि एक तरफ यह वर्ष किसान वर्ष के रूप में घोषित है, दूसरी तरफ फसलों की बर्बादी व किसान आत्महत्या जैसे सवालों पर सरकार आपराधिक उपेक्षा बरत रही है. फसलों की बर्बादी के कारण किसानों पर खड़ी आपदा के समय उत्तर प्रदेश सरकार को किसानों के साथ खड़ा होकर उनके आर्थिक नुकसान की भरपाई करनी चाहिए थी, ऐसे वक्त में सरकार आंकड़ों के जरिए किसानों की मौतों को झुठलाने का प्रयास कर रही है. प्रदेश सरकार अपनी जिम्मेदारी व जवाबदेही से बचने के लिए किसान आत्महत्या के सवाल पर झूठ बोलती रही कि किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की. जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसानों की असामयिक मृत्यु के शिकार किसानों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की, तब तक पचासों किसानों की मौत हो चुकी थी. मंच ने 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने, गेहूं के समर्थन मूल्य पर सात सौ रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देने, 50 प्रतिशत फसल बर्बाद होने पर ही मुआवजा देने के मानदंड को समाप्त कर किसान को ईकाई मानते हुए उसके फसल की बर्बादी का मूल्यांकन करने, नई मुआवजा नीति बनाने, फसल की बर्बादी के कारण आत्महत्या, दिल का दौरा पड़ने व सदमे से मरने वाले किसानों के परिवार को बीस लाख रुपये देने, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने, खेत-खेत के सर्वे से फसलों के नुकसान का आकलन करने, पीड़ितों के अल्पावधि ऋण समाप्त करने, निजी ऋणदाताओं के खिलाफ किसानों की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने, बटाईदार किसान को भूमि की गारंटी देने, एक माह के भीतर गन्ना किसानों के भुगतान की गारंटी करने, किसानों को एक साल के लिए बिजली बिल माफ करने की मांग की है. ■

कबीर की विरासत को बचाने की कवायद

चौथी दुनिया ब्यूरो

वाराणसी के कबीरचौरा मठ मूलगादी में महान संत कबीरदास की विरासत के संरक्षण की कोशिशें शुरू हो गई हैं. इसके लिए लखनऊ से पहुंचे राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला के दल ने काम शुरू कर दिया है. इसमें संत कबीर द्वारा उपयोग में ले आई गई काठ की हांडी पर चढ़ी गर्द साफ की जा रही है. उनसे जुड़ी अन्य वस्तुओं का भी मूल स्वरूप लौटाया जाएगा. उनके विचारों को सहेजने वाली पांडुलिपियों को भी संरक्षित करने की योजना है. सभी 700 पांडुलिपियों व दो पेंटिंग भी लखनऊ स्थित अनुसंधानशाला भेजी जाएंगी. संरक्षण के लिए आए दल में सीनियर टेक्निकल रिस्टोरर वीरेंद्र कुमार रसायनज्ञ और वरिष्ठ संरक्षण सहायक शिव बालक फाइन आर्ट विशेषज्ञ हैं. दोनों सदस्य कबीर के इस्तेमाल में आई काठ की हांडी व ताना बाना के लौह कील को मूल स्वरूप देने में जुट गए. इसके लिए हांडी पर थिनर लगाने के बाद विशेष प्रकार के औजार से खुरचा गया. शाम तक हांडी की लालिमा और ताना-बाना की कील की चमक लौटने लगी. रसायनज्ञ वीरेंद्र कुमार ने बताया कि अभी हांडी व कील को मूल रूप में आने में कुछ दिन लगेंगे. इसी प्रकार संत कबीर की खड़ाऊं व उनके त्रिशूल को भी सहेजा जाएगा.

कबीरचौरा मठ मूलगादी के मुख्य महंत संत विवेकदास आचार्य कहते हैं कि महलगादी के पास ही लहरतारा तालाब के किनारे मिले नवजात कबीर का नीरू नीमा ने मठ से सटे परिसर में लालन पालन किया था. मूल मठ परिसर कबीर की साधना स्थली थी. बाद के वर्षों में संत कबीर के मगहर गमन व ब्रह्मलीन होने के बाद उनके अनुयायियों ने मठ की स्थापना की. इसमें उनके द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं यथा, खड़ाऊं, हांडी, तानाबाना, किसी संत द्वारा हारा गया त्रिशूल व गुरु रामानंद से मिली माला (जो पिछले साल चोरी हो गई) को सहेज रखा था. वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण न होने से इनका मूल स्वरूप छिप गया था.

नीरू-नीमा टीला पर 4.66 करोड़ की लागत से म्यूजियम व ट्राइबल हट बनाई जा रही है. इसके लिए केंद्र सरकार के पास वर्षों से प्रस्ताव लंबित है. इसके लिए आचार्य विवेक दास ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को कई बार पत्र लिखा. इस क्रम में पहले संस्कृति सचिव मठ भी आए थे. उन्होंने कबीर द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं के साथ ही पांडुलिपि व नीरू नीमा टीला का निरीक्षण किया था. इन्हें वैज्ञानिक तरीके से सहेजने में मदद करने का भरोसा दिया था. उनके निर्देश पर ही सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला ने थाती संरक्षण की कवायद शुरू की है.

धार्मिक नगरी के रूप में विश्व प्रसिद्ध वाराणसी के कबीर मठ में रखी एक पत्थर की चक्की कबीर पंथियों के आकर्षण का केन्द्र है. अरब देश के बुखारा शहर में सुल्तान इब्राहीम ने कैदखाने में यह चक्की लगवायी थी जिसे उसके शासन में गिरफ्तार किए गये साधु संतों से चलवाया जाता था. सुल्तान इब्राहीम साधु संतों और फकीरों को अपने दरबार में बुलवाता था और उनसे अनेक प्रश्नों का समाधान पूछता था. साधु-संत जब उसकी शंकाओं और जिज्ञासा का समाधान नहीं कर पाते थे तो उन्हें कैदखाने में डालकर इस भारी चक्की को चलाने का दंड दिया जाता था. संत कबीरदास को पंजाब भ्रमण के दौरान उनके अनुयायियों ने बुखारा में संतों को दी जा रही यातना की जानकारी दी और उनसे इस बारे में कुछ करने को कहा. कबीरदास सच जानने के लिये बुखारा पहुंचे और वहां संतों और फकीरों को दी जा रही यातना देखकर बहुत दुखी हुए. कबीर ने उनसे कहा कि भगवत भजन कीजिए, जिसकी कृपा से यह चक्की अपने आप चलेगी और उन्होंने यह कह कर चक्की को छू दिया. उनके छूते ही चक्की चलने लगी और माना जाता है कि तबसे वह चक्की लगातार चल रही है. बाद में कबीर पंथ के पांचवें संत लाल साहब उस चक्की को भारत लाये और कबीर मठ में स्थापित किया. वह चक्की वाराणसी में दशकों से पर्यटकों को लुभा रही है.

वाराणसी के सिद्धपीठ कबीर चौरा मठ परिसर में संत कबीर ने अपनी कई साहित्य रचनाएं कीं. बीजक उनकी मूल रचना है और कबीर पंथ के संत और अनुयायी बीजक को ही अपना धर्मग्रंथ मानते हैं. कबीरदास के परिनिर्वाण के बाद बीजक की हस्तलिखित पांडुलिपि को मंदिर के स्मृति कक्ष में उनकी जर्जर खड़ाऊं और उनके इस्तेमाल किए लकड़ी के बर्तन के साथ ही रखा गया है. वहां एक हजार से अधिक लकड़ी की मणिकाओं वाली एक माला भी है जो स्वामी रामानन्द ने संत कबीर को दी थी. वही माला चोरी चली गई.

कबीरचौरा मठ मूलगादी के मुख्य महंत संत विवेकदास आचार्य कहते हैं कि महलगादी के पास ही लहरतारा तालाब के किनारे मिले नवजात कबीर का नीरू नीमा ने मठ से सटे परिसर में लालन पालन किया था. मूल मठ परिसर कबीर की साधना स्थली थी. बाद के वर्षों में संत कबीर के मगहर गमन व ब्रह्मलीन होने के बाद उनके अनुयायियों ने मठ की स्थापना की. इसमें उनके द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं यथा, खड़ाऊं, हांडी, तानाबाना, किसी संत द्वारा हारा गया त्रिशूल व गुरु रामानंद से मिली माला (जो पिछले साल चोरी हो गई) को सहेज रखा था.

मठ में कबीर साहित्य और संत साहित्य का एक समृद्ध पुस्तकालय भी है. करीब सात सौ पांडुलिपियां भी पुस्तकालय में रखी गई हैं. कबीर चौरा मठ स्वतंत्रता आंदोलन के समय क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र था. अंग्रेज गवर्नरों ने नाराज होकर तीन-तीन बार मठ को तोड़कर अस्पताल में मिला देने का आदेश दिया. मठ में मौजूद कबीर के जीवन दर्शन पर आधारित मूर्तियां और तैल चित्र भी आकर्षण का केंद्र हैं.

वाराणसी के कबीर चौरा मठ से 30 नवंबर को करीब छह सौ साल पुरानी संत कबीर की ऐतिहासिक माला चोरी हो गई थी. इस घटना के करीब छह महीने पहले कोलकाता के बेल्लूर मठ से रामकृष्ण परमहंस की माला भी इसी तरह चोरी हुई थी. कोलकाता पुलिस की डिटेक्टिव यूनिट चोरों की तलाश में थी. कोलकाता और वाराणसी पुलिस से मिली खुफिया सूचना के बाद क्राइम ब्रांच गोरखपुर की टीम भी लामा की शक्ल में माला चुराने वाले थाई नागरिकों की तलाश में लगी थी. इस मामले में चार थाई नागरिकों को कुशीनगर मार्ग पर सोनबरसा के पास से गिरफ्तार किया गया. पकड़े गए लोगों की पहचान थाईलैंड, नान्थाबुरी के श्रीचाईं, फ्रुक उर्फ बुनटीरानान, बैंकॉक कोलसुक के पट्टा रावत और यहीं के कीराती पाई के रूप में हुई. इन्होंने कोलकाता के बेल्लूर मठ से रामकृष्ण परमहंस की ऐतिहासिक माला और वाराणसी के कबीर चौरा मठ से संत कबीर की माला चोरी करने की बात कबूल की थी. कबीर चौरा की ऐतिहासिक माला की फोटो भी इनके पास से बरामद हुई थी. चोरों ने कोलकाता एयरपोर्ट पर पुलिस सख्ती के कारण निजी चौपहिया वाहन से सोनौली जाने और और वहां से नेपाल होते हुए वह थाईलैंड फरार होने की योजना स्वीकार की थी. कहते हैं कि कबीर चौरा स्थित कबीरमठ से चोरी संतकबीर की छह सौ साल पुरानी माला देश से बाहर जा चुकी है. पूजा के बहाने कबीरमठ से माला चुराने वाले थाई नागरिकों ने गया में पहले से मौजूद तीन थाई युवतियों को माला सौंप दी थी. पुलिस को चकमा देने के लिए वहां से कोलकाता चले गए. जब तक पुलिस माला चोरों के गिरेबान तक पहुंचती, युवतियां माला लेकर थाईलैंड के लिए उड़ान भर चुकी थीं. इन घटनाओं को देखते हुए ही मूलगादी के महंत संत विवेकदास आचार्य ने ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं और मठ के संरक्षण के तकनीकी इंतजामात शुरू कर दिए हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

महाराजगंज नगरपालिका में भ्रष्टाचार का बोलबाला

शत्रुंजय सिंह रैकवार

महाराजगंज नगरपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार में नेता नौकरशाह और इंजीनियर की तिकड़ी चर्चा में है. नगर पालिका इंजीनियर योगेश तिवारी और अधिशासी अधिकारी पशुपतिनाथ गुप्ता द्वारा सरकारी धन का अपव्यय किया जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन जांच के नाम पर मौन धारण किए है. इससे नगरवासियों में रोष है. सपा नेता विजय कश्यप व लोहिया वाहिनी के नेता सुग्रीव यादव ने शासन को पत्र लिखकर भ्रष्ट इंजीनियरों को निलम्बित करने की मांग की है ताकि सरकारी धन का बेजा इस्तेमाल रुक सके.

नगर पालिका परिषद महराजगंज की कथनी करनी में बड़ा फर्क है. ईमानदारी का तो हाल यह है कि बनी हुई सड़क का टेंडर निकाल कर रकम हड़प ली जाती है. नगर पालिका कर्मी अब इस जुगाड़ में हैं कि घपले से कैसे बचा जाए. महराजगंज नगर पालिका परिषद ने शासन से मिले लगभग दो करोड़ रुपये हड़प लिए और जो रोड पहले से बनी थी उसी का टेंडर निकाल दिया. इस कारनामे से पर्दा उठा तो हाय तौबा मच गयी. अब यही इनके गले की फांस बन गई है. टेंडर में गड़बड़ी कर सरकारी धन गटकने के खेल में शामिल लोग प्रशासन को भी उलझा रहे हैं. जांच पड़ताल तो चल ही रही है, लेकिन उसकी गति मंथर है. जांच अधिकारी एसडीएम सदर जितेन्द्र कुशवाहा का कहना है कि जांच रिपोर्ट एक माह पहले ही जिलाधिकारी महराजगंज को सौंपी जा चुकी है. वे फिर कहते हैं कि कुछ मामले बाकी हैं जिसकी जांच चल रही है. महराजगंज के जिलाधिकारी सुनील कुमार श्रीवास्तव कहते हैं कि मामले की पूरी जानकारी कर कार्रवाई करूंगा. जांच अधिकारी जितेंद्र कुशवाहा की जो जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी गई, उस पर क्या हुआ. यह सवाल अनुत्तरित ही है.

नगर पालिका परिषद महराजगंज की ओर से वार्ड नम्बर 14 लोहिया नगर में कोतवाली से श्रीराम के घर तक इंटरलॉकिग रोड निर्माण के लिए सात फरवरी को टेंडर निकाला गया था. जिस सड़क का टेंडर निकाला गया उसका निर्माण रिवॉल्विग फंड से पहले ही हो चुका है. नगर पालिका के टेंडर में गड़बड़ी की पोल खुली तो कोतवाली परिसर में 100 मीटर कच्चे मार्ग के इंटरलॉकिंग पर 11.52 लाख रुपये खर्च किए जाने की बात कही जाने लगी. इस मुददे को लेकर पूर्व सभासद लोहिया नगर योगेन्द्र मणि ने आवाज बुलंद की तो जांच पड़ताल शुरू हुई. बीते 15 फरवरी को एसडीएम सदर जितेन्द्र कुशवाहा ने मौके पर जांच पड़ताल की. जांच में उक्त सड़क पहले से ही इंटरलॉक युक्त पायी गयी. एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रेषित कर दी. इस धांधली में ईओ और अवर अभियन्ता के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन कार्रवाई हो नहीं रही. नगर पालिका के इस कारनामे पर अपर पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र नाथ ने कहा कि नगर पालिका कोतवाली कैम्पस के अन्दर सौंदर्यीकरण व इंटरलॉकिंग कराने पर क्यों आमादा है यह समझ से परे है. कोतवाली की जमीन पर पुलिस को अधिकार है. इस मामले में कुछ और कहना मुनासिब नहीं है. वहीं, एसडीएम सदर जितेन्द्र कुशवाहा कहते हैं कि पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल की गयी है. जिस सड़क की निविदा निकाली गयी है वह सड़क तो ठीक-ठाक मिली है, लेकिन कुछ और जरूरी तथ्यों की जांच पड़ताल की जा रही है. नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी पृथ्वीनाथ गुप्ता का कहना है कि सड़क के लिए पुलिस से एनओसी नहीं ली गयी, लेकिन कोतवाल से मौखिक वार्ता हुई थी. कोतवाली परिसर के अन्दर इंटरलॉकिंग हो जाएगा तो पुलिस आगे बाउन्ड्री नहीं करा पाएगी. जो तथ्य सामने आये हैं उसका समुचित जवाब दे दिया जायेगा. सब कुछ कायदे कानून के मुताबिक हुआ है. कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है. ■

हरीश सरकार की अग्निपरीक्षा

राजकुमार शर्मा

चारधाम यात्रा राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत के लिए एक बार फिर अग्नि-परीक्षा है. 2013-14 में हिमालयी में आई तबाही ने हरीश के धुर विरोधी पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को भी कुर्सी हटा दिया. केदारघाटी की तबाही के लिए मीडिया से लेकर हरीश रावत तक ने विजय बहुगुणा की नाकामी को कसूरवार ठहराया. एक सच यह भी सामने आया कि सूबे की सरकार सजग होती तो केदारघाटी में तबाही आने के बाद जो सैकड़ों लोग बच कर जंगलों में पहाड़ों की चोटीयों पर पहुंचे भूख-प्यास से तड़प कर अपनी जिंदगी नहीं गवांते. विजय बहुगुणा सरकार की असफलता को उजागर करने के लिए हरीश ने केदारघाटी की पैदल यात्रा की. तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री के रूप में हरीश रावत की इस यात्रा ने बहुगुणा को एक खलनायक के रूप में पेश किया और हरीश ने उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इस सच्चाई से भी इन्कार नहीं किया जा सकता की जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रूपये फूकने के बावजूद भी शीतकालीन यात्रा ढ़ाक के तीन पात सिद्ध हुई. सीधे शब्दों में कहा जाए की पुरी की पुरी यात्रा असफल सिद्ध हुई. इन सब के बहाने मुख्यमंत्री के प्रयास से नीम के सदस्यों ने शीतकाल में केदारधाम में तिरंगा फहराने में सफलता का एक नया इतिहास रचा. हरीश इस सरकारी खर्चे से पुरी तरह चर्चा में बने रहे. पूरे उत्तराखंड में हरीश अपने विपक्षी दल एवं भाजपा के चारधाम यात्रा के बहाने निशाने पर हैं. भारतीय जनता पार्टी उनके द्वारा आपदा में बांटे गए धन की सीबीआई जांच की माग के साथ उनको कठघरे में खड़ा करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है. चारधाम यात्रा शुरू होने में कुछ ही समय बचा है, लेकिन सरकारी अमला तैयारी के नाम पर अब तक फिसड्डी दिख रहा है. राज्य के मुख्यमंत्री इस चारधाम यात्रा के बहाने अपनी होने वाली अग्निपरीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं. केदारनाथ धाम की यात्रा के बाद सत्ता संभालने वाले मुख्यमंत्री हरीश का मानना है कि बाबा की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं खटकता फिर सफलता तो मिलनी ही है. सूबे के मुख्यमंत्री के लिए चारधाम यात्रा काटों के ताज से कम नही है.

20 अप्रैल को शीतकालीन मठ मुखबा से दोपहर डेढ़ बजे मां गंगा की डोली गंगोत्री के लिए रवाना होगी, जो रात को भैरोंघाटी स्थित भैरव मंदिर में रहेगी और 21 को सुबह गंगोत्री पहुंचेगी. चौत्र नवरात्र के पहले दिन गंगोत्री मंदिर समिति की बैठक में शुभ मुहूर्त तय किया गया. मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने बताया कि गंगोत्री मंदिर के कपाट 21 अप्रैल को 12 बजकर 30 मिनट पर कर्क लग्न में खोले जाएंगे. यमुनोत्री मंदिर समिति के सचिव मनमोहन उनियाल ने बताया कि यमुनोत्री मंदिर के कपाट 21 अप्रैल को खुलेंगे. यमुना की डोली 21 अप्रैल सुबह शीतकालीन मठ खरसाली गांव से यमुनोत्री के लिए रवाना होगी. गंगोत्री मंदिर समिति की बैठक में अध्यक्ष भागेश्वर सेमवाल, पूर्व अध्यक्ष संजीव सेमवाल, हिमाचल सेमवाल, रजनीकांत आदि मौजूद रहे.

कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने हरीश रावत को केदारनाथ धाम की तैयारी सहित चारधाम यात्रा की सफलता के लिए जनता को बेहतर सुविधा प्रदान करने की हिदायत दी है. श्रीमती गांधी का मानना है कि सरकार होस्ट के रूप में दिखे. उनका मानना है कि उत्तराखंड आने वाले हर तीर्थ यात्री को अतिथि देवों भवः की भावना से बेहतर सेवा प्रदान की जाए. कांग्रेस सेवा के माध्यम से एक अच्छी सरकार का संदेश देना चाहती है. सोनिया की नसीहत मिलने के बाद हरीश पूरी तरह से तैयार हो गए हैं.

बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी(सीईओ)बीडी सिंह ने अन्य कर्मचारियों के साथ हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ तक यात्रा मार्ग और धाम का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि बद्रीनाथ धाम में आठ फीट बर्फ जमी हुई है. मंदिर को बर्फ से कोई नुकसान नहीं हुआ है, आसपास की धर्मशालाओं और निजी भवनों को क्षति पहुंची है. कई भवनों की टिन की छत अलकनंदा नदी में पड़ी हुई हैं. इस बार तीर्थयात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को हनुमान चट्टी से ही हिमखंडों के दर्शन होंगे. बद्रीनाथ में पैदल पुल और बामणी गांव को जाने वाला रास्ता बर्फ में ढका हुआ है. बारिश-बर्फबारी से बचाव के लिए बने टिन शेड भी हिमखंडों के नीचे दबे हैं. माणा गांव भी बर्फ से आच्छादित है. आगामी नौ अप्रैल को समिति के कर्मचारियों का दल बद्रीनाथ पहुंचकर बर्फ हटाने के साथ ही यात्रा तैयारियों में जुट जाएगा.

उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने में कुछ ही दिन रह गया है, सड़कों का हाल जस का तस है. गोपेश्वर-चोपता मोटर मार्ग अभी तक भी चार धाम यात्रा के लिए तैयार नहीं हो पाया है. मार्ग कई जगहों पर इतनी क्षतिग्रस्त हैं कि कभी भी कोई दुर्घटना मार्ग कई जगहों पर जानलेवा बना हुआ है. केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों की तीर्थयात्रा इसी मार्ग से होकर गुजरती है, जिला प्रशासन की यात्रा तैयारियों को लेकर हुई कई दौर की बैठकों में इस सड़क के सुधारीकरण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है. मंडल, गंगोलगांव, सगर, ग्वाड़, देवलधार, कांचुलखर्च और चोपता में सड़क जानलेवा बनी हुई है. ग्वाड़ में सड़क पर पिछले छह माह से निर्माणाधीन कार्य अभी तक भी आधा-अधूरा निर्मित है. यहां पर छोटे वाहनों की आवाजाही भी मुश्किल से हो पा रही है. क्षेत्र पंचायत सदस्य देवेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह राणा, कुंवर सिंह और सत्येंद्र रावत का कहना है कि कई बार जिला प्रशासन से सड़क सुधारीकरण की मांग उठाई गई, प्रशासन का फोकस सिर्फ मुख्यमंत्री की नज़रों में आने के लिए बद्रीनाथ हाईवे को चाक-चौबंध बनाने में लगा हुआ है. जिलाप्रषासन का कहना है कि चमोली-गोपेश्वर-चोपता मोटर मार्ग के सुधारीकरण के लिए एडीबी आपदा विंग के अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं. अधिकारियों ने मोटर मार्ग पर जमी बर्फ के पिघलने के बाद ही सुधारीकरण कार्य शुरू करने की बात कही है.

आगामी 26 अप्रैल को भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलने जा रहा है. इस बार हुए भारी हिमपात के कारण मंदिर समिति ने भी कपाटोद्घाटन से पूर्व सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए अग्रिम दल को भी बीस दिन पहले बद्रीनाथ भेजने का फैसला किया है. ग्लेशियरों की स्थिति व धाम मे टूट-फूट का जायजा लेकर श्री बद्री-केदार मंदिर समिति के सीईओ बीडी सिंह अपने अधीनस्थ स्टाफ के साथ बदरीनाथ से लौटे सीईओ सिंह ने बताया कि हनुमान चट्टी से पैदल ही बद्रीनाथ पंहुचे. घोड़सिल चट्टान से बद्रीनाथ तक पूरा क्षेत्र बर्फ लगभग सात फुट बर्फ से पटा है और दर्जनों ग्लेशियर भी मार्ग में पड़े हैं. बीआरओ ने हनुमान चट्टी से बर्फ हटाने का कार्य शुरू कर दिया है. उन्होंने जानकारी दी कि बद्रीनाथ धाम मे बामणी गांव की ओर नारायणी नाले में ग्लेशियर आया है और इससे भारी टूट-फूट की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. इसके अलावा अभी भी बद्रीनाथ धाम के सभी भवन व मार्ग बर्फ से पटे हैं, इसलिए भी क्षति का अंदाजा नहीं लगाया जा सका. भारी बर्फबारी के कारण यात्रियों के लिए दर्शन की लाइन के लिए बनाए गए रैन सल्टर भी कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुए हैं. उनके अनुसार मंदिर परिसर, मंदिर गेस्ट हाइस आदि की साफ-सफाई व मरम्मत कार्य के लिए मंदिर समिति का अग्रिम दल आगामी 9 अप्रैल को जोशीमठ से प्रस्थान करेगा. उनका कहना था कि बद्रीनाथ तक के पूरे मार्ग का सर्वेक्षण करने के उपरांत ही बद्रीनाथ तक मार्ग खोलने की निर्धारित तिथि तय की जा सकेगी. कुल मिलाकर अब तक लगातार बिगड़ते मौसम के मिजाज से मौसम वैज्ञानिक भी हैरत में हैं. हिमालय की ऊंची पहाड़िया हिमपात से लदलद हैं. भगवान के आगे सरकार की कोई व्यवस्था कहीं टिकती ही नहीं है फिर भी भगवान भरोसे सूबे के मुख्यमंत्री चारधाम यात्रा में कोई चूक नहीं करना चाहते. ■